रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 1977/अषाढ़ 4, 1899
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1977/ASADHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सूचना
NOTICE

निम्नलिखित भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी, 1977 तक प्रकाशित किए गए ।
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 28th February, 1977.

निर्गमन सं० Issue No.	संख्या तथा तिथि No. and Date	द्वारा जारी Issued by	विषय Subject
1	2	3	4
49	का०आ० 60(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1977	उद्योग मंत्रालय	सीमेन्ट नियंत्रण (पहला संशोधन) आदेश, 1977 ।
	S.O. 60(E), dated the 1st February, 1977.	Ministry of Industry	The Cement Control (First Amendment) Order, 1977.
50.	का०आ० 61(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	गृह मंत्रालय	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7-2-77 से छ: मास के लिए मणिपुर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 61(E), dated the 2nd February, 1977.	Ministry of Home Affairs	The duty of every person serving in Manipur for a period of six months w.e.f. 7-2-77 declared as active duty.
	का०आ० 62(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 10-2-77 से छ मास के लिए महाराष्ट्र में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 62(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Maharashtra for a period of six months w.e.f 10-2-77 declared as active duty.

1	2	3	4
	का०आ० 63(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	गृह मंत्रालय	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 13-2-77 से छः मास के लिए मध्य प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 63(E), dated the 2nd February, 1977.	Ministry of Home Affairs	The duty of every person serving in Madhya Pradesh for a period of six months w.e.f. 13-2-77 declared as active duty.
	का०आ० 64(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-2-77 से छ मास के लिए मैसूर में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 64(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Mysore for a period of six months w.e.f. 17-2-77 declared as active duty.
	का०आ० 65(अ), दिनांक 2 फरवरी 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-2-77 से छः मास के लिए आन्ध्र प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 65(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Andhra Pradesh for a period of six months w.e.f. 23-2-77 declared as active duty.
	का०आ० 66(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 28-2-77 से छः मास के लिए उत्तर प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 66(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Uttar Pradesh for a period of six months w.e.f. 28-2-77 declared as active duty.
	का०आ० 67(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-77 से छः मास के लिए हिमाचल प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 67(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Himachal Pradesh for a period of six months w.e.f. 22-3-77 declared as active duty.
	का०आ० 68(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-77 से छः मास के लिए उड़ीसा में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 68(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Orissa for a period of six months w.e.f. 22-3-77 declared as active duty.
	का०आ० 69(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-77 से छः मास के लिए गोआ, दमण और दीव में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 69(E), dated the 2nd February, 1977	Do.	The duty of every person serving in Goa, Daman and Diu for a period of six months w.e.f. 22-3-77 declared as active duty.
	का०आ० 70(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-77 से छः मास के लिए पांडिचेरी में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 70(E), dated the 2nd February, 1977	Do.	The duty of every person serving in Pondicherry for a period of six months w.e.f. 22-3-77 declared as active duty.
	का०आ० 71(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-77 से छः मास के लिए अरुणाचल प्रदेश में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 71(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Arunachal Pradesh for a period of six months w.e.f. 22-3-77 declared as active duty.
	का०आ० 72(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-3-77 से छ मास के लिए दादरा और नागर हवेली में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 72(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Dadra and Nagar Haveli for a period of six months w.e.f. 22-3-77 declared as active duty.
	का०आ० 73(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	—तदैव—	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-3-77 से छः मास के लिए तमिलनाडु में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 73(E), dated the 2nd February, 1977.	Do.	The duty of every person serving in Tamil Nadu for a period of six months w.e.f. 11-3-77 declared as active duty.

1	2	3	4
	का०आ० 74(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1977	गृह मंत्रालय	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-3-77 से छः मास के लिए सिक्किम में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 74(E), dated the 2nd February, 1977.	Ministry of Home Affairs	The duty of every person serving in Sikkim for a period of six months w.e.f. 11-3-77 declared as active duty.
	का०आ० 75(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	सरकारी आफीसर को आन्ध्र प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफीसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S.O. 75(E), dated the 3rd February, 1977.	Election Commission of India	Designation of the officer of Government as Returning Officer of the Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh.
	का०आ० 76(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	आन्ध्र प्रदेश के राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफीसर के कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करना ।
	S.O. 76(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Appointment of Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh.
	का०आ० 77(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	असम राज्य के लिए सरकारी आफिसर को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S.O. 77(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Designation of the officer of Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Assam.
	का०आ० 78(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट असम सरकार के प्रत्येक आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए नियुक्ति ।
	S.O. 78(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission hereby appoints each of the officers of Govt. of Assam as specified in Column 2 of the table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Assam.
	का०आ० 79(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार सरकार के परामर्श से बिहार राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर को पदाभिहित करना ।
	S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission designates Returning Officer and Asstt. Returning Officers in consultation with the Govt. of Bihar in respect of Parliamentary Constituencies in the State of Bihar.
	का०आ० 80(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग गुजरात सरकार के परामर्श से सरकारी आफिसरों के सामने गुजरात राज्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित ।
	S.O. 80(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission designates in consultation with the Govt. of Gujarat the officer of Govt. as Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Gujarat.
	का०आ० 81(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग गुजरात सरकार के आफिसरों में से प्रत्येक को ऐसे सरकारी आफिसर तथा आफिसरों के सामने गुजरात राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिए नियुक्ति ।
	S.O. 81(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission hereby appoints each of the officers of Govt. as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Gujarat.
	का०आ० 82(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग हरियाणा राज्य सरकार के परामर्श से सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर के सामने हरियाणा राज्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S.O. 82(E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission hereby designates, in consultation with the Govt. of Haryana, the Officer of Govt. as the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Haryana.

1	2	3	4
	का०आ० 83(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा सरकार के आफिसरों को हरियाणा राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर के सहायक के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 83(E), dated the 3rd February, 1977.	Election Commission o India	Election Commission appoints the Officers of Government of Haryana to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Haryana.
	का०आ० 84(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से सरकारी आफिसरो को हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रो के रिटर्निंग आफिसर के रूप मे पदाभिहित करना ।
	S.O. 84(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, the Officer of the Government, as Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Himachal Pradesh.
	का०आ० 85(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आफिसरो को हिमाचल प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रो के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप मे नियुक्ति ।
	S.O. 85(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission appoints the Officers of Government of Himachal Pradesh to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Himachal Pradesh.
	का०आ० 86(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को जम्मू-कश्मीर राज्य मे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S.O. 86(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir, designates the Officer of the Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Jammu and Kashmir.
	का०आ० 87(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के आफिसर या आफिसरो को जम्मू-कश्मीर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप मे नियुक्ति ।
	S.O. 87(E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission appoints the Officer or Officers of the Government to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Jammu and Kashmir.
	का०आ० 88(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को कर्नाटक राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप मे पदाभिहित करना ।
	S.O. 88(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of Karnataka, the Officer of Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Karnataka.
	का०आ० 89(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा कर्नाटक सरकार के प्रत्येक आफिसर का कर्नाटक राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 89(E), dated the 3rd February, 1977	Do	Election Commission appoints each of the Government officers as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Karnataka.
	का०आ० 90(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, केरल सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को केरल राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप मे पदाभिहित करना ।
	S.O. 90(E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of Kerala, the Officer of Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Kerala.

1	2	3	4
	का०आ० 91(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग, ऐसे सरकारी आफिसर तथा आफिसरों के सामने केरल राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 91(E), dated the 3rd February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission hereby appoints each of the Officers of Govt. of Kerala as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Kerala.
	का०आ० 92(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से, मध्य प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में पदाभिहित करना ।
	S.O. 92(E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission of India hereby designates, the Returning Officer and the Assistant Returning Officer in consultation with the Govt. of Madhya Pradesh in respect of the Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh.
	का०आ० 93(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से महाराष्ट्र राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता ।
	S.O. 93(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission hereby designates the Returning Officer in consultation with the Govt. of Maharashtra as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra.
	का०आ० 94(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग, प्रत्येक सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर या आफिसरों के सामने महाराष्ट्र राज्य के ससदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 94(E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission hereby appoints each of the Officers of the Govt. as Returning Officer to Assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra.
	का०आ० 95(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग मणिपुर राज्य सरकार के परामर्श से उपायुक्त मणिपुर केन्द्रीय (इम्फाल) को मणिपुर राज्य के 1. आन्तरिक मणिपुर और 2. बाह्य मणिपुर (अ० आ० जा०) ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित ।
	S.O. 95(E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission hereby designates the Returning Officer in consultation with the Govt. of Manipur, Deputy Commissioner, Manipur Central (Imphal), to be the Returning Officer for 1. Inner Manipur and 2. Outer Manipur (ST.) Parliamentary Constituency in the State of Manipur.
	का०आ० 96(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग प्रत्येक सरकारी आफिसर का ऐसे आफिसरों के सामने मणिपुर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 96(E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission hereby appoints each of the Officer of Govt. as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Manipur.
	का०आ० 97(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे सरकारी आफिसर के सामने मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S.O. 97(E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission hereby designates as the Returning Officer, in consultation with the Govt. of Meghalaya of the Parliamentary Constituency in the State of Meghalaya.
	का०आ० 98(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग मेघालय सरकार के प्रत्येक आफिसर को मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है ।

1	2	3	4
	S O. 98(E), dated the 3rd February, 1977	Election Commission of India	Election Commission hereby appoints each of the Officers of Govt of Meghalaya to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Meghalaya
	का०आ० 99(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग नागालैण्ड सरकार के परामर्श से आयुक्त, नागालैण्ड, कोहिमा को नागालैण्ड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।
	S O 99(E), dated the 3rd February 1977	Do	Election Commission in consultation with the Govt of Nagaland, designates the Commissioner, Nagaland, Kohima to be the Returning Officer in Nagaland Parliamentary Constituency
	का०आ० 100(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा नागालैण्ड सरकार के आफिसरों को नागालैण्ड राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए नियुक्ति ।
	S O 100(E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission appoints the Officers of Government to assist the Returning Officer of the Nagaland Parliamentary Constituency in the State of Nagaland
	का०आ० 101(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा उड़ीसा सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को उड़ीसा राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S O 101(E), dated the 3rd February, 1977	Do	Election Commission designates, in consultation with the Government of Orissa, the Officer of the Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Orissa
	का०आ० 102(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी आफिसर या आफिसरों को उड़ीसा राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिय सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
	S O 102(E), dated the 3rd February, 1977	Do	Election Commission appoints the Officer or Officers of the Government as the Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Orissa
	का०आ० 103(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, पंजाब सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को पंजाब राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S O 103(E), dated the 3rd February, 1977	Do	Election Commission designates, in consultation with the Govt of Punjab, the Officer of Govt as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Punjab
	का०आ० 104(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रत्येक सरकारी आफिसर को पंजाब राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
	S O 104(E), dated the 3rd February 1977	Do	Election Commission appoints each of the Officers of Govt as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Punjab
	का० आ० 105 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान सरकार का परामर्श से सरकारी आफिसर को राजस्थान राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S O 105 (E), Dated the 3rd February, 1977	Do	Election Commission designates, in consultation with the Government of Rajasthan, the Officer of the Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Rajasthan
	का० आ० 106 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के आफिसरों की राजस्थान राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
	S O 106 (E) dated the 3rd February, 1977	Do	Election Commission appoints the Officers of the Government of Rajasthan as Assistant Returning Officers of the Parliamentary Constituencies in the State of Rajasthan

1	2	3	4
का० आ० 107 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		भारतीय निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग, सिक्किम सरकार के परामर्श से, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला कलक्टर, पूर्वी जिला, गंगटोक को सिक्किम के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।
S.O. 107 (E), dated the 3rd February 1977		Do.	Election Commission , in consultation with the Government of Sikkim, designates the District Magistrate and District Collector, East District, Gangtok to be the Returning Officer for the Parliamentary Constituency for Sikkim.
का० आ० 108 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, सिक्किम सरकार के परामर्श से, सरकार के आफिसरों को सिक्किम के लिये संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
S.O. 108 (E), dated the 3rd February, 1977.		Do.	Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim, appoints the Officers of Government as Assistant Returning Officers for the Parliamentary constituency for Sikkim.
का० आ० 109 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
S.O. 109 (E), dated the 3rd February, 1977		Do.	Election Commission, in consultation with the Government of Tamil Nadu, designates the Officer of Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Tamil Nadu.
का० आ० 110 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक सरकारी आफिसर को तमिलनाडु राज्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
S.O. 110 (E), dated the 3rd February, 1977		Do.	Election Commission appoints each of the Officers of Government as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Tamil Nadu.
का० आ० 111 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिपुरा सरकार के परामर्श से, सरकार के आफिसर को त्रिपुरा राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये रिटर्निंग, आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
S.O. 111 (E), dated the 3rd February, 1977		Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of Tripura, the Officer of Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Tripura.
का० आ० 112 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिपुरा सरकार के प्रत्येक आफिसर को त्रिपुरा राज्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
S.O. 112 (E), dated the 3rd February, 1977		Do.	Election Commission appoints each of the Officers of Government of Tripura as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Tripura.
का० आ० 113 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
S.O. 113 (E), dated the 3rd February, 1977		Do.	Election Commission designates in consultation with the Government of Uttar Pradesh, the Officer of Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh.
का० आ० 114 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी आफिसर या आफिसरों को, उत्तर प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
S.O. 114 (E), ated the 3rd February, 1977		Do.	Election Commission appoints Officer or Officers of Government as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Uttar Pradesh.
का० आ० 115 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में उस संसदीय क्षेत्र में समाविष्ट सभी निर्वाचन क्षेत्रों के सभी रिटर्निंग आफिसरों तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों को उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिये नियुक्ति ।

S.O. 115 (E), dated the 3rd February, 1977	Election Commission of India	Election Commission appoints in respect of every Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh all the Returning Officers and Assistant Returning Officers for all assembly constituencies comprised within that Parliamentary Constituency, as Officers to assist the Returning Officer of that Parliamentary Constituency
का० आ० 116 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को पश्चिमी बंगाल राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
S.O. 116 (E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of West Bengal, the Officers of the Government as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of West Bengal.
का० आ० 117 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के आफिसर या आफिसरों की पश्चिमी बंगाल राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति।
S.O. 117 (E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission appoints the Officer or Officers of the Government as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the state of West Bengal.
का० आ० 118 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977,	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से, उपायुक्त पोर्ट ब्लेयर, को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
S.O. 118 (E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, the Deputy Commissioner, Port Blair to be the Returning Officer for the Andaman and Nicobar Islands Parliamentary Constituency.
का० आ० 119 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी आफिसरों को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति।
S.O. 119 (E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission appoints the Officers of Government as Assistant Returning Officers of the Andaman and Nicobar Islands Parliamentary Constituency in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands.
का० आ० 120 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, अरूणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से, सरकारी आफिसर को अरूणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
S.O. 120 (E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Arunachal Pradesh, the Officer of Government as Returning Officer for the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Arunachal Pradesh.
का० आ० 121 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा अरूणाचल प्रदेश के प्रत्येक सरकारी आफिसर को अरूणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति।
S.O. 121 (E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission appoints each of the Government Officers as Assistant Returning Officer for Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Arunachal Pradesh.
का० आ० 122 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से, उपायुक्त, चण्डीगढ़ को चण्डीगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
S.O. 122 (E), dated the 3rd February, 1977	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Chandigarh, the Deputy Commissioner, Chandigarh to be the Returning Officer for the Chandigarh Parliamentary Constituency.

1	2	3	4
का० आ० 123 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		भारतीय निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी आफिसरों की चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के चण्डीगढ़, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति।
S.O. 123 (E), dated the 3rd February, 1977.		Election Commission of India	Election Commission appoints the Officers of Government as Assistant Returning Officers of the Chandigarh Parliamentary constituency in the Union Territory of Chandigarh.
का० आ० 124 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के परामर्श से, प्रशासक दादरा और नागर हवेली के सचिव को दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
S.O. 124 (E), dated the 3rd February, 1977.		Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, the Secretary to the Administrator Dadra and Nagar Haveli to be the Returning Officer for the Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency.
का० आ० 125 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के आफिसरों को दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में नियुक्ति।
S.O. 125 (E), dated the 3rd February, 1977.		Do.	Election Commission appoints the Officers of Government as Assistant Returning Officers for Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
का० आ० 126 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, दिल्ली प्रशासन के परामर्श से, दिल्ली प्रशासन के आफिसर को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
S.O. 126 (E), dated the 3rd February 1977.		Do.	Election Commission designates, in consultation with the Delhi Administration, the Officer of the Administration, as the Returning Officer of the Parliamentary constituencies in the Union Territory of Delhi.
का० आ० 127 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली प्रशासन के हरेक आफिसर को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति।
S.O. 127 (E), dated the 3rd February, 1977.		Do.	Election Commission appoints each of the Offiers of the Delhi Administration as Assistant Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the Union Territory of Delhi.
का० आ० 128 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, गोवा, दमन और दीव सरकार के परामर्श से कलक्टर, गोवा, पणजी को, गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
S.O 128 (E), dated the 3rd February, 1977.		Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of Goa, Daman and Diu, the Collector of Goa, Panaji, to be the Returning Officer for the Parliamentary Constituencies in the Union Territories of Goa, Daman and Diu.
का० आ० 129 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक सरकारी आफिसर को गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति।
S.O. 129 (E), dated the 3rd February, 1977.		Do.	Election Commission appoints each of the Officers of Government as Assistant Returning Officers of the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.
का० आ० 130 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977		—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के सेटिलमेंट आफिसर को, लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।

1	2	3	4
	S.O. 130 (E), dated the 3rd February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission in consultation with the Administration of the Union Territory of Lakshadweep, designates the Settlement Officer of the Union Territory of Lakshadweep as the Returning Officer for the Lakshadweep Parliamentary Constituency.
	का० आ० 131 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	भारतीय निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी आफिसरो को लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप मे नियुक्ति।
	S.O. 131 (E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission appoints the Officers of Government as Assistant Returning Officers of the Lakshadweep Parliamentary Constituency in the Union Territory of Lakshadweep.
	का० आ० 132 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, मिज़ोरम संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से, उपायुक्त, जिला अइजावल, अइजावल को मिज़ोरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
	S.O. 132 (E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Mizoram, the Deputy Commissioner, Aizawl Districts Aizawl to be the Returning Officer for the Mizoram Parliamentary Constituency.
	का० आ० 133 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन-आयोग द्वारा सरकार के आफिसरों की मिज़ोरम संघ राज्य-क्षेत्र में मिज़ोरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये, सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप मे नियुक्ति।
	S.O. 133 (E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission appoints the Officers of Government as Assistant Returning Officers of the Mirzoram Parliamentary Constituency in the Union Territory of Mizoram.
	का० आ० 134 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा, पांडिचेरी की सरकार के परामर्श से, कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट (इंडिपेंडेंट) को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र मे पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये रिटर्निंग आफिसर के रूपमे पदाभिहित करना।
	S.O. 134 (E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission designates, in consultation with the Government of Pondicherry, the Collector-cum-District Magistrate (Independent), Pondicherry to be the Returning Officer for the Parliamentary Constituency in the Union Territory of Pondischerry.
	का० आ० 135 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के आफिसरो की, पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र के पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति।
	S.O. 135 (E), dated the 3rd February, 1977.	Do.	Election Commission appoints the Officers of Government as Assistant Returning Officers of the Pondicherry Parliamentary Constituency in the Union Territory of Pondicherry
52	का० आ० 136 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1977	श्रम मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार द्वारा एक या अधिक ऐसी सलाहकार समितियां गठित करने के लिये विनिर्दिष्ट करती है जो उसे इस संबंध में सलाह देंगे कि किस सीमा तक स्त्रियो को नियोजित किया जा सकता है।
	S.O. 136 (E), dated the 5th February, 1977.	Ministry of Labour	Central Government specifies the constitutions of one or more Advisory Committees by the appropriate Government to advise it with regard to the extent of employment of Women.
	का० आ० 137 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1977	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार 10 फरवरी, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम लागू होगा।
	S.O. 137 (E), dated the 5th February, 1977.	Do.	Central Govt. appoints the 10th day of Feb, 1977 as the date on which the said act shall come into force.
53	का० आ० 138 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1977	नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार की (i) अलसी के बीज और (ii) अरण्डी के बीज के क्रय या विक्रय के लिए अग्रिम संविदा करने के बारे में घोषणा।
	S.O. 138 (E), dated the 5th February, 1977.	Ministry of Civil Supplies and Cooperation	Central Govt. declares regarding entering into any forward Contract for the Sale or Purchase of (i) Linseed and (ii) castorseed.

1	2	3	4
	का० आ० 139 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1977	नागरिक पूर्ति सहकारिता मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त वस्तुओं की बाबत अनन्तर्णीय विनिर्दिष्ट परिधान संक्रियाओं को सम्पूर्ण भारत में लागू होंगे ।
	S.O. 139 (E), dated the 5th February 1977.	Ministry of Civil Supplies and Cooperation	Central Govt. declares that the provisions of the said Act shall apply to non-Transferable specific delivery contracts in respect of the said Commodities in of the whole of India.
54	का० आ० 140 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1977	वाणिज्य मंत्रालय	इस आदेश के निर्यात (नियंत्रण) द्वारा संशोधन आदेश 1977 की संज्ञा दी जाये ।
	S.O. 140 (E), dated the 5th Febyuary, 1977.	Ministry of Commerce.	This order may the called the exports (Control) 2nd Amd. order, 1977.
55.	का० आ० 141 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/केरल /77(2) तारीख 2 फरवरी, 1977 में संशोधन ।
	S.O. 141 (E), dated the 7th February, 1977.	Election Commission of India.	Election Commission directs Amendments in its notification No. 434/KL/77 (2) deted 2nd Feb, 1977.
56.	का० आ० 142 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 1977	राजस्व और बैंकिंग विभाग	केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में "सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है ।
	S.O. 142 (E) dated the 8th February, 1977.	Department of Revenue and Banking	Central Govt. establishes a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Sultanpur Kshetriya Government Bank.
	का० आ० 143 (अ) दिनांक 8 फरवरी, 1977	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार सुल्तानपुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है जहां पर सुल्तानपुर क्षेत्रय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा ।
	S.O. 143 (E), dated the 8th February, 1977.	Do.	Central Govt. specifies Sultanpur as the place where Sultanpur Kshetriya Gramin Bank shall have its head Offices.
	का० आ० 114 (अ) दिनांक 8 फरवरी, 1977	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 3 की उपधारा (i) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है ।
	S.O. 144 (E), dated the 8th February, 1977.	Do.	Central Govt. Notifies the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank being an Institution establish under Sub-Section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976.
	का० आ० 145 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 1977	भारतीय रिज़र्व बैंक	भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में "सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुल्तानपुर" को समाविष्ट किया जाए ।
	S.O. 145 (E), dated the 8th February, 1977.	Reserve Bank of India	Reserve Banks of India directs the inclusion in the IInd Schedule to the said Act of the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur.
	का० आ० 146 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	भारत निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेन्स को एक राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी और "हल" प्रतीक उसके लिए आरक्षित रहेगा ।
	S.O. 146 (E), dated the 8th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission of India directs that Jammu and Kashmir National Conference shall be recognised as a State party and the Symbol 'Plough' shall be Reserved for it.
	का० आ० 147 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 (ii) तारीख 31 जनवरी, 1975 के असाधारण अंक में प्रकाशित तथा समय-2 पर संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 56/75-(i) तारीख 31 जनवरी, 1975 में संशोधन करता है ।
	S.O. 147 (E), dated the 8th February, 1977.	Do.	Election Commission makes the following Amendment in its Notification No. 56/75 I dated the 31st Jan., 1975 published as S.O. 61 (E) in the Gazette of India Extra Ordinary Part II Section 3 (ii) dated 31st Jan., 1975 and as amended from time to time.
	का० आ० 148 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 1977	—तदैव—	भारत निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि मुस्लिम लीग (विपक्ष) को केरल राज्य में एक राज्यीय दल के रूप में तदर्थ आधार पर मान्यता दी जाएगी और "नाव" प्रतीक उसके लिए आरक्षित रहेगा ।

1	2	3	4
	S.O. 148 (E), dated the 8th February, 1977	Election Commission of India	Election Commission of India directs that Muslim league (opposition) shall be recognised as a State party on adhoc basis in the State of Kerala and that the Symbol "Boat" shall be reserved for it.
58.	का० आ० 149(अ), दिनांक 9 फरवरी 1977	गृह मंत्रालय	राष्ट्रपति द्वारा निदेश कि अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित ही रहेगा और अनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध 28 मार्च, 1977 से एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रवर्तित रहेंगे ।
	S.O. 149 (E), dated the 9th Feb, 1977	Ministry of Home Affairs	President of India directs that the Operation of the provision of the Acts shall Continues to remain suspended for a further period of one year w.e.f. the 28th March, 1977.
59	का० आ० 150 (अ), दिनांक 9 फरवरी, 1977	उद्योग मंत्रालय	इस आदेश को सीमेंट नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1977 कहा जाएगा ।
	S.O. 150 (E), dated the 9th Feb. 1977	Ministry of Industry	This order may be called the Cement Control (2nd Amendment) Order, 1977.
60.	का० आ० 151(अ), दिनांक 9 फरवरी, 1977	वाणिज्य मंत्रालय	इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1977 की संज्ञा दी जाए ।
	S.O. 151 (E), dated 9th Feb, 1977	Ministry of Commerce	This order may be called the Exports (Control) Third Amendment Order, 1977.
61.	का० आ० 152(अ), दिनांक 9 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करता है— (क) राष्ट्रीय दल तथा उनके लिये क्रमशः आरक्षित प्रतीक (ख) राज्यीय दल, वह राज्य अथवा वो राज्य जिनमें वे राज्यीय दल है तथा ऐसे राज्य अथवा राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक, तथा (ग) प्रत्येक राज्य के लिए मुक्त प्रतीक ।
	S.O. 152 (E), dated the 9th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission Specifies that— (A) The National Parties and the Symbols respectively reserved for then, (B) the State parties the State or States in which they are State parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States, and (C) The free symbols for each State.
62.	का० आ० 153(अ), दिनांक 10 फरवरी, 1977	विधि,न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	राष्ट्रपति सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करते है कि वे उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करे ।
	S.O. 153 (E), dated the 10th February, 1977.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	President calls upon all the Parliamentary Constituencies to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders mand there under.
	का० आ० 154(अ), दिनांक 10 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग—प्रत्येक राज्य के लिये तथा उक्त निर्वाचनों में से प्रत्येक के बारे में—नाम निर्देशन के लिये अन्तिम सचिव नाम निर्देशन की समीक्षा की तारीख, अभ्यर्थियों में वापस लेने के लिये अन्तिम तारीख, वह तारीख जिस के पूर्व निर्वाचन पूरा कर दिया जाएगा तथा मतदान की तारीख नियत करता है ।
	S.O. 154 (E), dated the 10th February, 1977.	Election Commission of India.	Election Commission appoints for each State with respect to each of the said elections the last date for making nominations, date for the Scrutiny of nominations, last date for withdrawal of condidature, date before which the election shall be completed and the date of Poll.
	का०आ० 155(अ), दिनांक 10 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान का समय नियत करना ।
	S.O. 155 (E), dated the 10th Febryary, 1977.	-Do-	Election Commission fix the hours of Poll.
63.	का० आ० 156(अ), दिनांक 10 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 434/पंजाब/77(2), तारीख 29 जनवरी, 1977 में संशोधन करता है ।
	S.O. 156 (E), dated the 10th February, 1977.	-Do-	Election Commission makes amendments in its notification No.434/PB/77(2), dated 29 January, 1977.
64.	का०आ० 157(अ), दिनांक 10 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि मणिपुर राज्य में मणिपुर फ्रिल्म-प्लेन यूनियन के लिये आरक्षित प्रतीक "शेर" वापस ले लिया जाएगा ।

1	2	3	4
			और मणिपुर राज्य के बारे में वह इसी समय से अगले आदेशों तक ऐसे वापस लिया ही रहेगा तथा उक्त साधारण निर्वाचन के प्रयोजन के लिये इन प्रतिद्वंदी गुटो में से किसी को भी मणिपुर राज्य में एक मान्यता प्राप्त राज्यीय दल के रूप में नही माना जाएगा ।
64.	S.O. 157(E), dated the 10th February, 1977.	Election Commision of India	Election Commission directs that the symbol 'Lion' reserved for the Manipur Hills-Plain Union in the State of Manipur, shall be withdrawn and shall remains so withdrawn in the State of Manipur is concurrently with immediate effect and untill further orders and that for any purpose of the said general election, none of the rival groups shall be treated as a recognised State Party in the State of Manipur.
65	का० आ० 158(अ), दिनाक 10 फरवरी, 1977	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि कुछ फिल्मा, जिन्हें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'ए' प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, का प्रदर्शन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो मास की अवधि के लिये रोक दिया जाए ।
	S.O. 158(E), dated the 10th February, 1977.	Ministry of Information and Broadcasting	Central Government directs suspension of exhibition of some films which have been granted 'A' certificate by the Central Board of Film Censors, for two months with effect from the date of issue of this notification.
66	का० आ० 159(अ)/15/आई डी आर ए/77, दिनाक 10 फरवरी, 1977	उद्योग मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार, इस मामले की परिस्थितियो का समस्त और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये, व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है ।
	S.O. 159(E)/15/IDRA/77, dated the 10th February, 1977.	Ministry of Industry	Central Government appoints a body of persons for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the Case.
	का०आ०.160(अ)/15/ आई डी आर ए/77, दिनांक 10 फरवरी, 1977	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार, इस मामले की परिस्थितियों का समस्त और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है ।
	S.O. 160(E)/15/IDRA/77, dated the 10th February, 1977.	-Do-	Central Government appoints a body of persons for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the Case.
67.	का० आ० 161(अ), दिनांक 11 फरवरी, 1977	गृह मंत्रालय	अधिसूचित किया जाता है कि उप राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है ।
	S.O. 161(E), dated the 11th February, 1977.	Ministry of Home Affairs	Notified that the Vice-President has assumed the office of the President.
68.	का०आ० 162(अ), दिनाक 14 फरवरी, 1977	उद्योग मत्रालय	केन्द्रीय सरकार यथा वर्णित वस्त्रो के अनुसूचित उद्योगों में सम्पूर्णत: या अंशत: पटसन से विनिर्मित या उत्पादित उस माल के वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर विनिर्दिष्ट दरों पर 1 मार्च, 1977 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा ।
	S.O. 162(E), dated the 14th February, 1977.	Ministry of Industry	Central Government specifies the classes of goods manufactured or produced wholly or in part of jute in the Scheduled industry of textiles on which a duty of excise shall be levied and collected as a case for the purposes of the said Act for a period of one year commencing from 1st March, 1977 at specified rates.
69	का०आ० 163(अ), दिनाक 14 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि तारीख 29 जनवरी, 1977 की इसकी अधिसूचना स० 434/दिल्ली /77(1) मे सशोधन किये जायेंगे ।
	S.O. 163(E), dated the 14th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission directs amendments in its notification No.434/DL/77(1), dated 29 January, 1977.
70.	का० आ० 164(अ), दिनाक 14 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी अधिसूचना स० 434/केरल/77(2), तारीख 2 फरवरी, 1977 में संशोधन का निदेश ।
	S.O. 164(E), dated the 14th February, 1977.	-Do-	Election Commission directs re-amendment in its notification No. 434/KL/77(2), dated 2 February, 1977.

1	2	3	4
71.	का० आ० 165(अ), दिनांक 14 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा अतिरिक्त रूप से, जिले के उप जिला निर्वाचन आफिसर का रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिये गुजरात राज्य में नियुक्त करना ।
	S.O. 165(E), dated the 14th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission appoints, in addition, in the State of Gujarat, the Deputy District Election Officer of the distrist, as the officer to assist the Returning Officer.
72	का० आ० 166(अ), दिनांक 15 फरवरी, 1977	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	इन नियमो का नाम धन कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1977 है ।
	S.O. 166(E), dated the 15th February, 1977.	Central Board of Direct Taxes	These rules may be called the Wealth-Tax (Second Amendment) Rules, 1977.
73.	का० आ० 167(अ), दिनांक 15 फरवरी, 1977.	—तदैव—	इन नियमो का नाम कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1977 है।
	S.O. 167(E), dated the 15th February, 1977.	-Do-	These rules may be called the Companies (Profits) Surtax (Amendment) Rules, 1977.
74.	का०आ० 168(अ), दिनांक 15 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा अतिरिक्त रूप से, श्री राम अधीन राम, अतिरिक्त अधिकारी प्रथम, आजम गढ़ की 44—घोसी, 45—आजमगढ़ और 46—लालगंज (अ०जा०) समवीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति।
	S.O. 168(E), dated the 15th February, 1977.	Election Commission of India.	Election Commission appoints, in addition, Sri Ram Adhin Ram, Extra Officer I, Azamgarh, to be the Assistant Returning-Officer for 44-Ghosi, 45-Azamgarh and 46-Lalganj (SC) Parliamentary Constituencies.
75.	का० आ० 169(अ), दिनांक 16 फरवरी, 1977	—तदैव—	भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 3 फरवरी, 1977 में का०आ० 76(अ) के रूप में प्रकाशित निर्वाचन आयोग की तारीख 1 फरवरी, 1977 की अधिसूचना सं 434/आ०प्र०/77(2) विषयक शुद्धि-पत्र ।
	S.O. 169(E), dated the 16th February, 1977.	-Do-	Carrigendum re-Commission's notification No.434/AP/72(2), dated 1 February, 1977 published as S.O.76(E) in Part II, Section 3, Sub section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary) dated February 3, 1977.
76.	का० आ० 170(अ), दिनांक 16 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा केरल राज्य में 'केरल कांग्रेस (पिल्लई ग्रुप)' नाम से एक राज्यीय दल के रूप में तदर्थ आधार पर मान्यता तथा उक्त दल के लिये प्रतीक आरक्षण का निर्देश ।
	S.O. 170(E), dated the 16th February, 1977.	-Do-	Election Commission directs recognition of "Kerala Congress (Pillai Group)" as a State Party on ad hoc basis in the State of Kerala and reservation of as ymbol for the said Party.
77.	का० आ० 171(अ), दिनांक 16 फरवरी, 1977	—तदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी अधिसूचना सं 434/केरल/77(2), तारीख 2 फरवरी, 1977 में संशोधन विषयक निर्देश ।
	S.O. 171(E), dated the 16th February, 1977.	-Do-	Election Commission directs amendment in its notification No. 434/KL/77(2), dated 2nd February, 1977.
78.	का० आ० 172(अ), दिनांक 17 फरवरी, 1977	वाणिज्य मंत्रालय	इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) चौथे संशोधन आदेश, 1977 की संज्ञा दी जाए ।
	S.O. 172(E), dated the 17th February, 1977.	Ministry of Commerce	This order may be called the Exports (control) Fourth Amendment Order, 1977.
79.	का० आ० 173(अ), दिनांक 17 फरवरी, 1977	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना सं० का आ० 469(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1976 के अधीन नियुक्त भुगतान आयुक्त की सहायता करने के लिये श्री एस० विजयरंगम को नियुक्त करती है ।
	S.O. 173(E), dated the 17th February, 1977.	-Do-	Central Government appoints Shri S. Vijayarangam, tourists the Commissioner of Payments appointed under the notification No.S.O.469(E), dated the 9th July, 1976.
80.	का० आ० 174(अ), दिनांक 17 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 434/पंजाब/77(1), तारीख 29 जनवरी, 1977 में संशोधन करता है ।
	S.O. 174(E), dated the 17th Feburary, 1977.	Election Commission of India	Election Commission makes Amendment in its Notification No. 434/PB/77(1), dated 29 January, 1977.

1	2	3	4
	का० आ० 175(अ), दिनांक 17 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 434/पंजाब/77(2), तारीख 29, जनवरी 1977 में संशोधन करता है।
	S.O. 175(E), dated the 17th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission makes Amendment in its Notification No. 434/PB/77(2), dated 29 January, 1977.
81.	का० आ० 176(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1977	रेलवे मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री एच०सी०पी० त्रिपाठी, जो इस समय अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, मद्रास के रूप में कार्य कर रहे हैं, की पूर्व रेलवे पर मुगलसराय में 130 डाउन वाराणसी—आसनसोल सवारी गाड़ी और 2 वी एम ए सवारी गाड़ी के बीच 18 जनवरी, 1977 को हुई दुर्घटना से उत्पन्न सभी दावों का निपटारा करने के लिए, तदर्थ दावा आयुक्त के रूप में नियुक्ति करती है।
	S.O. 176(E), dated the 18th February, 1977.	Ministry of Railways	Central Government hereby appoints Shri H.C.P. Tripathi, a retired Judge of the Allahabad High Court presently working as Chairman, Railway Rates Tribunal, Madras concurrently as Ad hoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the accident involving 130 Dn. Varanasi-Asssansal Passenger and No. 2 VM.A. Passenger at Mughalsarai on Eastern Railway on 18th Jan., 1977.
82.	S.O. 177(E), dated the 18th February, 1977.	Ministry of Home Affairs	Central Government specifies each of the Organisation to be an Organisation of a Political nature, not being a political party.
83.	का० आ० 178(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1977	उद्योग मंत्रालय	इस आदेश का नाम सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 है।
	S.O. 178 (E), dated the 18th February, 1977.	Ministry of Industry	This Order may be called the Cement (Quality Control) Amendment Order, 1977.
84.	का० आ० 179(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1977	राजस्व और बैंकिंग विभाग	इन नियमों का नाम तस्कर और विदेशी मुद्रा छलमार्जक (समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण) नियम, 1977 है।
	S.O. 179(E), dated the 18th February, 1977.	Department of Revenue and Banking	These Rules may be called the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forfeited Property) Rules, 1977.
85.	का० आ० 180(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1977	वाणिज्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार अधिसूचना सं० का०आ० 469 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 1976 के अधीन नियुक्त भुगतान आयुक्त की सहायता करने के लिये श्री सी०पी० अब्दुल्ला कई को नियुक्त करती है।
	S.O. 180(E), dated the 18th February, 1977.	Ministry of Commerce	Central Government appoints Shri C.P. Abdulla Keyi, to assist the Commissioner of Payments appointed under the Notification No.S.O.469(E), dated the 9th July, 1976.
86.	का० आ० 181(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1977	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार अधिसूचना सं० का०आ० 169(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1976 के अधीन नियुक्त भुगतान आयुक्त की सहायता करने के लिये श्री वी०एच० ठाकोर को नियुक्त करती है।
	S.O. 181(E), dated the 18th February, 1977.	-Do-	Central Government appoints Shri V.H. Thakore to assist the Commissioner of Payments appointed under the notification No. S.O. 469(E), dated the 9th July, 1976.
87.	का० आ० 182(अ), दिनांक 19 फरवरी, 197	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी अधिसूचना सं० 434/हरि०/77(1), तारीख 29 जनवरी, 1977 में संशोधन का निदेश।
	S.O. 182(E), dated the 19th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission directs amendment in its notification No. 434/HN/77(1), dated 29 January, 1977.
88.	का० आ० 183(अ), दिनांक 21 फरवरी, 1977	राजस्व और बैंकिंग विभाग	केन्द्रीय सरकार फरवरी, 1977 के इक्कीसवें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।
	S.O. 183(E), dated the 21st February, 1977.	Department of Revenue and Banking	Central Government appoints the 21st day of February, 1977 as the date on which the said Act shall come into force.
	का० आ० 184(अ), दिनांक 21 फरवरी, 1977	—तदैव—	केन्द्रीय सरकार फरवरी, 1977 के इक्कीसवें दिन को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस तारीख को बैंककारी सेवा आयोग स्थापित किया जाएगा।
	S.O. 184(E), dated the 21st February, 1977.	-Do-	Central Government specifies the twenty first day of February, 1977 as the date on which Banking Service Commission shall be established.

1	2	3	4
	का० आ० 185(अ), दिनांक 21 फरवरी, 1977	राजस्व और बैंकिंग विभाग	केन्द्रीय सरकार श्री ए० एन० बनर्जी को बैंककारी सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।
	S.O. 185(E), dated the 21st February, 1977.	Department of Revenue and Banking	Central Government appoints Shri A.N. Banerji as the Chairman of the Banking Service Commission.
89.	का० आ० 186(अ), दिनांक 21 फरवरी, 1977	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	अधिसूचना सं० का०आ० 671(अ), दिनांक 11 अक्तूबर, 1976 विषयक शुद्धि-पत्र ।
	S.O. 186(E), dated the 21st February, 1977.	Ministry of Agriculture and Irrigation	Corrigendum re. notification No.S.O.674(E), dated 11th October, 1976.
90.	का० आ० 187(अ), दिनांक 21 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक सरकारी आफिसर की उड़ीसा राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिये अतिरिक्त रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 187(E), dated the 21st February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission, in addition, appoints each of the Officers of the Government to assist the Returning Officers of the Parliamentary Constituency in the State of Orissa.
91	का० आ० 188(अ), दिनांक 22 फरवरी, 1977	—वही—	निर्वाचन आयोग द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र में मतपत्र द्वारा मतदान की पद्धति विषयक निदेश ।
	S.O. 188(E), dated the 22nd February, 1977.	-Do-	Election Commission directs re. methed of voting by ballot in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
92.	का० आ० 189(अ), दिनांक 22 फरवरी, 1977	—वही—	निर्वाचन आयोग द्वारा अतिरिक्त रूप में, आसाम सरकार के आफिसरों को आसाम राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिये नियुक्ति ।
	S.O. 189(E), dated the 22nd February, 1977.	-Do-	Election Commission, in addition, appoints the Officers of the Government of Assam to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Assam.
93.	का० आ० 190(अ)/15क/आई डी आर ए/77, दिनांक 23 फरवरी, 1977	उद्योग मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त औद्योगिक उपक्रम को पुन. आरम्भ करने की सम्भावना की जांच के प्रयोजन के लिये व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है ।
	S.O. 193(E)/15A/IDRA/77, dated the 23rd February, 1977.	Ministry of Industry	Central Government appoints a body of persons for the purpose of making an investigation into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertaking.
94.	का० आ० 191(अ), दिनांक 23 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा 9 फरवरी, 1977 को का०आ० 152(अ) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii) में प्रकाशित उसकी 9 फरवरी, 1977 की अधिसूचना सं० 46/77-II में शुद्धि का निदेश ।
	S.O. 191(E), dated the 23rd February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission directs corrections in its notification No.46/77-II, dated 9 February, 1977, published as S.O. 152(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii)), dated 9 February, 1977.
95.	का० आ० 192 (अ), दिनांक 24 फरवरी, 1977	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा "आईना" हिन्दी नामक फिल्म का प्रदर्शन स्थगित करने के आदेश को शुद्ध करने का निदेश ।
	S.O. 192(E), dated the 24th February, 1977.	Ministry of Information and Broadcasting	Central Government directs to rescind the Order suspending exhibition of the film entitled "AAINA" (Hindi).
96.	का० आ० 193(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1977	—वही—	केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि वह आदेश, जिसमे "तित्तमाकला" (तेलुगु) नामक फिल्म का प्रदर्शन स्थगित किया गया था, रद्द कर दिया जाए ।
	S.O. 193(E), dated the 24th February, 1977.	-Do-	Central Government directs that the Order suspending the exhibition of the film "TATAMMA KALA" (Telugu) be rescinded.
97.	का० आ० 194(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी अधिसूचना सं० 434/गुज०/77(2), तारीख 29 जनवरी, 1977 में संशोधन का निदेश ।
	S.O. 194(E), dated 24th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission directs that further amendment shall be made in its notification No.434/GJ/77(2), dated 29th January, 1977.

1	2	3	4
98.	का० आ० 195(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी अधिसूचना सं० 434/तं० ना० 77/(1) तारीख 1 फरवरी, 1977 में संशोधन का निदेश ।
	S.O. 195(E), dated the 25th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission directs amendment in its notification No. 434/TN/77(1), dated 1 February, 1977.
	का० आ० 196(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1977	—सदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी अधिसूचना सं० 434/तं० ना०/77(2), तारीख 1 फरवरी, 1977 में संशोधन के लिये निदेश ।
	S.O. 196(E), dated the 25th February, 1977.	-Do-	Election Commission directs that amendments shall be made in its notification No. 434/TN/77(2), dated 1 February, 1977.
99.	का० आ० 197(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1977	श्रम मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार 27 फरवरी, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4, 5 और 6 के उपबन्ध गुजरात राज्य के क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे ।
	S.O. 197(E), dated the 25the February, 1977.	Ministry of Labour	Central Government appoints the 27th February, 1977 as the date on which provisions of Chapters IV, V and VI of the said Act shall come into force in the area in the State of Gujarat.
100.	का० आ० 198(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी अधिसूचना सं० 434/उड़ीसा/77(1), तारीख 21 फरवरी, 1977 में संशोधन के लिये निदेश ।
	S.O. 198(E), dated the 25th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission directs amendment in its notification No. 434/OR/77(1), dated 21 February, 1977.
101.	का० आ० 199(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1977	—सदैव—	निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 29 जनवरी, 1977 की उसकी अधिसूचना सं० 434/बिहार/77(1) में संशोधन का निदेश ।
	S.O. 199(E), dated the 25th February, 1977.	-Do-	Election Commission directs amendments in its notification No. 434/BR/77(1), dated 29 January, 1977.
102.	का० आ० 200(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1977	—सदैव—	निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 10 फरवरी, 1977 में संशोधन करता है ।
	S.O. 200(E), dated the 25th February, 1977.	-Do-	Election Commission makes amendments in its notification No. 464/77, dated 10 February, 1977.
103	का० आ० 201 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 1977	राजस्व और बैंकिंग विभाग	केन्द्रीय सरकार मार्च, 1977 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6, 12 और 13 प्रवृत्त होगी ।
	S.O. 201(E), dated the 28th February, 1977.	Department of Revenue and Banking.	Central Government appoints the 1st day of March, 1977 as the date on which sections 6, 12 and 13 of the said Act shall come into force.
104.	का० आ० 202(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1977	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी अधिसूचना सं० 434/अरुणाचल/77(1), तारीख 31 जनवरी, 1977 में संशोधन का निदेश ।
	S.O. 202(E), dated the 28th February, 1977.	Election Commission of India	Election Commission directs amendment in its notification No. 434/ARUN/77(1), dated 31 January, 1977.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 4 जून, 1977

का०आ० 2086—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के परामर्श से, श्री डी० सी० मिश्र के स्थान पर श्री आर० एस० राय, वित्त सचिव, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिये मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/अ० नि० नी०/77]

वी० नागासुब्रमनियन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 4th June, 1977

S.O. 2086.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Andaman and Nicobar Islands Administration, hereby nominates Shri R. S. Rai, Finance Secretary of Andaman and Nicobar Islands Administration, as the Chief Electroral Officer for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands with effect from the date he takes charge of the office and until further orders vice Shri D. C. Misra.

[No. 154/ANI/77]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1976

आय-कर

का० आ० 2087.—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री राजा राजेश्वर स्वामी देवस्थानम, वेमूलवाडा" को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये, निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिये तथा उस वर्ष से, अधिसूचित करती है ।

[सं० 1612/फा० सं० 197/96/76-आ० क० (ए० आई०)]

टी० वी० झुनझुनवाला, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 31st December, 1976

INCOME-TAX

S.O 2087.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Shri Raja Rajeswara Swamy Devasthanam, Vemulawada" for the purpose of the said section for and from assessment years 1974-75 and 1975-76.

[No. 1612/F. No. 197/66-IT(AI)]

T. P JHUNJHUNWALA, Director

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

आय-कर

का० आ० 2088 —केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री आरासूरी अम्बाजी, माताजी देवस्थान न्यास अम्बाजी" को उक्त धारा के प्रयोजन के लिये निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिये तथा उस वर्ष से अधिसूचित करती है।

[सं० 1633/फा० सं० 197/6/77-आ० क० (ए० आई०)]

New Delhi, the 24th January, 1977

INCOME-TAX

S.O. 2088.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Arasuri Ambaji Mataji Devsthan Trust, Ambaji" for the purpose of the said section for and from assessment year 1976-77.

[No 1633/F. No. 197/6/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1977

आय-कर

का० आ० 2089 —केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि आर्कडाइसेस आफ हैदराबाद सोसाइटी, सिकन्दराबाद" को निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 1639/फा० सं० 197/129/76-आ० क० (ए० आई०)]

New Delhi, the 28th January, 1977

INCOME-TAX

S.O. 2089.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Archdiocese of Hyderabad Society Secunderabad" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1975-76

[No 1639/F No 197/129/76 IT(AI)]

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1977

आय-कर

का० आ० 2090 —केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "गोविन्द भवन कार्यालय, कलकत्ता" का निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिये और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 1672/फा० सं० 197/143/76-आ० क० (ए० आई०)]

New Delhi, the 26th February, 1977

INCOME-TAX

S.O. 2090.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Govind Bhawan Karyalaya, Calcutta" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1974-75.

[No. 1672/F. No. 197/143/76-IT(AI)]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1977

आय-कर

का० आ० 2091 —केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "हिन्दू सत्कार समिति कलकत्ता' को निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिये और उससे धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 1697/फा० सं० 197/183/76-आ० क० (ए० आई०)]

New Delhi, the 28th March, 1977

INCOME-TAX

S.O.2091 —In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Hindu Satkar Samity, Calcutta" for the purpose of the said section for and from the assessment year 1974-75

[No 1697 F. No. 197/13/76-IT(AI)]

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1977

आय-कर

का० आ० 2092 —केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ङ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कल्याण वेंकट रमण स्वामी, मन्दिर थानथोनिमलाई, कारूर जिला तिरुचिरापल्ली को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये तमिलनाडु में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 1730/फा० सं० 176/33/77-आई० टी० (ए० आई०)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

New Delhi, the 16th April, 1977

Income-Tax

S.O. 2092.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies "Shri Kalyanavenkataramanaswamy Temple, Thanthonimalai, Karur-5, Tiruchirapalli District" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Section.

[No. 1730/F. No. 176/33/77-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1977

आय-कर

का० आ० 2093.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(i) यह कि श्री अभिनव विद्यातीर्थ स्वामिगल वैज्ञानिक अनुसन्धान अकादमी, बंगलौर वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगा।

(ii) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपने वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिये अधिकथित किये जायें और उसे सूचित किये जायें।

संस्था

श्री अभिनव विद्यातीर्थ स्वामिगल वैज्ञानिक अनुसन्धान अकादमी, बंगलौर।

यह अधिसूचना 9-3-1977 से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं० 1714/फा० सं० 203/32/77-आई० टी० (ए० II)]

New Delhi, the 5th April, 1977

Income-Tax

S.O. 2093.—It is hereby notified for general information that the association mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) That the Sri Abhinava Vidyateertha Swamigal Scientific Research Academy, Bangalore, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research ;

(ii) that the said Academy will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

ASSOCIATION

Sri Abhinava Vidyateertha Swamigal Scientific Research Academy, Bangalore.

This notification is effective for a period of three years from 9-3-1977.

[No. 1714/F. No. 203/32/77-IT(A.II)]

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1977

आय-कर

का० आ० 2094.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(i) यह कि भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगा।

(ii) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपने वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी क्रिया कलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिये अधिकथित किये जायें, और उसे सूचित किये जायें।

संस्था

भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1976 से प्रभावी है।

[सं० 1729/फा० सं० 203/131/76-आई० टी० (ए० II)]

जे० पी० शर्मा, उप-सचिव

New Delhi, the 15th April, 1977

INCOME-TAX

S.O. 2094.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) that the Bhagalpur University, Bhagalpur will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research ;

(ii) That the said University, will furnish the annual return of its Scientific Research Activities to the prescribed authority by 30th April, each year for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose

INSTITUTION

Bhagalpur University, Bhagalpur.

This notification takes effect from 1st September, 1976.

[No. 1729/F. No. 203/131/76-IT(AII)]

J. P. SHARMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 4 मई, 1977

का० आ० 2095.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 6 फरवरी, 1973 के अपने आदेश सं० 4/फा० सं० 328/111/72-धनकर के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि दिनांक 6-2-1973 के उपर्युक्त आदेश के नीचे दी गई सारणी की क्र० सं० 14 ए के स्तम्भ (2) और (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

सारणी

(1)	(2)	(3)
14ए	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अभिग्रहण रेंज, कानपुर	आयकर आयुक्त, कानपुर, मेरठ और आगरा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाके।

2 यह आदेश 9-5-1977 से लागू होगा।

[सं० 34/77/फा० सं० 316/44/77-धन कर]

एच० एन० मण्डल, अवर सचिव

New Delhi, the 4th May, 1977

S.O. 2095.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of their order No. 4/F No 328/111/72-WT, dated 6th February, 1973, the Central Government hereby order that in the Table given below the aforesaid order dated 6-2-73, the entries under columns (2) & (3) against S No 14A shall be substituted by the following:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
14A	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Kanpur	Areas comprised within the jurisdiction of Commissioners of Income-tax, Kanpur, Meerut and Agra

2 This order shall come into force with effect from 9-5-1977.

[No 34/77/F No 316/44/77-WT]
H N MANDAL, Under Secy

नई दिल्ली 28 मई, 1977

आयकर

का० आ० 2096—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की दिनांक 18 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना स० 1168 (फा० स० 404/98/75-आ० क० स० क०) के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री वी० पी० खोबरागड़े को, जो केन्द्रीय सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2 यह अधिसूचना जिस तारीख से श्री खोबरागड़े कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार सम्भालेंगे उसी तारीख से लागू होगी।

[स० 1785/फा० स० 404/28/77-आ० क० स० क०]

एच० वंकटरामन, उप-सचिव

New Delhi, the 28th May, 1977
INCOME TAX

S.O. 2096—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the Notification No 1168 (F No 404/98/75 ITCC) dated 18th December, 1975 of the Government of India in the Department of Revenue & Banking, the Central Government hereby authorises Shri V P Khobragade being a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act

2 This notification shall come into force with effect from the date Shri Khobragade takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 1785 (F No 404/28/77 ITCC)]
H VENKATARAMAN, Dy Secy

कोचीन, 26 अप्रैल, 1977

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

का० आ० 2097—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 के नियम 233 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निदेश देता हूँ कि इस समाहर्ता-अधिकार क्षेत्र में [केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 4-II (6) के अन्तर्गत आने वाली] नसवार के निर्माता एतत्पश्चात् कच्चे माल अर्थात् नसवार, बनाने में इस्तेमाल किये जाने वाले (1) तम्बाकू (2) सिगरेट का चूरा और (3) वनस्पति उत्पाद का एक पृथक दैनिक खाता संलग्न फार्म में रखेंगे, और, जैसा कि पूर्वोक्त नियम के नियम 53 के अन्तर्गत अपेक्षित है, उक्त कच्चे माल की एक त्रैमासिक विवरणी भी, जिस तिमाही से उसका संबंध हो, उसमें अगले मास की दस तारीख तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित रेंज अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे इसकी प्रतिलिपि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित सहायक समाहर्ता को भेजी जायेगी।

2 मैं यह भी निदेश देता हूँ कि उक्त निर्माता 'खमीर' (ऐसा मिश्रण जिसमें तम्बाकू, सिगरेट का चूरा, वनस्पति घी, चूना और जल होता है) के नाम से ज्ञात अन्तवर्ती उत्पादन का खाता भी संलग्न फार्म में रखेंगे।

नसवार बनाने के लिए कच्चे माल का दैनिक खाता

कारखाने का नाम पता

कच्चे माल का विवरण

तारीख	अथशेष	बीजक संख्या तथा तारीख	माल भेजने वाले का नाम	प्राप्त माल की मात्रा	जोड़
1	2	3	4	5	6

निम्नलिखित के निर्माण में इस्तेमाल की गई मात्रा — नसवार	निम्नलिखित के निर्माण में इस्तेमाल की गई मात्रा — अन्य माल	अन्य प्रकार से निपटाई गई मात्रा	निपटान का स्वरूप	बरबाद की गई अथवा नष्ट की गई मात्रा	रोकड़-बाकी
7	8	9	10	11	12

निर्मित नसवार की मात्रा	निर्मित अन्य माल की मात्रा	विशेष	निर्धारिति अथवा उसके एजेंट के हस्ताक्षर
13	14	15	16

मास के लिए जोड़

नोट —1 प्रत्येक कच्चे माल के संबंध में पृथक रजिस्टर रखा जाना चाहिए।

2 यदि कोई भी कच्चा माल उत्पादन शुल्क लगने योग्य (विभिन्न टैरिफ मदों के अन्तर्गत आने वाले) एक से अधिक माल अथवा अन्य निर्मित माल के लिये इस्तेमाल किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रत्येक माल के लिए इस्तेमाल की गई मात्रा अलग-अलग दिखाई जानी चाहिये और इसके साथ कालम 5 तथा 8 को उपयुक्त प्रकार से उप-विभाजित करके इस प्रकार के माल का विवरण दिया जाना चाहिए।

खमीर खाता रजिस्टर

कारखाने का नाम तथा पता :

मिलाने की तारीख	बैच संख्या	मिलाये गये तम्बाकू की मात्रा	मिलाये गये सिगरेट के चूरे की मात्रा	मिलाये गये वनस्पति घी की मात्रा	मिलाये गये चूने की मात्रा
1	2	3	4	5	6

3 से 5 तक के कालमों का जोड़	निर्मित रंगदार नसवार की मात्रा	छीजन यदि कोई हो	विशेष	निर्धारिती अथवा उसके एजेंट के हस्ताक्षर
7	8	9	10	11

[अधिसूचना सं० 3/77/सी०स० V/4/30/32/76-के०उ०शु०-I]
सी० के० गोपालकृष्णन, समाहर्ता

Cochin, the 26th April, 1977

Central Excise

S.O. 2097.—In exercise of the powers vested in me under Rule 233 of Central Excise Rules, 1944 I direct that the manufactures of snuff falling under Central Excise Tariff item No. 4-II(6) in this Collectorate, shall hereafter maintain a separate daily account of raw materials, namely, (1) Tobacco, (2) Cigarette dust, and (3) Vegetable Product, used in the manufacture of Snuff in the form enclosed, and, as required under Rule 55 ibid, shall also funish a quarterly return of the said raw materials to the Central Excise Range Officer concerned, with copies to the Assistant Collector of Central Excise concerned, by the 10th of the month following the quarter to which it relates.

2. I further direct that the said manufacturers shall also maintain an account of intermediary product known as "Khamir" (mixture containing tobacco, cigarette dust, Vegetable ghee, lime and water) in the enclosed form.

DAILY ACCOUNT OF RAW MATERIALS FOR THE MANUFACTURE OF SNUFF

Name & Address of the factory:
Description of Raw Materials:

Date	Opening Balance	Invoice No. and date	Name of consigner	Quantity received	Total
1	2	3	4	5	6

Qty. used in the manufacture of		Qty. otherwise disposed of	Qty. wasted or destroyed	Closing balance
Snuff	Other goods	Nature of the disposal		
7	8	9	10	

Qty. of Snuff manufactured.	Qty. of other goods manufactured	Remarks	Signature of the assessee or his agent
12	13	14	15
Total for the month			

Note:—1. Separate Register should be maintained in respect of each raw material.

2. If any raw material is used for more than one excisable goods (falling under different tariff Items) or other goods manufactured, quantity used for each of such goods should be shown separately alongwith description of such goods by suitably subdividing column 5 & 8.

KHAMIR ACCOUNT REGISTER

Name & Address of the factory:

Date of mixing	Batch No.	Qty. of tobacco mixed	Qty. of cigarette dust mixed	Qty. of vegetable ghee mixed	Qty. of Lime mixed	Total of of Cols. 3 to 5
1	2	3	4	5	6	7

Qty. of coloured Snuff manufactured	Wastage, if any.	Remarks	Signature of the Assessee or his agent
8	9	10	11

[Notification No. 3/77/C. No. V/4/30/32/76-CX-I].
C.K. GOPALAKRISHNAN, Collector.

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 3 जून, 1977

का० आ० 2098—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 28 मार्च, 1979 तक दी बैंक आफ तंजावूर लिमिटेड, तंजावूर पर निम्नलिखित अचल सम्पत्ति के बारे में लागू नहीं होंगे :—

(i) तमिलनाडु के साउथ अर्काट जिले के चिदम्बरम्, थेरकुथल्ली ग्राम में 3 एकड़ 15 सेंट क्षेत्रफल की भूमि (क्रम सं० 71/2—0.72, 74/3—0.34; 77/1—0.75; 53/7—1.34) और

(ii) तमिलनाडु के साउथ अर्काट जिले के चिदम्बरम्, परमेश्वरनल्लूर ग्राम में 1 एकड़ 29 सेंट क्षेत्रफल की भूमि (क्रम सं० 106/3 —1.29)

[सं० 15(20)-बी०ओ० III/77]
जे० सी० राय, निदेशक

(Banking Wing)

New Delhi, the 3rd June, 1977

S.O. 2098.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act, shall not apply till 28th March, 1979 to the Bank of Thanjavur Ltd. Tanjore in respect of the following immovable properties.

(i) Land measuring 3 acres and 15 cents in Therkuvelli Village, Chidambaram, South Arcot District, Tamil Nadu (S. No. 74/2—0.72; 74/3—0.34; 77/1—0.75; 53/7—1.34) and

(ii) Land measuring 1 acre and 29 cents in Parameswaranallur Village, Chidambaram, South Arcot District, Tamil Nadu (S. No. 106/3—1.29).

[No. 15(20)-B.O.III/77]

J. C. ROY, Director

समाहर्ता का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

बंगलौर, 31 मार्च, 1977

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 2099.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग और इस कार्यालय की दिनांक 24-7-61 की अधिसूचना सं० 4/61 का अधिक्रमण और दिनांक 18-3-61 की अधिसूचना स० 1/61 में इस सीमा तक संशोधन करते हुए जहां तक कि यह नियम 145, खंड (ए) के प्रथम उपबन्ध से संबंधित है मैं, इस अधिसूचना द्वारा नीचे बताई गई सारणी में विनिर्दिष्ट पद तथा उससे ऊपर के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सारणी के स्तम्भ 2 में बताये गये नियम के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त तथा सारणी के स्तम्भ 3 में वर्णित सीमाओं के अधीन, समाहर्ता की शक्तियां प्रदान करता हूं।

सारणी

अधिकारी की श्रेणी	नियम	प्राधिकार का विस्तार और/या सीमायें
1	2	3
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक समाहर्ता	नियम 145 के तीसरे उपबन्ध का खंड (क)	फल्यू द्वारा सिझाये गये तम्बाकू के बारे में 2 वर्ष की सामान्य समय अवधि के अतिरिक्त एक वर्ष की अवधि और बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति।

[अधिसूचना स० 2/77/सी० सं० IV/8/1/77/बी० 2]

आर० एन० शुक्ल, समाहर्ता

Office of the Collector of Central Excise

Bangalore, the 31st March, 1977

CENTRAL EXCISE

S.O. 2099.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of the Central Excise Rules,1944, and in supersession of this office Notification No. 4/61 dated 24-7-61 and in modification of this office Notification No. 1/61 dated 18-3-61, in so far as it relates to Rule 145, Clause (a) first proviso of the said Rule, I hereby empower the C. Ex. officers of and above the rank specified in Column 1 of the table below to exercise within their respective jurisdiction, the powers of the Collector conferred by the provisions of the rule enumerated in Column 2, subject to thelimitations set out in column 3 of the table.

Table

Rank of Officer	Rule	Extent of authority and/or limitations
1	2	3
Assistant Collector of Central Excise	Clause (a) of third proviso of Rule 145	In the case of fluecured tobacco, to grant extension of time for one year in addition to the normal period of two years.

[Notification No. 2/77/C.No. IV/8/1/77-B.2].

R. N. SHUKLA, Collector

समाहर्तालय, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

कोचीन, 25 अप्रैल, 1977

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

का० आ० 2100.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा नीचे संलग्न सारणी के कालम 1 में विनिर्दिष्ट ओहदे के तथा उससे उच्च ओहदे के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में, सारणी के कालम 3 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, कालम 2 में दिये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता हूं।

सारणी

अधिकारी का ओहदा	नियम	प्राधिकार की सीमा और/अथवा परिसीमायें
1	2	3
सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	नियम 145 के तृतीय परन्तुक का खंड (क)	धुंआ देकर सिझाये गये तम्बाकू के मामले में, दो वर्ष की सामान्य अवधि के अलावा समय को एक वर्ष और बढ़ाने की मंजूरी देना।

इस अधिसूचना के जारी हो जाने से, इस समाहर्तालय के दिनांक 19-1-67 की अधिसूचना सं० 3/67 द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के नियम 145(क) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधीक्षकों को प्रत्यायोजित शक्तियां निरस्त हो जायेंगी। इस समाहर्तालय की दिनांक 19-1-67 की अधिसूचना सं० 3/67 द्वारा नियम 145(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक समाहर्ताओं को प्रत्यायोजित शक्तियां ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित हो जायेंगी।

[अधिसूचना सं० 2/77/सी० स० V/4/30/44/77-के० उ० शु०-I]

Collectorate of Customs and Central Excise

Cochin, the 25th April, 1977

CENTRAL EXCISE

S.O. 2100.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower het Central Excise Officers of and above the rank specified in

Col. 1 of the Table appended below to excise within their respective jurisdictions the powers of the Collector conferred by the provisions of the rules enumerated in Col. 2 subject to the conditions setout in Col. 3 of the Table.

Table

Rank of Officer	Rule	Extent of authority and/or limitations
(1)	(2)	(3)
Assistant Collector of Central Excise.	Clause (a) of third proviso of Rule 145.	In the case of flue cured tobacco, to grant extension of time for one year in addition to the normal period of two years.

The powers delegated under Rule 145(a) of the Central Excise Rules to the Superintendents of Central Excise as per this Collectorate Notification No. 3/67 dated 19-1-67 will stand cancelled with the issue of this notification. The powers delegated to the Assistant Collectors of Central Excise under Rule 145(b) as per this Collectorate Notification No. 3/67 dated 19-1-67 will stand modified to the extent indicated above.

[Notification No. 2/77/C. No. V/4/30/44/77-CX.I]

कार्यालय समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

कानपुर, 19 मार्च, 1977

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 2101:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 173 ओ के उक्त नियम (2) और नियम 185 के उप नियम (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों का, जैसा कि भारत सरकार की अधिसूचना सं० 5/77 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 29 जनवरी, 1977 में उल्लिखित है, निर्यात किए जाने वाले माल की पेटियों या उसके पैकटों के प्रस्तुत करने के संबंध में समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करता हूं।

[अधि० सं० 3/77/पत्र सं०V(8)(30)20-टेक/VI/77/13364]

Office of the Collector, Central Excise, Kanpur

Kanpur, the 19th March, 1977

CENTRAL EXCISES

S.O. 2101.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the Superintendents of Central Excise, to exercise the powers of Collector under sub-rule (2) of rule 173-C and sub-rule (i) of Rule 185 of Central Excise Rules, 1944, for presentation of packages or cases containing goods to be exported as laid down under Govt of India notification No. 5/77-CE, dated the 29th January, 1977.

[Notification No. 3/77/C. No. V (8) (30) 20-Tech/VI/77/13364].

कानपुर, 31 मई, 1977

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 2102:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के अध्याय VII-ए के० अधिकथित और भारत सरकार की अधिसूचना सं० 171/69 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दिनांक 21-6-69, 121/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दिनांक 28-5-70, 179/71 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 23-9-71, 195/71-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 12-11-71, 117/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 25-3-72 और 161/73-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 16-8-73 तथा 18/75-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1-3-75 के अन्तर्गत अधिसूचित स्वनिर्धारण पर निकासी प्रक्रिया के अन्तर्गत काम कर रहे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय कानपुर उत्पाद शुल्क लगने योग्य माल के सभी विनिर्माता बजट दिवस अर्थात् 16 जून, 1977 के पूर्व दिन के अपराह्न 6 बजे के तत्काल बाद अपने कारखाने के प्रभारी रेंज अधिकारी के पास (इस अधिसूचना के साथ लगे फार्म में) एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि उचित अधिकारी को भेजेंगे। इस घोषणा में :—

(क) विनिर्माता द्वारा उस तारीख अर्थात् 16-6-77 के शाम 6 बजे तक जारी किए गए अन्तिम गेट पास (जी० पी०-1 तथा जी० पी०-2) का नम्बर, और

(ख) उस तारीख अर्थात् 16 जून, 77 को शाम 6 बजे विनिर्माता के पास माल का इति शेष दर्ज किया जायेगा।

जहां कारखाने, रेंज मुख्यालय में ही अथवा उसके निकट स्थित हो; निर्धारिती उपर्युक्त घोषणा पत्र रेंज कार्यालय में दर्ज प्रस्तुत करेगा और उसकी लिखित पावती ले लेगा। अन्य निर्धारिती जो रेंज मुख्यालय से बहुत दूर हो वह अपने घोषणा पत्र उसी दिन दर्ज या तार से भेज देंगे।

परिशिष्ट

स्वनिर्धारण पर निकासी प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य कर रहे विनिर्माताओं द्वारा माल इत्यादि के सम्बन्ध में बजट के पूर्व दिवस की घोषणा

लाइसेंस धारक का नाम

लाइसेंस नम्बर

वस्तु (जिन्स)

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि अन्तिम गेट पास की क्रम सं० (प्रपत्र जी० पी०-1/जी० पी०-2) जो मैंने/हमने जारी किए हैं उनकी क्रम संख्या तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगने योग्य माल का इति शेष (स्थामित्व में उपलब्ध) जो मेरे/हमारे द्वारा विनिर्मित किया गया,* (दिनांक————————के अपराह्न 6 बजे) निम्नलिखित के अनुसार था :—

माल का नाम तथा टैरिफ मद संख्या	अन्तिम गेट पास (जी० पी०-1/जी० पी०-2) की क्रम संख्या	उत्पाद शुल्क लगने योग्य माल का आर० जी०-1 के अनुसार इति शेष।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है।

निर्धारिती अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान————

दिनांक————

*(संघ सरकार के वार्षिक बजट पेश किए जाने के एक दिन पूर्व)

अधीक्षक/सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क————को दिनांक ————का शाम————बजे दर्ज किया।

[अधि० सं० 7/77/पत्र सं० V(8)/73/बजट/77/25286]

कृ० श्री दिलीपसिंहजी, समाहर्ता

Kanpur, the 31st May, 1977

CENTRAL EXCISE

S.O. 2102.—In exercise of the powers conferred on me under rule 233 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby direct that all the manufacturers of excisable goods in

the Central Excise Collectorate, Kanpur working under self-Removal Procedure as laid down in Chapter VII-A of the Central Excise Rules, 1944 and notified under Government of India's Notification Nos. 171/69-CE dated 21-6-69, 121/70-CE dated 28-5-70, 179/71-CE, dated 23-9-71, 195/71-CE dated 12-11-71, 117/72-CE dated 25-3-72 and 161/73-CE dated 16-8-73 and 18/75 dated 1-3-75 shall file immediately after 6 P.M. on the day prior to the Budget day (i.e. the 16th June, 1977) a declaration with the Range Officer Incharge of their factory with a copy to the Proper Officer in the form appended to this Notification. The declaration shall contain :—

(a) The number of last Gate Pass (G.P. 1 and G.P. 2) issued by the manufacturer upto 6 P.M. on that date i.e. 16-6-77, and

(b) The closing balance of the stocks held by the manufacturer at 6 P.M. on that date i.e. 16th June, 1977.

2. The above declaration shall be submitted by the assessee by hand in the Range Officer against a written acknowledgement where the factories are located at or near the Range Hqrs. other assessees who may be situated far away from the hdqrs. of the Range Office may send their declaration either by hand or through telegram despatched on the same day.

APPENDIX

DECLARATION OF STOCK ETC. ON PRE-BUDGET DAY BY A MANUFACTURER WORKING UNDER SELF REMOVAL PROCEDURE

1. Name of the licensee :
2. Licence No. :
3. Commodity :

I/We hereby declare that the Serial Number of last Gate Pass (as) in form G.P. 1/G. P. 2 issue by me/us and the balance in hand of the excisable goods manufactured* by me/us on (date at 6 P.M.3 was/were as under :

Name of goods with Tariff Item No.	S. No. of last G.P 1./G.P.2.	Closing balance of excisable goods in stock as per R. G. 1.

Certified that the particulars given above are correct.

Signature of the assessee or his authorised agent.

Place :
Date :

*(One day prior to the presentation of annual budget of the Union Government)

Handed over to the Superintendent/Assistant Collectors of Central Excise on at

[Notification No 7/77/C. No V(8) 173/Budget/77/25286]

K. S. DILIPSINGHJI, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता

कलकत्ता, 4 अप्रैल, 1977

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 2103—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 15 और 16 के साथ नियम 233 के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय पश्चिम बंगाल की दिनांक 18 अगस्त, 1969 की अधिसूचना संख्या 2/69 और 3/69 में निम्नलिखित संशोधन के लिए आदेश देता हूं :—

(2) दिनांक 18-8-69 की अधिसूचना सं० 2/69 की संलग्न अनुसूची में क्रमांक 10 पर उल्लिखित "मुर्शिदाबाद" जिला के लिए निम्न प्रविष्टियां होंगी :—

'मुर्शिदाबाद निम्नलिखित गावों के क्षेत्रफल को छोड़कर :—

कशियाडांगा, चाईपाड़ा, बादलपाड़ा टेघरी कोयलपाड़ा बलिया, नयनडांगा, रामनगर, मथुरापुर, साहेबनगर, नूतनग्राम, टेघरीपाड़ा, कबीलपुर, गादी (सागरदीघी थाना के अन्तर्गत) हाथीबांधा, बहरा, हातपाड़ा, रघुनाथपुर, गंगाप्रसाद, इच्छाखाली, सम्मति नगर (रघुनाथगंज थाना के अन्तर्गत), डांगापाड़ा, राजारामपुर, सरपटिया, हरिपुर, झाउडांगा, चन्दीपुर, रेहनपुर, खमरपाड़ा, श्यामपुर, अतोसिया, पाइकपाड़ा, चल्कामाहरम, रामपल, नरेशगंज, रामनगर, सशपुर, गोसपुर (लालगोला थाना के अन्तर्गत) बांसगोला, दहपाड़ा (मुर्शिदाबाद थाना के अन्तर्गत) ।"

(3) दिनांक 18-8-69 की अधिसूचना सं० 3/69 की संलग्न अनुसूची में क्रमांक सं० 10 पर उल्लिखित मुर्शिदाबाद जिला के लिए निम्न प्रविष्टियां होंगी ।

"मुर्शिदाबाद निम्नलिखित गांवों के क्षेत्रफल को छोड़कर :—

कशियाडांगा, चाईपाड़ा, बादलपाड़ा, टेघरी कोयलपाड़ा, बलिया, नयनडांगा, रामनगर, मथुरापुर, साहेबनगर, नूतनग्राम, टेघरीपाड़ा, कबीलपुर, गादी (सागरदीघी थाना के अन्तर्गत), हाथीबांधा बहरा, हातपाड़ा, रघुनाथपुर गंगाप्रसाद, इच्छाखाली, सम्मतिनगर, (रघुनाथगंज थाना के अन्तर्गत) डांगापाड़ा, राजारामपुर, सरपाटिया, हरिपुर, झाउडांग, चन्दीपुर, रेहनपुर, खमरपाड़ा, श्यामपुर, अतोसिया, पाइकपाड़ा, चल्कामाहरम, रामपाल, नरेशगंज, रामनगर, सशपुर, गोसपुर, (लालगोला थाना के अन्तर्गत) बांसगोला, दहपाड़ा (मुर्शिदाबाद थाना के अन्तर्गत) ।'

[अधिसूचना सं० 4/के०उ०शु०/1977/सी०सं० iv(16) 2-सी०ई०/प०बं०/77]

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS : WEST BENGAL

Calcutta, the 4th April, 1977

CENTRAL EXCISE

S.O. 2103.—In exercise of the powers conferred on me under Rules 15 and 16 of the Central Excise Rules, 1944 read with rule 233 of the said Rules, I hereby order the following amendment in the Notification of the Collectorate of Central Excise & Customs, West Bengal, Nos. 2/69 and 3/69, both dated 18th August, 1969, namely :—

2. In the Schedule annexed to Notification No. 2/69 dated 18-8-69, for the Distict "Murshidabad" appearing at Sl. No. 10 thereof the following shall be substituted, namely :—

"Murshidabad excluding the areas comprised of the villages, namely :—

Kashiadanga, Chaipara, Badalpara, Teghari, Koyal Para, Balia, Nayandanga, Ramnagore, Mathurapur, Sahebnagore, Natungram, Tegharipara, Kabilpur, Gadi (under Sagardighi Police Station), Hathibandha, Bahara, Hatpara, Raghunathpur, Gangaprosad, Itchakhali, Sammatinagore (under Raghunathganj Police Station), Dangapara, Rajarampur, Sarpatia, Haripur, Jhaudanga, Chandipur, Rehanpur, Khamarpara, Shyampur, Atrosia, Paikpara, Chalkmaharam, Rampal, Narashgunj, Ramnagar, Sashpur, Goespur (under Lalgola Police Station), Bansgola, Dahapara (under Murshidabad Police Station)".

3. In the schedule annexed to Notification No. 3/69 dated 18-8-69, for the District Murshidabad appearing at Serial No. 10 thereof, the following shall be substituted, namely :—

"Murshidabad excluding the areas comprised of the villages, namely :—

Kashiadanga, Chaipara, Badalpara, Teghari, Koyal Para, Balia, Nayandanga, Ramnagore, Mathurapur, Sahebnagore, Natungram, Tegharipara, Kabilpur, Gadi (under Sagardighi Police Station), Hathibandha, Bahara, Hatpara, Raghunathpur, Gangaprosad, Itchakhali, Sammatinagore (under Raghunathganj Police Station), Dangapara, Rajarampur, Sarpatia, Haripur, Jhaudanga, Chandipur, Rehanpur, Khamarpara, Shyampur, Atrosia, Paikpara, Chalkmaharam, Rampal, Narashgunj, Ramnagar, Sashpur, Goespur (under Lalgola Police Station), Bansgola, Dahapara (under Murshidabad Police Station)".

[Notification No. 4/CE/1977/C. No. IV(16)-2-CE/WB/77]

कलकत्ता, 27 अप्रैल, 1977

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 2104.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 5 के अधीन प्राप्त कार्यक्षमता का उपयोग करते हुए मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक समाहर्ता को नियम 173 ए उक्तद में अनुसूचित उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं से संबंधित समाहर्ता के कार्यक्षमता जिसका उल्लेख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 ई में किया गया है, के उपयोग की अनुमति देता हूं जिसका प्रयोग वे अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में करेंगे।

[अधिसूचना सं० 6/के०उ०शु०/77/सी०सं० IV(16) 36-सी०ई०/डब्ल्यू०बी०/76]

Calcutta, the 27th April, 1977

CENTRAL EXCISE

S.O. 2104.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the Assistant Collector of Central Excise to exercise within their respective jurisdiction the powers of the "Collector", under Rule 173E of the Central Excise Rules, 1944 in respect of the excisable goods notified under Rule 173A ibid.

[Notification No 6/CE/77/C. No IV(16)-36 CE/WB/76]

कलकत्ता, 16 मई, 1977

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 2105.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 5 के द्वारा प्राप्त कार्यक्षमता का उपयोग करते हुए और इस समाहर्तालय की दिनांक 26/7/63 की अधिसूचना सं० 4/1963 का आंशिक संशोधन करते हुए मैं पश्चिम बंगाल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय के अधीक्षक को समाहर्ता के कार्यक्षमता, जिसका उल्लेख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 192 में किया गया है, को उपयोग करने की अनुमति इस शर्त पर दे रहा हूं कि वे इसका उपयोग अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में करेंगे और पर्यवेक्षण कर्मचारी के स्थापन व्यय का निर्धारण समाहर्ता द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं० 7/के०उ०शु०/77/सी०सं० IV(7) 1-सी०ई०/डब्ल्यू० बी०/76]

ए० के० भौमिक, समाहर्ता

Calcutta, the 16th May, 1977

CENTRAL EXCISE

S.O. 2105.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 and in partial modification of the Collectorate Notification No. 4/1963-CE dated 26-7-63, I hereby empower the Superintendent of Central Excise to exercise the power of the Collector of Central Excise under Rule 192 of the Central Excise Rules, 1944 in his respective jurisdiction of West Bengal Collectorate subject to the condition that cost of establishment of supervisory staff shall be fixed with reference to the conditions laid down by the Collector.

[Notification No. 7/CE/77-C. No. IV(7)1-CE/WB/76]

A. K. BHOWMIK, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, 20 मई, 1977

(केन्द्रीय उत्पाद)

का० आ० 2106—मैं, के०के० द्विवेदी, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चण्डीगढ़, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, चण्डीगढ़ के नीचे दी गई तालिका के कालम 2 में विनिर्दिष्ट श्रेणी में और उससे ऊपर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को कथित तालिका के कालम 3 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के अन्तर्गत समाहर्ता की शक्तियों को, उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उसी तालिका के कालम 4 में विहित सीमाओं के अन्तर्गत, प्रयोग में लाने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

दिनांक 24-12-1971 की अधिसूचना संख्या 5-के०उ०शु०/71 इस सीमा तक आशोधित समझा जाए।

तालिका

क्रम सं०	श्रेणी	नियम	सीमाएं
1	2	3	4
1.	अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	नियम 192	—

[अधिसूचना 3/के०उ०शु०/77/पत्राचार संख्या IV(16)तक०/77]

के० के० द्विवेदी, समाहर्ता

Central Excise Collectorate, Chandigarh

Chandigarh, the 20th May, 77

(CENTRAL EXCISE)

S.O. 2106.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I, K.K. Dwivedi, Collector of Central Excise Collectorate, Chandigarh, hereby authorise the Central Excise Officers of Central Excise Collectorate, Chandigarh of and above the rank specified in column (2) of the following table, to exercise, within their respective jurisdiction, the powers of "Collector" under the Central Excise Rules, 1944, mentioned in column No. 3 of the said table subject to the limitations set out in column No. (4) thereof:—

Notification No. 5-CE/71 dated 24-12-1971 be treated as modified to this extent.

TABLE

S.No.	Rank	Rule	Limitations
1	2	3	4
1.	Superintendents of Central Excise.	Rule 192	—

[Notification 3-CE/77/C. No. IV(16)9-TECH/77]

K. K. DWIVEDI, Collector

का० आ० 2107.—कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10 वर्ष में परिपक्व होने वाले 25 करोड़ रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) के उन बांडों पर देय ब्याज की दर 6 प्रतिशत (छः प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है, जो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा 15 से 17 जून, 1977 की अवधि में 99.00 रु० प्रतिशत पर जारी किये जायेंगे तथा उक्त रकम में 10 प्रतिशत अधिक तक पाप्त अंशदान रख लेने का अधिकार निगम को होगा।

[सं० एफ० 14-41/77-ए० सी०]

S.O. 2107.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 20 of the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963, (10 of 1963), the Central Government hereby fixes 6 per cent (six per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds of Rs. 25 crores (Rupees twenty five crores) to be issued at Rs. 99.00 per cent during the period 15th to 17th June, 1977 with the right to

retain subscription received upto 10 per cent in excess of the said amount, with a maturity period of 10 years by the Agricultural Refinance and Development Corporation.

[No. F. 14-44/77-AC]

नई दिल्ली, 7 जून, 1977

का० आ० 2108.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्ध 1 मार्च, 1977 से 28 फरवरी, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए शिवसागर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जोरहाट और कामरूप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोहाटी पर लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ०-8/3/77-ए० सी०]

वी० एन० बहादुर, उप सचिव

New Delhi, the 7th June, 1977

S.O. 2108.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Sibsagar District Central Cooperative Bank Limited, Jorhat and the Kamrup District Central Co-operative Bank Limited, Gauhati for a period from 1 March, 1977 to 28 February, 1978.

[No. F. 8/3/77-AC]

V. N. BAHADUR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 1977

का० आ० 2109.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री मोहम्मद फजल और श्री एम० नरसिंहम के स्थान पर क्रमशः औद्योगिक विकास विभाग के सचिव श्री एस० एस० मराठे और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव डा० मनमोहन सिंह को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक नामित करती है।

[सं० एफ०-10(73) आई० एफ०-I/77]

एम० के० वेंकटाचलम, विशेष कार्य अधिकारी

New Delhi, the 6th June, 1977

S.O. 2109.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India, Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri S. S. Marathe, Secretary, Department of Industrial Development and Dr. Manmohan Singh, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as the Directors of the Industrial Development Bank of India vice Shri Mohamed Fazal and Shri M. Narasimham respectively.

[No. F. 10(73) IF. I/77]

M. K. VENKATACHALAM, Officer on Special Duty

नई दिल्ली, 7 जून, 1977

का० आ० 2110.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री काशीनाथ चतुर्वेदी को हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 7 जून, 1977 से प्रारम्भ होकर 31 अक्टूबर, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें श्री काशीनाथ चतुर्वेदी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 1-1/77-आर० आर० बी०]

सी० आर० बिस्वास, उप सचिव

New Delhi, the 7th June, 1977

S.O. 2110.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Kashi Nath Chaturvedi as the Chairman of the Hardoi-Unnao Gramin Bank, Hardoi and specifies the period commencing on the 7th June, 1977 and ending with the 31st October, 1977 as the period for which the said Shri Kashi Nath Chaturvedi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-1/77-RRB]

C. R. BISWAS, Dy. Secy.

का० आ० 2111.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 27-9-1977 तक पूर्णत्रयीश विलासम बैंक लिमिटेड, त्रिपूर्णीथुरा पर अचल सम्पत्ति अर्थात केरल राज्य में त्रिचूर जिले के कल्लात्तुमकारा ग्राम के सर्वे सं० 176 और 177 के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(17)-बी० ओ० III/77]

S.O. 2111.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act, shall not apply till 27th September 1977 to the Sree Poornathrayeesa Vilasom Bank Ltd., Tripunithura, in respect of the immovable property, viz. survey nos. 176 and 177 at Kalettumkara Village in Trichur District in Kerala State.

[No. 15(17)-B.O.III/77]

का० आ० 2112.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध 31 मार्च, 1978 तक ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उनका सम्बन्ध इस बैंक द्वारा निम्नलिखित कम्पनियों के उनके नाम के सामने दिये गये तथा अपने पास रेहन रखे गये शेयरों से है:—

कम्पनी का नाम	रेहन रखने की तारीख	रखे शेयरों का चुकता मूल्य (लाख रुपयों में)
(1) जे० के० आटोमा बाइल्स प्राइवेट	24-11-1966	1.65
लिमिटेड	3-2-1967	0.25
(2) ग्लोब यूनाइटेड इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री	20-11-1960	8.80
कम्पनी लिमिटेड	16-2-1968	8.81
	16-3-1968	0.05

[सं० 15(18)-बी० ओ० III/77]

सं० भा० उमरानीकर, अवर सचिव

S.O. 2112.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply, till the 31st March 1978, to the Grindlays Bank Ltd., Calcutta, in respect of the shares held by it as pledge of the undernoted companies as shown against their names:—

Name of the company	Date of Lodgement	Paid-up value of shares held (in lakhs of Rs.)
(1) Jay Kay Automobiles Pvt. Ltd.	24-11-1966	1.65
	3-2-1967	0.25
(2) Globe United Engineering & Foundary Co. Ltd.	20-11-1967	8.80
	16-2-1968	8.81
	16-3-1968	0.05

[No. 15 (18)-B.O.III/77]
M.B. USGAONKAR, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 4 मई, 1977

का० आ० 2113—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख की उप-धारा (6) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 6 फरवरी 1973 के अपने आदेश सं० 5/फा० सं० 328/111/72-धन कर के आंशिक संशोधन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 6-2-1973 के उपर्युक्त आदेश के नीचे दी गई सारणी की क्रम सं० 15ए के सामने की स्तंभ (2) और (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

सारणी

(1)	(2)	(3)
15ए	आयकर आयुक्त कानपुर	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अभिग्रहण रेंज, कानपुर

2. यह आदेश 9 मई, 1977 से लागू होगा।

[सं० 33/77-फा० सं० 316/11/77-धन कर]
एच० एस० मंडल, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 4th May, 1977

S.O. 2113.—In exercise of the powers conferred by the Explanation to sub-section (6) of section 269F of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of their order No. 5/F. No. 328/111/72-WT dated 6th February, 1973, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that in the Table given below the aforesaid order dated 6-2-73 the entries under columns (2) & (3) against Sl No. 15A shall be substituted by the following:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
15A.	Commissioner of Income-tax, Kanpur.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Kanpur.

2. This order shall come into force with effect from 9-5-1977.

[No. 33/77-F. No. 316/44/77-WT]
H.N. MANDAL, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 मई, 1977

का० आ० 2114—सर्वश्री टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसस (टाटा सन्स प्रा० लि० का एक प्रभाग) बम्बई हाउस, सर होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई-400001 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत लाइसेंस के साथ संलग्न सूची के अनुसार एक बरोज़ बी० 6700 संगणक प्रणाली का आयात करने के लिए 71,59,228 रुपए मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1114646 दि० 20-9-75 130 लाख रुपए के निर्यात आभार के साथ प्रदान किया गया था।

2 उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति उनसे खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस में मात्र 2,38,892/- रुपए (26708 18 यू० एस० डालर) अप्रयुक्त शेष बचा हुआ था और लाइसेंस बम्बई सीमा शुल्क कार्यालय, बम्बई में पंजीकृत था।

3 अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1114646 दि० 20-9-75 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई या अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए। उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

4 लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[फा० संख्या 4/17/75-76/एम० एस०-2/216]
एम० के० बत्रा, उप-मुख्य नियंत्रक
कृते मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

Office of the Chief Controller of Imports & Exports

ORDER

New Delhi, the 16th May, 1977

S.O. 2114.—M/s. Tata Consultancy Service, (A Division of Tata Sons Pvt. Ltd.) Bombay House, Sir Homi Mody St. Bombay-400001 were granted import licence No. P/A/1414646 dated 20-9-75 for import of one Burroughs B. 6700 Computer system as per list attached to it valued at Rs. 71,59,228 under C.C.A. with an Export obligation of Rs. 130 lakhs.

2. They have requested for the issue of duplicate exchange purpose copy of the above said licence on the ground that the original exchange purpose copy has been lost or misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an unutilised balance of Rs 2,38,892 (US $26,708.18) only the licence was registered with Bombay Custom House, Bombay.

3. In support of their contention the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original exchange purpose copy of import licence No. P/A/1414646 dated 20-9-75 has been lost or misplaced and directs that a duplicate exchange control purpose copy of the said licence should be issued to the applicant. The original exchange control purpose copy of the said licence is cancelled.

4. The duplicate exchange control purpose copy of the licence is being issued separately.

[File No. 4/17/75-76/MI. II/216]

S. K. BATTA, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 1977

का० आ० 2115.—सर्वश्री तामिल नाडु लघु उद्योग निगम लि०-5 ग्रीक्स रोड, मद्रास-600006 को निम्नलिखित कच्चे माल जैसे :—

(1) कास्लाक्स-पी 1 बेरियम फेरिस्ट्रस पाउडर

(2) „ - „ 2 स्ट्रान्शियम फेरिट्रस ग्रौर

(3) परमाकोल के ग्रायात के लिए 2,17,838 रुपए के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सहित ग्रायात लाइसेंस संख्या जी/टी/2419640/एन/एम एन/62/एच/43-44, दिनांक 31-1-1977 दिया गया था । लाइसेंस के साथ वास्तविक उपयोक्ता सर्वश्री, ग्राग रोला मैजेटिक्स प्रा० लि० मैसूर बैंक बिल्डिंग 377, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मार्ग, मद्रास, 600001, तमिल नाडु के पक्ष में प्राधिकार पत्र दिया गया था । जैसा कि टी टी एन एस ग्राई डी सी लि० ने सूचना दी है कि उनसे ग्रायात लाइसेंस ग्रौर प्राधिकार पत्र डाक में खो गए हैं ग्रत. उन्होंने ग्रायात लाइसेंस की ग्रनुलिपि के साथ, वास्तविक उपयोक्ता के नाम में नये प्राधिकार पत्र की ग्रनुलिपि प्रति जारी करने के लिए ग्रावेदन किया है । उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मूल ग्रायात लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था ग्रौर इसलिए उसका उपयोग नहीं किया गया था ।

2 ग्रपने पूर्वोक्त कथन के समर्थन में टी एन एस ग्राई डी सी लि० 1976-77 की ग्रायात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक (परिशिष्ट 8 के निर्दिष्ट प्रपत्र में स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । उन्होंने वचन दिया है कि मूल ग्रायात लाइसेंस यदि पहले मिल गया तो प्राधिकार पत्र (दोनों प्रतियां) के साथ रिकार्ड के लिए इस कार्यालय को वापिस कर देंगे । मैं संतुष्ट हूं कि ग्रायात लाइसेंस संख्या जी/टी/2419640/एन/एम एन/62/एच/43-44 दिनांक 31-1-77 की मूल प्रति खो गई है ग्रौर ग्रादेश देता हूं कि वास्तविक उपयोक्ता के नाम में प्राधिकार-पत्र की ग्रनुलिपि के साथ ग्रायात लाइसेंस की ग्रनुलिपि (टी एन एस ग्राई डी सी लि०) को भेजी जाए । ग्रायात लाइसेंस की मूल प्रति को रद्द माना जाए ।

3. प्राधिकार-पत्र के साथ ग्रायात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के साथ ग्रनुलिपि प्रति ग्रलग से जारी की जा रही है ग्रौर टी एन एस ग्राई डी सी लि०, मद्रास को भेजी जा रही है ।

[सं० 56/ग्राई० एन० एस० ए०/76-76/बी एल एस/696]

एच० एल० बहल, उप-मुख्य नियंत्रक
कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 8th June, 1977

S.O. 2115.—The Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Limited, 5 Greams Road, Madras-600006 was granted Import Licence No. G/T/2419640/N/MN/62/H/43-44 dated 31-1-1977 with Exchange Control Purpose Copy for Rs. 2,17,838 c.i.f. only for import of the following raw materials, viz., (i) Caslox-P-1 Barium Ferrits Powder; (ii) Caslox P-2 Strondium Ferrits; and (iii) Permacol, with Letter of Authority in favour of the Actual User—M/s. Aag Rola Magetics Pvt. Ltd., Mysore Bank Building, 377, Netaji Subhash Chandra Bose Road, Madras-600001, Tamil Nadu. The TNSIDC Ltd. has now applied for a duplicate copy of Import Licence (with Exchange Control Purposes copy) along with fresh Letter of Authority, in duplicate, in favour of the Actual User, as these are reported to have been lost in the transit. They have confirmed that the original Import Licence was not registered with any Customs authorities and hence not utilised.

2. In support of the above contention the TNSIDC Ltd. has filed an affidavit on a stamped paper in the prescribed form as given in Appendix 8 of the ITC Hand Book of Rules and Procedure for 1976-77. They have undertaken to return the original Import Licence with Letter of Authority (both in duplicate) if traced later to this office for record. I am satisfied that the original Import Licence No. G/T/2419640/N/MN/62/H/43-44 dated 31-1-77 has been lost and direct that a duplicate import Licence with exchange Control Purposes Copy along with Letter of Authority in favour of the Actual User should be issued and forwarded to them (TNSIDC Ltd.). The original Import Licence may be treated as cancelled.

3 A duplicate Import Licence with Exchange Control Purposes Copy together with letter of Authority in duplicate is being issued separately and forwarded to the TNSIDC Ltd., Madras.

[No. 56/INSA/76-77/BLS/696]

H. L. BAHL, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

उद्योग मंत्रालय

(ग्रौद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1977

का० आ० 2116.—केन्द्रीय सरकार, पेटेन्ट ग्रधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय (ग्रौद्योगिक विकास विभाग) की ग्रधिसूचना सं० का० ग्रा० 2819, तारीख 29 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, ग्रर्थात् :—

उक्त ग्रधिसूचना में, "2 ग्रासाम" शीर्षक नीचे जोरहाट के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, ग्रर्थात् :—

"निदेशक,
प्रादेशिक ग्रनुसंधान प्रयोगशाला,
जोरहाट-6 (ग्रासाम) ।"

[फा० सं० 19(10)/77-पी पी एण्ड सी]

बी० एन० माथुर, ग्रवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi the 17th May, 1977

S.O.2116.—In exercise of the powers conferred by section 152 of the Patent Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following amendment

in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies, (Department of Industrial Development) No. S. O. 2819, dated the 29th July, 1975 namely :—

In the said notification under the heading "2. Assam" for the existing entry against Jorhat, the following entry shall be substituted namely :—

"The Director,
Regional Research Laboratory,
Jorhat-6, 'Assam'."

[F. No. 19(10)/77-PP&C]
B. N. MATHUR, Under Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th March, 1977

S.O. 2117/18FB/IDRA/77.—In exercise of the powers conferred by section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 826(F)/18FB/IDRA/76 dated 23rd December, 1976, namely :—

In the said Order, after the words "limits guaranteed", the words 'by the Government of Maharashtra and the amounts drawn" shall be inserted.

[F. No. 3/17 75-CUC]
R. P. PAHWA, Under Secy.

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई 1977

का० आ० 2118.—सरकारी परिसर (गैर-कानूनी कब्जा की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम 1 में उल्लिखित अधिकारी जो सरकारी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष का अधिकारी है, को सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त तालिका के कालम 2 में उल्लिखित सरकारी परिसर के मामले में अपने अधिकार सीमा में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा के अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये दायित्वों का पालन करेगा।

तालिका

अधिकारी का पद नाम	सरकारी परिसर की श्रेणी और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा
1	2
वाणिज्यिक प्रबंधक (निर्माण तथा सर्विसिंग) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर	कारखाने की इमारत क्षेत्र के अलावा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर के उपक्रम से संबंधित परिसर

[फ़ा० सं० 13(2)/77-एच० ई० पी०-1/एम० ए० एम० सी०]
आर० एन० कालिया, उप सचिव

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 30th May, 1977

S.O. 2128.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column 1 of the Table below being officer equivalent to the rank of gazetted officer of Government, to be as Estate Officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column 2 of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premise and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Commercial Manager (Erection & Servicing), Mining & Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur.	Premises belonging to the undertaking of Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur other than the area of the factory building.

[F.No.13(2)/77-HBP-I/MAMC]
R. N. KALIA, Dy. Secy.

नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1977-06-02

का० आ० 2119—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्हन) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी० एम०/एल०-5480 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म का नाम और स्वामित्व बदल जाने के कारण 1977-04-01 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-5480 1976-09-06	सर्वश्री नार्थ बंगाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, तीसरा मील, सेवोक रोड, डाकघर इक्तियासाल, जिला जलपाईगुड़ी-735101 इनका कार्यालय राय भवन, सेठ श्रीलाल मार्केट, डाकघर सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग (प० बंगाल) में है।	चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड के तख्ते मार्का. 'एनबीपी'	IS. 10-1970 चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)

[संख्या सी० एम० डी०/55.5480]
ए० बी० राव, उप महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 1977-06-02

S. O. 2119.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Insittution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-5480 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1977-02-01 due to change in the name of the firm and ownership.

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process governed by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-5480 1976-09-06	M/s. North Bengal Plywood Industries, 3rd Mile, Sevoke Road, P.O. Ektiasal Distt. Jalpaiguri-735101 having their office at Rai Bhawan, Seth Srilal Marhet P.O. Siliguri, Distt. Darjeeling (West Bengal)	Tea-chest Plywood Panels Brand : 'NBP'	IS : 10-1970 Specification for plywood tea-chests (Third Revision)

[No. CMD/55: 5480]
A. B. RAO, Dy. Director General

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 8 जून, 1977

का० आ० 2120.—यत केन्द्रीय सरकार की राय में भारत में खनिजों के सरक्षण और विकास के लिये यह आवश्यक है कि निम्नलिखित सारणी में उन विनिर्दिष्ट भूमियों में या के अन्तर्गत उपलब्ध खनिजों के सम्बन्ध में जिनके लिये उड़ीसा सरकार द्वारा खनन पट्टे मजूर किये गये है यथा सभव उपर्युक्त जानकारी एकत्र की जाये —

अत यत्र खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 67) के खंड 18 के उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार से परामर्श के बाद, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण को कथित सारणी में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में उक्त जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी आवश्यक हो, एतद्द्वारा, व्यापक खोज कार्य के लिये प्राधिकृत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	स्थान/ग्राम	मुकिन्दा पट्टी: तहसील और जिला	पट्टाधारी	क्षेत्र हेक्टरों में
1	2	3	4	5
1	भीमटगर	मुकिन्दा (कटक)	मै० टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी	1100
2	कालिआपानी	मुकिन्दा (कटक)	मै० उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि०	971

1	2	3	4	5
3.	भीमटंगर खान और भतत्व निदेशालय का (पहले टाटा आयरन एंड कम्पनी का)	सुकिन्दा (कटक)	भूतत्व और खनन निदेशालय, उड़ीसा	454
4	सुकरंगी	सुकिन्दा (कटक)	भूतत्व और खनन निदेशालय, उड़ीसा	446
5	कामरदा	सुकिन्दा (कटक)	श्री बी० सी० मोहन्ती	107
6	सरूआबिल	सुकिन्दा (कटक)	मै० मिश्री लाल माइन्स प्राइवट लिमिटेड	259
		नौसाही पट्टी		
7	बौला	आनन्दपुर जिला क्योंझर	मै० एफ० एसी० ओ० आर०	187
8.	नौसाही (न्यु)	आनन्द पुर जिला क्योंझर	मै० सिराजुद्दीन एंड कं०	41
9.	नौसाही (पुराना)	आनन्दपुर जिला क्योंझर	मै० सिराजुद्दीन एंड क०	41

[फाइल संख्या 1(1)/77-खान-6/एम० वी०]

टी० आर० विश्वनाथन, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Mines)

New Delhi the 8th June, 1977

S. O. 2120.—Whereas the Central Government is of opinion that for the conservation and development of minerals in India, it is necessary to collect as precise information as possible with regard to any mineral available in or under the lands specified in the Table below in relation to which mining leases have been granted by the Government of Orissa;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18A of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government after consultation with the Government of Orissa, hereby authorises the Geological Survey of India to carry out such detailed investigations for the purpose of obtaining such information as may be necessary in relation to the lands specified in the said Table.

TABLE

S. No.	Location/ Village	Tehsil and District	Lessee	Area in Hectares
1	2	3	4	5
		Sukinda Belt		
1.	Bhimtangar	Sukinda (Cuttack)	Messrs Tata Iron and Steel Company.	1400
2.	Kaliapani	Sukinda (Cuttack)	Messrs Orissa Mining Corporation Limited.	971
3.	Bhimtangar of Directorate of Mines and Geology (Formerly of TISCO)	Sukinda (Cuttack)	Directorate of Geology and Mining, Orissa.	454
4.	Sukarangi	Sukinda (Cuttack)	Directorate of Geology and Mining, Orissa.	446
5.	Kamarda	Sukinda (Cuttack)	Shri B.C. Mohanty.	107
6.	Saruabil	Sukinda (Cuttack)	Messrs Misrilal Mines Private Limited	259
		Nausahi Belt		
7.	Boula	Anandpur, District Keonjhar.	Messrs FACOR	187
8.	Nausahi (New)	Anandpur, District, Keonjhar.	Messrs Serajuddin and Company.	41
9.	Nausahi (Old)	Anandpur, District, Keonjhar.	Messrs Serajuddin and Company	41

[File No. 1(1)/77-MVI/MV]

T. R. VISWANATHAN, Dy. Secy

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जून, 1977

का० आ० 2121.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन० के० ए० जेड० से डब्ल्यू० एच० आई० एन० के०-25 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख-भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एन० के० ए० जेड० से डब्ल्यू० एच० आई० एन० के०-25 तक भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करना ।

राज्य गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका वीरमगम

गाव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
तेलावी	191	0	02	40
	190	0	13	20
	कार्ट-ट्रैक	0	00	84
	214	0	25	32
	212/1	0	07	20
	209/4/4	0	13	20
	210/2	0	13	20
	209/4/1	0	15	24
	कार्ट-ट्रैक	0	00	60
	226/4/1	0	43	20
	226/3/1	0	10	10
	226/5/11	0	12	60
	226/2/1	0	02	10
	225/4	0	03	60

[सं० 12016/2/77-प्रोडक्शन I]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 18th June, 1977

S.O. 2121.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. NKAZ to WHI NK-25 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of used in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintainance Division, Makarpura Road, Vadodara-9 ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of right of user for well no. NKAZ to WHINK-25.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Telavi	191	0	02	40
	190	0	13	20
	Cart-track	0	00	84
	214	0	25	32
	212/1	0	07	20
	209/4/4	0	13	20
	210/2	0	13	20
	209/4/1	0	15	24
	Cart-track	0	00	60
	226/4/1	0	43	20
	226/3/1	0	10	40
	226/5/11	0	12	60
	226/2/1	0	02	40
	225/4	0	03	60

[No. 12016/2/77-Prod. I]

का० आ० 2122.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन० के० बी० क्यू० से डब्ल्यू० एच० आई० कादी-25 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० एन० के० बी० क्यू० से डब्ल्यू० एच० आई० कादी-25 तक भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करना ।

राज्य गुजरात जिला अहमदाबाद तालुका वीरगमन

गाव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टयर	ए आर ई	सेन्टीयर
तेलावी	236/5/पी	0	69	84
	226/5/3-पी०	0	03	60

[सं० 12016/2/77-प्रोडक्शन II]

S.O. 2122.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. NKBQ to WHI Kadi 25 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whether it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquision of right of user from Well No. Nkbq to W.H.I. Kadi-25

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Telavi	236/5/P	0	69	84
	226/5/3-P	0	03	60

[No. 12016/2/77-Prod.II]

का० आ० 2123.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० 9 (जी० जी० एस०-1) से मतवान-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण तथा अनुरक्षण प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० 9 (जी० जी० एस०-1) से मोतवान-1 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करना

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
1	2	2	4	5
सारथान	68	0	07	28
	70/4	0	05	72
	70/5	0	04	94
	70/6	0	07	93
	70/7	0	04	55
	70/8	0	08	84
	70/9	0	18	07
	70/10	0	15	60
सारथान—जारी	98/2	0	03	12
	105	0	01	69
मोतवान	63	0	03	64
	71/1	0	14	17
	70/1+2	0	17	42
	68/1	0	08	84
	68/2/1	0	05	20
	68/2/2	0	06	50
	65/1 बी	0	02	60
	65/2 ए	0	26	00
	54	0	06	89
	55	0	15	21
	56/1	0	14	43
	58/1	0	06	76
	58/2	0	14	30
	50/12	0	03	12
	50/14	0	09	75

[सं० 12016/3/77-प्रोडक्शन]

टी० पी० सुब्रह्मनियन, अवर सचिव

S.O. 2123.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 9 (GGS-I) to Motwan-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Acquisition of R.O.U. for laying pipelines from Well No. 9 (GGS-1) to Motwan-1

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar

Villages	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Sarthan	68	0	07	28
	70/4	0	05	72
	70/5	0	04	94
	70/6	0	07	93
	70/7	0	04	55
	70/8	0	08	84
	70/9	0	18	07
	70/10	0	15	60
	98/2	0	03	12
	105	0	01	69

1	2	3	4	5
Motwan	63	0	03	64
	71/1	0	14	17
	70/1+2	0	17	42
	68/1	0	08	84
	68/2/1	0	05	20
	68/2/2	0	06	50
	65/1B	0	02	60
	65/2A	0	26	00
	54	0	06	89
	55	0	15	21
	56/1	0	14	43
	58/1	0	06	76
	58/2	0	14	30
	50/12	0	03	12
	50/14	0	09	75

[No. 12016/3/77-Prod.]

T. P. SUBRAHMANYAN Under Secy.

कृषि व सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1977

का० आ० 2124.—पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5 की उप धारा (1) के उपबन्धो के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पशु कल्याण मण्डल का सदस्य मनोनीत करती है :—

सदस्य	तारीख	अवधि	श्रेणी
1. श्रीमती रुकमणी देवी अरुणडेल	18-3-77	3 वर्ष	धारा 5(1) (एच) केन्द्रीय सरकार की नामजद सदस्या।
2. श्री जयंतीलाल नारादियन मांकर	18-3-77	3 वर्ष	धारा (5)1 (एफ) बम्बई ह्यूमनीटेरियन लीग, बम्बई के प्रतिनिधि।
3. श्री जी० आर० राजगोपाल	18-3-77	3 वर्ष	धारा 5(1) (एच) केन्द्रीय सरकार के नामजद सदस्य।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्रीमती रुकमणी देवी अरुणडेल को उपर बताए गए अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुपालन में पशु कल्याण मण्डल की अध्यक्षा मनोनीत करती है।

[सं० 14-27/73-एल० डी०-I]

पी० जी० रामरखियानी, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 11th April, 1977

S. O. 2124.—Under provisions of Sub-section (1) of Section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby nominates the following persons to be the member of the Animal Welfare Board for a further period of three years, as shown against each member:—

Member	Date	Period	Category
1. Smt. Rukmini Devi Arundale	18-3-77	3 years	Section 5(1) (h)—Nominee of the Central Government.
2. Shri Jayantilal Naradial Mankar.	18-3-77	3 years	Section 5(1)(f)—Representative of Bombay Humanitarian League, Bombay.
3. Shri G.R. Rajagopaul.	18-3-77	3 years	Section 5(1)(h)—Nominee of the Central Government.

2. The Central Government hereby nominates Smt. Rukmini Devi Arundale to be the Chairman of the Animal Welfare Board in pursuance of sub-section (3) of Section 5 of the said Act.

[No. 14-27/73-LD I]

P. G. RAMRAKHIANI, Dy. Secy.

(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 1977

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (निवास स्थानो का आबंटन) पुनरीक्षण नियम, 1977

का० आ० 2125.—मूल नियमों के नियम 45 के अनुसरण में, राष्ट्रपति अनुपूरक नियमो में, जो भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त विभाग के पत्र सं० 104-सी० एम० आर० तारीख 4 फरवरी, 1922 के साथ जारी किए गए थे, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

उक्त नियमो के भाग 8 मे, खण्ड 26-ण और उसके नीचे के शीर्षक और नियमों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड, शीर्षक और नियम रखे जायेंगे; अर्थात् :—

"खण्ड 26 ण—भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान (निवास स्थानों का आबंटन) नियम, 1977—

अ० नि० 317-ण-1 : संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (निवास स्थानो का आबंटन) नियम, 1977 है।

(2) ये सरकार के और भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान के परिसरों के भीतर स्थित निवासी भवनो को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अ० नि० 317 ण-2 : इन नियमो में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "आबंटन" से इन नियमो के उपबन्धों के अनुसार किसी निवास स्थान को अधिभोग में रखने के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है,

(ख) "आबंटन" वर्ष से प्रथम जनवरी को आरम्भ होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है, जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसकी ओर से कार्य करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(घ) "पात्र कार्यालय" से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और उसके वे उप-केन्द्र अभिप्रेत है जिनके कर्मचारिवृन्द को निदेशक द्वारा इन नियमों के अधीन वास सुविधा के लिए पात्र घोषित किया गया है;

(ङ) "उपलब्धियां" से मूल नियम 45 ग में यथा परिभाषित उपलब्धियां अभिप्रेत है, किन्तु इनके अन्तर्गत प्रतिकरात्मक भत्ते सम्मिलित नहीं हैं,

स्पष्टीकरण :—किसी निलम्बित अधिकारी के मामले में उसके द्वारा उस आबंटन वर्ष के जिसमें वह निलम्बित किया गया है, प्रथम दिन को, अथवा यदि वह आबंटन वर्ष के प्रथम दिन को निलम्बित रहा है तो उसके द्वारा उस तारीख से ठीक पहले, ली गई 'उपलब्धियां' मानी जाएंगी ।

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, यथास्थिति पत्नी, या पति और संतान, सौतेली संतान, वैध रूप से दत्तक ली गई संतान, माता पिता, भाई अथवा बहनें जो सामान्यत: अधिकारी के साथ निवास करते है और उस पर आश्रित है;

(छ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "संस्थान" से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(झ) "अनुज्ञप्ति" फीस से इन नियमों के अधीन आबंटित निवास स्थान के सम्बन्ध में, मूल नियमों के उपबन्धों के अनुसार मासिक रूप से सन्देय धनराशि अभिप्रेत है;

(ञ) इन नियमों के अधीन निवास स्थानों के आबंटन के लिए किसी अधिकारी की "पूर्विकता तारीख" से वह पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जिससे वह संस्थान के अधीन किसी पद पर निरन्तर अहैक नियुक्ति जिसमें प्रतिनियुक्ति, अन्यत्र सेवा, प्रशिक्षण या छुट्टी आदि पर प्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि सम्मिलित है, धारण करता है;

परन्तु अ० नि० 317-ण-5 के उपबन्धों के अधीन निवास स्थान के टाइप के लिए पात्रता का अवधारण उन उपलब्धियों पर किया जाएगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाने वाले आबंटन वर्ष की प्रथम तारीख को उसकी हो;

परन्तु यह और कि टाइप V और टाइप VI के लिए पात्र अधिकारी जिस टाइप के लिए वे पात्र हैं उसके ठीक नीचे के टाइप के अर्थात् क्रमश: टाइप IV और टाइप V के, निवास स्थान के आबंटन के लिए भी पात्र होंगे ।

परन्तु यह और भी कि जहां दो या अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही हो वहां उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की राशि से अवधारित की जाएगी अर्थात् अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी, और जहां उपलब्धियां एक ही है वहां ज्येष्ठता सेवा काल की दीर्घता के अनुसार की जाएगी ;

(ट) "निवास स्थान" से ऐसा निवास स्थान अभिप्रेत है जो तत्समय निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में हो;

(ठ) "उप-पट्टे पर देना" के अन्तर्गत किसी आबंटिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, उस अन्य व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर अथवा उसके बिना, वास सुविधा का सहभोग करना भी है;

स्पष्टीकरण :—आबंटिती द्वारा अपने निकट के सम्बन्धियों के साथ वास सुविधा का सहभोग उपपट्टे पर देना नहीं समझा जाएगा।

(ड) "स्थानान्तरण" से नई दिल्ली स्थित संस्थान के कार्यालय से नई दिल्ली के बाहर संस्थान के किसी अन्य कार्यालय को, या विपरीततः, स्थानान्तरण अभिप्रेत है और इसमें किसी आत्र कार्यालय या संगठन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति अभिप्रेत है;

(ढ) "अस्थायी स्थानान्तरण" से वह स्थानान्तरण अभिप्रेत है, जिसमें चार मास से अनधिक की अनुपस्थिति हो;

(ण) किसी अधिकारी के संबंध में "टाइप" से निवास स्थान का वह टाइप अभिप्रेत है, जिसका वह अनु० नि० 317-ण-5 के अधीन पात्र है।

अनु० नि० 317-ण-3 : जिन अधिकारियों के अपने मकान हैं वे इन नियमों के अधीन आबंटन के लिए अपात्र होंगे :—कोई अधिकारी इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह नई दिल्ली/दिल्ली की नगरपालिका सीमाओं के भीतर अपने स्वयं के नाम में या अपनी—पत्नी या पति के नाम में या अपने किसी आश्रित के नाम में किसी मकान या उसके भाग का स्वामी है।

अनु० नि० 317-ण-4 : पति और पत्नी का, आबंटन—एक दूसरे से विवाहित अधिकारियों के मामले में पात्रता :—

(1) जहां पति और पत्नी दोनों ही संस्थान के अधीन कर्मचारी है वहां इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आबंटन के लिये दोनों अधिकारियों में से प्रत्येक के हक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

(2) किसी अधिकारी को, जिसकी यथास्थिति, पत्नी या पति को पहले ही कोई निवास स्थान आबंटित किया जा चुका है, इन नियमों के अधीन कोई निवास स्थान तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा निवास स्थान अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता :

परन्तु यह उपनियम वहां लागू नहीं होगा, जहां पति पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में अलग अलग निवास कर रहे हैं।

(3) जहां दो अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन पृथक रूप से आबंटित निवास स्थानों के अधिभोगी है, एक दूसरे से विवाह कर लें जहां वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से एक अभ्यर्पित करेंगे।

(4) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण, उपनियम (2) की अपेक्षानुसार, नहीं किया जाता है तो निम्नतर टाइप के निवास स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द हो गया समझा जाएगा और यदि निवासस्थान एक ही टाइप के है तो निदेशक के विनिश्चयानुसार उनमें से एक का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द हो गया समझा जाएगा।

(5) उप नियम (1) से (4) तक में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यदि, यथास्थिति, पत्नी या पति को, जो इन नियमों के अधीन किसी निवास स्थान का आबंटिती है, ऐसे पूल से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते एक ही, स्टेशन पर बाद में कोई वास-सुविधा आबंटित कर दी जाती है तो, यथास्थिति, पत्नी या पति ऐसे आबंटन के एक मास के भीतर इन निवास स्थानों में से कोई एक अभ्यर्पित कर देगा,

परन्तु यह खण्ड वहां लागू नहीं होगा जहां पति-पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में, अलग अलग रह रहे है;

(ख) जहां दो अधिकारी, जो एक ही स्टेशन पर ऐसे पृथक निवास-स्थानों के अधिभोगी है, जिनमें से एक निवास-स्थान इन नियमों के अधीन आबंटित किया गया हो और दूसरा ऐसे

पूल से, जिसमें ये नियम लागू नहीं होते, एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं वहां उनमें से कोई भी एक अधिकारी ऐसे विवाह के एक मास के भीतर उस निवास-स्थानों में से किसी एक को अभ्यर्पित कर देगा;

(ग) यदि निवास-स्थान का अभ्यर्पण, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता है तो इन नियमों के अधीन किया गया निवास स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द कर दिया गया समझा जाएगा।

अ० नि०-317-ण-5 : निवास स्थानों का वर्गीकरण—इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अधिकारी नीचे की सारणी में दर्शित टाइप के निवास-स्थान के आबंटन का पात्र होगा :

सारणी

निवास-स्थान का टाइप	अधिकारी को जिस आबंटन वर्ष में आबंटन किया जाए उसके प्रथम दिन उसकी मासिक उपलब्धियों के आधार पर उसका प्रवर्ग	निवास-स्थान
1	2	3
I.	260 रुपए प्रतिमास से कम	वर्ग IV टाइप I
II.	500 रुपए से कम किन्तु 260 रुपए अन्यून प्रतिमास	टाइप II-ए, II-बी, एच और ई
III.	700 रुपए से कम किन्तु 500 रुपए से अन्यून प्रतिमास	टाइप डी
IV.	1000 रुपए से कम किन्तु 700 रुपए से अन्यून प्रतिमास	डी-II फ्लैटस और सी टाइप
V.	1650 रुपए से कम किन्तु 1000 रुपए से अन्यून प्रतिमास	टाइप सी
VI.	2500 रुपए से कम किन्तु 1650 रुपए से अन्यून प्रतिमास	टाइप बी
VII.	निदेशक	टाइप बी।

निवास स्थानों का वर्गीकरण और आरक्षण वैसा ही होगा जैसा इन नियमों से उपाबद्ध क्रमशः अनुसूची 1 और 2 में दिया गया है। उस पद के छोड़ने पर, जिसके लिए निवास स्थान निश्चित किया गया है, आरक्षित क्वार्टर के निवास स्थान को रखे रहने के लिए अनुज्ञात अवधि दो मास होगी जिसके अवसान पर अधिकारी निवास-स्थान खाली कर देगा।

अ० नि०-317-ण-6 : आबंटन के लिये आवेदन :

(1) प्रत्येक सरकारी अधिकारी, जो इन नियमों के अधीन सरकारी आवास सुविधा का अधिभोगी है, अपना आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख तक भेजेगा जो निदेशक, द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) उन अधिकारियों की दशा में, जो इन नियमों के अधीन आवास सुविधा, के अधिभोगी नहीं हैं, निदेशक ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति से तथा ऐसे तारीख से पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(3) वह अधिकारी, जो प्रथम नियुक्ति पर या स्थानान्तरण पर स्थान में पदभार ग्रहण करता है, अपना आवेदन पदभार ग्रहण करने के एक मास के भीतर निदेशक को भेज सकेगा।

(4) किसी कैलेण्डर मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व उपनियम (3) के अधीन प्राप्त आवेदनों पर ही, उत्तरवर्ती मास में आबंटन के लिए, विचार किया जाएगा।

अ० नि० 317-ण-7 : निवास-स्थानों का आबन्टन और प्रस्थापनाएं

(1) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी निवास-स्थान के खाली होने पर, वह निदेशक द्वारा अधिमानतः उस आवेदन को आबंटित किया जाएगा, जो अ० नि० 317-ण-16 के उपबन्धो के अधीन उस टाइप की वास-सुविधा में परिवर्तन चाहता है और यदि वह उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो तो, उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस टाइप की आवास सुविधा नहीं है और जिसकी उस टाइप के निवास-स्थान के लिए पूर्विकता तारीख सबसे पहले की हो। यह आबंटन निम्नलिखित शर्तों पर होगा, अर्थात :—

(i) निदेशक उस टाइप से उच्चतर टाइप के निवास-स्थान का आबंटन नहीं करेगा जिसके लिए आवेदक अ० नि० 316-ण-5 के अधीन पात्र है।

(ii) निदेशक किसी आवेदक को इस बात के लिए विवश नहीं करेगा कि वह जिस टाइप के लिए अ० नि० 417-ण-5 के अधीन पात्र है उससे निम्नतर टाइप के निवास-स्थान को स्वीकार करे।

(iii) निदेशक, किसी निम्नतर प्रवर्ग के निवास-स्थान के आबंटन के लिए किसी आवेदक की प्रार्थना प्राप्त होने पर, उसे ऐसे टाइप में ठीक निम्नतर निवास-स्थान आबंटित कर सकेगा, जिसके लिए आवेदक अ० नि० 317-ण-5 के अधीन अपनी पूर्विकता तारीख के आधार पर पात्र है।

(2) यदि किसी अधिकारी अधिभोग में के निवास-स्थान को खाली कराना अपेक्षित है तो, निदेशक उस अधिकारी का वर्तमान आबंटन रद्द कर सकेगा और उसे उसी टाइप का आनुकल्पी निवास-स्थान आबंटित कर सकता है या, आवश्यकता की स्थिति में, उसे अधिकारी के अधिभोग में के निवास-स्थान के टाइप के ठीक निम्नतर टाइप का आनुकल्पी निवास-स्थान आबंटित कर सकता है।

(3) खाली निवास-स्थान को, उपनियम (1) के अधीन उसे किसी अधिकारी से आबंटित किए जाने के अतिरिक्त, अन्य पात्र अधिकारियों को उनकी पूर्विकता तारीखो के क्रम मे साथ ही साथ दिए जाने की प्रस्थापना की जा सकती है।

अनु० नि० 317-ण-8 : पारी-बाह्य आबंटन-अनु० नि० 317-ण-7 के उपबन्धों के होते हुए भी, निदेशक द्वारा किसी निवास-स्थान का आबंटन किसी अधिकारी को पारी-बाह्य तौर पर, उसकी अपनी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी के आधार पर, यदि आवश्यक समझा जाए तो किसी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से, जो सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी के रैंक से कम का न हो, किया जा सकेगा। ऐसी दशाओं मे आबंटन के लिए पूर्विकता-तारीख वह तारीख होगी जिसको अधिकारी का पारी-बाह्य आबंटन का आवेदन निदेशक को प्राप्त होता है।

अनु० नि० 317-ण-9 : आबंटन या प्रस्थापना का स्वीकार न किया जाना, अथवा आबंटित निवास-स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अधिभोग में न लेना :—

(1) यदि कोई अधिकारी, किसी निवास स्थान का आबंटन आबंटन-पत्र की जारी किए जाने की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है अथवा स्वीकार करने के बाद भी ऐसी तारीख से आठ दिन के भीतर उस निवास-स्थान का कब्जा नहीं लेता है तो, वह आबंटन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा।

(2) यदि किसी अधिकारी को, जिसके अधिभोग में किसी निम्नतर टाइप का निवास-स्थान है, ऐसे टाइप का निवास-स्थान आबंटित या प्रस्थापित किया गया है जिसके लिए वह अ० नि० 317—ण—5 के अधीन पात्र है या जिसके लिए उसने अनु० नि० 317—ण—7 के उपनियम (1) के खण्ड (iii) मे आवेदन किया है तो उसे, उक्त आबंटन की प्रस्थापना को अस्वीकार कर देने पर, पूर्वतन आबंटित निवास-स्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) ऐसा अधिकारी उस आबंटन की बची हुई अवधि तक, जिसमें उच्चतर वर्ग की वास-सुविधा के आबंटन या प्रस्थापना को अस्वीकार कर दिया था, दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा;

(ख) वर्तमान निवास-स्थान रखे रहने के दौरान उस पर वही अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी जो उसे मू० नि० 45-क के अधीन इस प्रकार आबंटित या प्रस्थापित निवास-स्थान के लिए, अथवा वह अनुज्ञप्ति फीस, जो उस निवास-स्थान के लिए देय है जो पहले ही उसके अधिभोग में है, दोनों में से जो भी अधिक हो, संदत्त करनी पड़ती। यदि किसी अधिकारी ने, जिसके अधिभोग में किसी निम्नतर टाइप का निवास-स्थान है, अ०नि० 317-ण-6 के अधीन किए गए अपने आवेदन मे उस निवास स्थान को रखे रहने का निश्चय किया है तो इस खण्ड में के उपबन्ध उस अवधि के दौरान जिसके लिए उसने ऐसा निश्चय किया है, उसे लागू नहीं होंगे।

अनु० नि० 317—ण—10 आबंटन प्रभावी रहने की अवधि और तत्पश्चात् कब्जा बनाए रखने की रियायती अवधि :—

(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है और तब तक प्रभावी बना रहेगा जब तक कि :—

(क) अधिकारी के दिल्ली स्थित संस्थान में कर्त्तव्यारूढ़ न रह जाने के पश्चात् वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उपखण्ड (2) के अधीन अनुज्ञेय है;

(ख) आबंटन निदेशक द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता;

(ग) आबंटन अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता; या

(घ) अधिकारी के अधिभोग में निवास-स्थान नहीं रह जाता।

(2) अधिकारी को आबंटित निवास-स्थान, उपनियम (3) के अधीन, निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के घटने पर उस अवधि पर्यन्त रखा जा सकता है जो उस सारणी के स्तम्भ (2) मे तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, परन्तु यह तब जब कि वह निवास-स्थान उस अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपभोग के लिए अपेक्षित हो।

सारणी

घटनाएं	निवास-स्थान अपने पास रखे रहने की अनुज्ञेय अवधि
1	2
(i) पदत्याग, पदच्युति, या सेवा से हटाया जाना, सेवा का पर्यवसान अथवा बिना अनुज्ञा के अप्राधिकृत अनुपस्थिति	एक मास।
(ii) सेवा-निवृत्ति या सेवांत छुट्टी	2 मास।
(iii) आबंटिती की मृत्यु	4 मास।
(iv) दिल्ली से बाहर किसी स्थान के लिये स्थानान्तरण	2 मास।
(v) दिल्ली में किसी अपाव कार्यालय की स्थानान्तरण	2 मास।
(vi) भारत में अन्यत्र सेवा में जाने पर	2 मास।
(vii) भारत मे अस्थायी स्थानान्तरण या भारत के बाहर के के किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण	4 मास।
(viii) छुट्टी (जो निवृत्ति-पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवांत छुट्टी चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)	छुट्टी, की अवधि पर्यन्त, किन्तु वह 1 मास से अधिक न हो।
(ix) निवृत्ति-पूर्व छुट्टी या मूल नियम 86 के अधीन ली गई अस्वीकृत छुट्टी, अथवा संस्थान के ऐसे कर्मचारियों को दी गई उपार्जित छुट्टी जो मू० नि० 56 के अधीन सेवा निवृत्त होते है।	पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त, किन्तु 4 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जिसमें निवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि भी सम्मिलित है।
(x) भारत से बाहर अध्ययनार्थ छुट्टी या प्रतिनियुक्ति।	छुट्टी की अवधि पर्यन्त, किन्तु वह 6 मास से अधिक न हो।
(xi) भारत में अध्ययनार्थ छुट्टी	छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु वह 6 मास से अधिक न हो।
(xii) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त।
(xiii) प्रशिक्षण पर जाने पर	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि पर्यन्त परन्तु यह तब जब कि यह संस्थान द्वारा प्रायोजित हो।

स्पष्टीकरण 1 :—जब भारत में स्थानान्तरण होने या अन्यत्र-सेवा में जाने पर किसी अधिकारी को कोई छुट्टी मंजूर की जाती है और वह नए कार्यालय मे पदभार ग्रहण करने से पूर्व उस छुट्टी का उपभोग करता है तो उस मद (iv), (v), (vi) और (vii) के सामने दर्शित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अधिक हो, निवास-स्थान रखे रहने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण 2 :—जब भारत मे स्थानान्तरण या अन्यत्र सेवा संबंधी कोई आदेश किसी अधिकारी को तब जारी किया जाता है जब वह पहले से ही छुट्टी पर है। तो स्पष्टीकरण 1 के अधीन अनुज्ञेय अवधि ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से गिनी जाएगी।

(3) जब कोई निवास-स्थान उपनियम (2) के अधीन रखे रहा जाए तब अनुज्ञेय रियायती, अवधियो की समाप्ति पर वह आबंटन, सिवाए उस दशा के जब उन अवधियों की समाप्ति के पश्चात् वह अधिकारी दिल्ली में संस्थान में कर्तव्यभार ग्रहण कर लेता है, रद्द किया गया समझा जाएगा।

(4) जब कोई अधिकारी बिना वेतन और भत्तों के विशिष्मा छुट्टी पर हो तब वह उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद सं० (xii) के अधीन दी गई रियायत के आधार पर अपने निवास-स्थान को अपने पास रख सकता है परन्तु यह तब जब वह ऐसे निवास-स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास नगद भेजता रहे और ऐसी फीस दो मास से अधिक तक न भेजने की दशा में आबंटन रद्द हो जाएगा।

(5) जिस अधिकारी ने, उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (i) या मद (ii) के अधीन दी गई रियायत के आधार पर निवास-स्थान अपने पास रखा है वह संस्थान में उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट 'अवधि' के भीतर पुनर्नियोजित होने पर, इस बात का हकदार होगा कि वह निवास-स्थान को अपने पास रखे रहे और वह इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के किसी और आबंटन का भी पात्र होगा

परन्तु यदि ऐसे पुनर्नियोजन पर अधिकारी की उपलब्धियां इतनी हों जिनके आधार पर वह उस टाइप के निवास-स्थान का हकदार न हो जो उसके अधिभोग में है, तो ऐसे निम्नतर टाइप का निवास-स्थान आबंटित किया जाएगा।

(6) उपनियम (2), या उपनियम (3), या उपनियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई अधिकारी पदच्युत कर दिया जाता है या सेवा से हटा दिया जाता है या जब उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है और निदेशक का ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है तो वह ऐसे अधिकारी को किए गए निवास-स्थान का आबंटन या तो तुरन्त, या उस तारीख से रद्द कर सकेगा जो उपनियम (2) के नीचे की सारणी की मद (1) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति से पहले की हो और जो वह विनिर्दिष्ट करे।

अनु० नि० 317-ण-11 अनुज्ञप्ति फीस विषयक उपबन्ध

(1) जहां घास सुविधा या आनुकल्पिक वास सुविधा का आबंटन स्वीकृत कर लिया गया है वहां, अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग, की तारीख से या आबंटन जारी किए जाने की तारीख से आठवें दिन, से, जो भी पहले पद, प्रारम्भ होगा।

जो अधिकारी आबंटन स्वीकार करने के पश्चात् उस मास सुविधा का कब्जा आबंटन-पत्र जारी किए जाने की तारीख से आठ दिन के भीतर नहीं लेता उससे उस तारीख से बारह दिन की अवधि तक अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी, परन्तु इसमें की कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी जब केन्द्रीय निर्माण विभाग यह प्रमाणित करे कि घास-सुविधा अधिभोग के योग्य नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवास सुविधा का अधिभोग में नहीं ले रहा है।

(2) जहां किसी अधिकारी को जिसके अधिभोग में कोई एक निवास-स्थान है, कोई दूसरा निवास-स्थान आबंटित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान पर अधिभोग में ले लेता है वहां पहले निवास-स्थान का आबंटन नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समझा जाएगा। तथापि वह, निवास-स्थान में परिवर्तन के लिए पहले निवास-स्थान को उस दिन और उसके बाद के एक दिन के लिए, अनुज्ञप्ति फीस दिए बिना, अपने पास रख सकता है।

अ० नि० 317-ण-12 निवास-स्थान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति-फीस देने का वैयक्तिक दायित्व और अस्थायी अधिकारी द्वारा प्रतिभू की व्यवस्था —

(1) जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आबंटन किया जाए उस पर उसकी अनुज्ञप्ति फीस तथा उस नुकसान का, जो उसे हुई उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हुआ हो या जो उस निवास-स्थान को दिए गए फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग या सेवा व्यवस्था को उस अवधि के दौरान, हुई हो, जिसके लिए निवास-स्थान उसे आबंटित किया जाता है और उसे आबंटित रहता है या जहां आबंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया जाता है वहां, जब तक वह निवास-स्थान तथा उससे सलग्न उपगृह खाली करके उनका पूर्णत खाली कब्जा निदेशक को वापस नहीं कर दिया जाता है तब तक, व्यक्तिगत दायित्व होगा।

(2) जहां वह अधिकारी, जिसे निवास-स्थान आबंटित किया जाता है, न तो संस्थान का स्थायी कर्मचारी है न स्थायीकल्प है वहां वह अनुज्ञप्ति फीस तथा अन्य ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए, जो उस निवास-स्थान और अन्य सेवाओं की बाबत तथा उनके बदले दिये गए किसी अन्य निवास-स्थान की बाबत उसके द्वारा देय हों, एक प्रतिभू सहित, निदेशक द्वारा इस नियम में विहित प्ररूप में एक प्रतिभूनिपत्र निष्पादित करेगा। यह प्रतिभू संस्थान के अधीन सेवा करने वाला संस्थान का स्थायी कर्मचारी होना चाहिए।

(3) यदि प्रतिभू संस्थान की सेवा में नहीं रह जाता या दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं रह जाता तो अधिकारी किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पादित एक नया बन्धपत्र, उसे, उस घटना या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, देगा, और यदि वह ऐसा न करे तो, जब तक निदेशक अन्यथा विनिश्चित न करे, उस निवास-स्थान का उसे आबंटन उक्त घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

अनु० नि० 317-ण-13 आबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि —

(1) अधिकारी ऐसी सूचना देकर, जो निवास-स्थान को खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व निदेशक के पास पहुंच जाए, किसी भी समय आबंटन को अभ्यर्पित कर सकता है। निवास-स्थान का आबंटन उस दिन के पश्चात् जिसको पत्र निदेशक को प्राप्त होता है, ग्यारहवें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, रद्द किया गया समझा जाएगा। यदि वह सम्यक् सूचना न दे तो, वह दस दिन की अथवा दस दिन की सूचना देने में जितने दिन की कमी हो उतने दिन की, अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु निदेशक कम अवधि की सूचना स्वीकार करता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन निवास-स्थान अभ्यर्पित करने वाले अधिकारी के संबंध में ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक संस्था में सरकारी वास सुविधा का आबंटन करने के लिए, पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

अनु० नि० 317-ण-14, निवास-स्थान में परिवर्तन—

(1) वह अधिकारी, जिसे इन नियमों के अधीन कोई निवास-स्थान आबंटित किया गया है, यह आवेदन करता है कि उसे उसके बदले उसी टाइप का या उस टाइप का जिसका पात्र वह अनु० नि० 317-ण-5 के अधीन है, जो भी निम्नतर हो, निवास-स्थान दिया जाए परन्तु किसी अधिकारी को आबंटित एक टाइप के निवास-स्थान की बाबत एक बार से अधिक परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) परिवर्तन के लिए वे सब आवेदन, जो निदेशक द्वारा विहित प्ररूप में दिए गए हों, और किसी कैलेंडर मास में 19 वें दिन तक प्राप्त हुए हों, अगले मास की प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। इस नियम के प्रयोजनों के लिए वे अधिकारी, जिनके नाम पूर्वतर मास की प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित नहीं हैं, सामूहिक रूप में उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चात्वर्ती मासों की सूची में सम्मिलित किए जाएं। किसी विशिष्ट मास में सूचीं में सम्मिलित किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम में आधारित की जाएगी।

(3) परिवर्तन, उपनियम (2) के अनुसार अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में तथा अधिकारी की अपनी पसन्द का यथासम्भव स्थान रखते हुए करना दिया जाएगा।

(4) यदि कोई अधिकारी निवास-स्थान के परिवर्तन को, प्रस्थापना या आबंटन जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर, स्वीकार नहीं करता है तो उसके नाम पर उसी टाइप के निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए पुन: विचार नहीं किया जाएगा ।

(5) जो अधिकारी निवास-स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता है उससे ऐसे निवास-स्थान के लिए अनु० नि० 317-ण-11 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति-फीस ली जाएगी, जो उस निवास-स्थान के लिए, जो पहले से ही उसके कब्जे में है और जिसका आबंटन बराबर बना रहेगा, सा० नि० 45-क के अधीन प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त होगी ।

अनु० नि० 317–ण–15 . कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में निवास स्थान का परिवर्तन––

अनु० नि० 317–ण–15 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अधिकारी के कुटुम्ब की मृत्यु हो जाती है और वह निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसी घटना के तीन मास के भीतर करता है तो उसे निवास-स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकती है, परन्तु यह परिवर्तन उसी टाइप के निवास-स्थान में तथा उसी मंजिल पर होगा जो उस अधिकारी को पहले आबंटित निवास-स्थान का है ।

अनु० नि० 317–ण–16 . निवास स्थानों का अपरिवर्तन पारस्परिक विनिमय

जिन अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास-स्थान आबंटित किए गए है, वे इस आशय का आवेदन कर सकते है कि उन्हें अपने निवास-स्थानों का पारस्परिक विनिमय करने की अनुज्ञा दी जाए । जब इस बात की उचित तौर पर प्रत्याशा हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनिमय के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छह मास तक दिल्ली में कर्त्तव्यारूढ रहेंगे और पारस्परिक रूप से विनिमय से प्राप्त अपने निवास-स्थानों में रहेंगे तब पारस्परिक विनिमय की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

अनु० नि० 317–ण–17 : उन स्थानों के लिए रूपांतरण जहां कुटुम्ब नहीं रखा जा सकता :

यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण किसी ऐसे स्थान को किया जाता है जहां उसे अपना कुटुम्ब साथ ले जाने के लिए निदेशक द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाता या मंजूर नहीं की जाती और इन नियमों के अधीन उसे आबंटित निवास-स्थान उसकी संतान की वास्तविक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए कुटुम्ब द्वारा अपेक्षित है तो, उसे, प्रार्थना करने पर, दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने वाली उसकी संतान के चालू शैक्षणिक सत्र के अन्त तक, सा० नि० 45-क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर, निवास-स्थान रखने के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है ।

अनु० नि० 317–ण–18 . निवास-स्थान का रखरखाव :

जिन अधिकारी को निवास-स्थान आबंटित किया गया है, वह उसे गैर-परिसरों को निदेशक तथा दिल्ली नगर निगम के संतोष प्रद रूप में साफ दशा में रखेगा । ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान में संलग्न किसी बाग, प्रांगण या चारदीवारी में न तो निदेशक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही निदेशक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी विद्यमान वृक्ष या झाड़ी को काटेगा या छांटेगा । इन नियमों के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष, पौधे या वनस्पति और मुर्गे-मुर्गी तथा ढोरों का, जिनका पालन किया जा रहा हो, संबंधित अधिकारी के जोखिम और खर्च पर हटाया जा सकता है ।

अनु० नि० 317–ण–19 : निवास स्थान का हिस्सा देना और सहयोग :

(1) कोई अधिकारी अपने को आबंटित निवास-स्थान या उससे संलग्न उपगृह से, गैरजों और अस्तबलों का सहभोग इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के आबंटन के पात्र संस्थान के कर्मचारियों के साथ ही करेगा । सेवक निवासों (क्वार्टरों), उपगृहों, गैरजों और अस्तबलों का उपयोग केवल सद्भावी प्रयोजनों के लिए, जिनके अन्तर्गत आबंटी के सेवकों का निवास भी है, या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जिसकी निदेशक अनुज्ञा दे ।

(2) कोई भी अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास-स्थान को उपपट्टे पर नहीं देगा परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास-स्थान में किसी अन्य अधिकारी को जो वास-सुविधा का सहभोग करने का पात्र हो, देखभाल करने वाले (केयर टेकर) के रूप में अ० नि० 317–ण–19(2) में विनिर्दिष्ट अवधि पर्यन्त, किन्तु छह मास से अनधिक के लिए रख सकता है ।

(3) जो अधिकारी, अपने निवास-स्थान को सहभोग में ले या उसे उप पट्टे पर दे वह, ऐसा अपनी जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा, और उस निवास-स्थान की बाबत देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए और ऐसे किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी बना रहेगा जो निवास-स्थान को या उसकी सीमाओं को पहुंचे और जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो ।

अनु०नि० 317–ण–20 : नियमों और शर्तों को भंग करने का परिणाम

(1) यदि वह अधिकारी, जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है, अनधिकृत रूप से उस निवास-स्थान को उप-पट्टे पर देता है या सहभोगी से ऐसी दर से किराया लेता है जिसे निदेशक अत्यधिक समझता है अथवा उस निवास-स्थान के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत निर्माण करता है अथवा उस निवास-स्थान या उसके किसी भाग का उपयोग उन प्रयोजनों से जिनके लिए वह है, से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए करता है, अथवा विद्युत् या जल के कनेक्शन बिगाड़ता है अथवा इन नियमों या आबंटन के निबन्धनों और शर्तों का कोई और भंग करता है, अथवा किसी ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें निदेशक अनुचित समझे ऐसे निवास-स्थान का परिसर का उपयोग करता है या उपयोग करने की अनुज्ञा देता है या उपयोग होने देता है, अथवा स्वयं ऐसा आचरण करता है जो उसकी राय में उसके पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है अथवा आबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूझ कर देता है तो निदेशक, उस अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, निवास-स्थान का आबंटन रद्द कर सकता है ।

स्पष्टीकरण ––इस उपनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिकारी" पद के अन्तर्गत, उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और उस अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति भी है ।

(2) यदि कोई अधिकारी उसे आबंटित निवास-स्थान को, या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपगृह, गैरेज या अस्तबल को इन नियमों का उल्लंघन कर के उप-पट्टे पर दे देता है तो ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, उससे ऐसी अधिक अनुज्ञप्ति फीस, जो सा० नि० 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के चार गुने से अधिक न हो, या बाजार अनुज्ञप्ति फीस, इनमें से जो भी अधिक हो वह, ली जा सकती है । प्रत्येक मामले में उस बात का विनिश्चय कि कितनी अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाएगी और कितनी अवधि के लिए वसूल की जाएगी निदेशक गुणागुण के आधार पर करेगा । इसके अतिरिक्त उस अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि पर्यन्त, जो निदेशक द्वारा विनिश्चित की जाए, निवास-स्थान को सहभोग में रखने से विसर्जित किया जा सकता है ।

(3) जहां आबंटिती द्वारा परिसर के अप्राधिकृत रूप से पट्टे पर दिए जाने के कारण आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाए वहां आबंटिती और उसके साथ उनमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर खाली करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जाएगा । परिसर के खाली किए जाने की तारीख से या आबंटन रद्द करने के आदेश की तारीख से, पन्द्रह दिन अवधि के समाप्त होने पर, जो भी इसमें से पहले पड़े, आबंटन रद्द हो जाएगा ।

(4) जहां निवास-स्थान का आबंटन ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाए जो पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां उस अधिकारी को, निदेशक के विवेकानुसार उसी वर्ग का निवास-स्थान किसी अन्य स्थान पर आबंटित किया जा सकता है ।

(5) निदेशक इस नियम के उप-नियम (1) से (4) तक के अधीन सभी कार्रवाइयां या कोई कार्रवाई करने के लिए, तथा ऐसे अधिकारी को, जो उन नियमों तथा उसे जारी किए गए अनुदेशों को भंग करता है, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए वास सुविधा के आबंटन के लिए भी अपात्र घोषित करने के लिए सक्षम होगा ।

अनु० नि० 317–ण–21 : आबंटन रद्द किए जाने के पश्चात् निवास-स्थान में बने रहना—

जहां कोई आबंटन, इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया जाए या रद्द किया गया समझा जाए और तत्पश्चात् वह निवास-स्थान उस अधिकारी के, जिसे वह आबंटित किया गया हो, या उस के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहे या बना रहा हो । वहां ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान सेवाओं, फर्नीचर के उपयोग और अधिभोग के लिए उतनी नुकसानी और बाग-प्रभारों का देनदार होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित बाजार अनुज्ञप्ति फीस के बराबर हो :

परन्तु निदेशक किसी अधिकारी को, विशेष दशाओं में, मू० नि० 45-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस से दो गुना या मू०नि० 45-क के अधीन मूल की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस से दो गुना, जो भी अधिक हो, देने पर, अ० नि० 317–ण–10(2) के अधीन अनुज्ञात अवधि से परे छह मास से अनधिक अवधि के लिए, निवास-स्थान रखने की अनुज्ञा दे सकता है ।

अनु० नि० 317–ण–22 : इन नियमों के जारी किए जाने से पहले किए गए आबंटन का बना रहना :

निवास-स्थान के किसी ऐसे विधिमान्य आबंटन के बारे में, जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अस्तित्व में हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया गया आबंटन है भले ही वह अधिकारी, जिसे वह आबंटन किया गया है, अनु० नि० 317–ण–5 के अधीन उस टाइप के निवास स्थान के लिए हकदार न हो और उस आबंटन और उस अधिकारी के संबंध में इन नियमों के सभी पूर्ववर्ती उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

अनु० नि० 317–ण–23 : नियमों का निर्वचन :

यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठे तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अनु० नि० 317–ण–24 : नियमों का शिथिल किया जाना :

सरकार उन कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, इन नियमों के सभी उपबन्धों का या उनमें से किसी का किसी अधिकारी या निवास-स्थान के मामले में अथवा अधिकारियों के किसी वर्ग या निवास-स्थानों के किसी टाइप के मामले में शिथिल कर सकती है ।

अनु० नि० 317–ण–25 : शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन :

सरकार इन नियमों द्वारा उसे प्रदत्त कोई शक्ति या सभी शक्तियां अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगी जिन्हें आरोपित करना वह ठीक समझे ।

अनुसूची—1

(अनु० नि० 317–ण–5 देखें)

निवास-स्थान का वर्गीकरण

निवास-स्थान का टाइप	निवास-स्थानों का वर्गीकरण
I	टाईप I (पुराना) सं० 1 से 44 तक टाईप I (नया) सं० 1 से 300 तक
II	ई—टाइप सं० 1 से 104 तक II—बी टाइप सं० 1 से 48 तक III—ए टाइप सं० 1 से 36 तक एच टाइप संख्या 1 से 3 तक
III	डी टाइप सं० 1 से 43 तक
IV	डी—II फ्लेट सं० 1 से 12 तक सी टाइप सं० 25 से 31 तक
V	बी टाइप सं० 22 से 24 तक और 32 सी टाइप सं० 33 से 42 तक
VI	बी टाइप सं० 1 से 7 तक और 9 से 20 तक
VII	बी टाइप सं० 8

अनुसूची 2

(अनु० नि० 317–ण–5 देखें)

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में निवास-स्थानों का आरक्षण

निवास-स्थान की विशिष्टियां	उन अधिकारियों के पदाभिधान जिनके लिए आरक्षित है
1. बी–8	. निदेशक
2. बी–7	. संकायाध्यक्ष और संयुक्त निदेशक
3. बी–11	. मुख्य प्रशासन अधिकारी-एवं-रजिस्ट्रार
4. बी–13	. वरिष्ठ परियोजना निदेशक
5. बी–32	. सम्पदा और प्रोटोकोल अधिकारी
6. सी–27	. चिकित्सा अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान चिकित्सालय ।
7. ई–1	. फार्मासिस्ट
8 डी—44	. सहायक पशुधन अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान डेरी
9. डी–1	. सहायक इंजीनियर, फार्म संक्रिया और प्रबन्ध विभाग
10. ई–28	. एक सुरक्षा पर्यवेक्षक

उन पदों के त्यागने पर, जिनके लिए निवास-स्थान है, आरक्षित क्वार्टर के निवास-स्थान को रखे रखने की अनुज्ञेय अवधि दो मास होगी जिसकी समाप्ति पर अधिकारी निवास-स्थान को खाली कर देगा ।

टिप्पणी 1 —उक्त अधिकारियों को, जो इस अनुसूची के अनुसार किसी विशिष्टि आरक्षित गृह के हकदार है, उस प्रकम के निवास स्थानों के आबंटन में, जिनके लिए वे हकदार हैं, प्रथम

प्राथमिकता दी जाएगी और जो गृह उनके लिए है उनके खाली होते ही उन्हें अधिभोग की अनुज्ञा दी जाएगी।

टिप्पणी 2 :—आरक्षित गृहों के अधिकारियों को, ऐसे पदों पर स्थानान्तरण, प्रोन्नति या प्रतिवर्तन पर, जिनसे कोई गृह सलग्न नहीं है, ऐसे गृहों को खाली करना पड़ेगा। विकल्पत. वाम सुविधा उसे उस प्रवर्ग में, जिसके लिए पदधारी ऐसे स्थानान्तरण, प्रोन्नति या प्रतिवर्तन पर हकदार होता है, यदि उपलब्ध है, तो आबंटित की जाएगी अन्यथा उसे दोनों प्रवर्गों में अध्यारोही पूर्विकता देते हुए ठीक निम्नतर प्रवर्ग में आबंटन किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि आवंटित गृह दो वर्ष से अन्यून अवधि तक उसके प्राधिकृत अधिभोग में रहा हो।"

[फा० सं० 3-1/69-ई० ई०-IV]

एम० सी० जयरामन, अवर सचिव

(Department of Agricultural Research and Education)

New Delhi, the 20th May, 1977.

INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

(ALLOTMENT OF RESIDENCES) REVISED RULES, 1977

S.O. 2125.—In pursuance of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Supplementary Rules, issued the Government of India, late Finance Department, letter No. 104-C.S.R., dated 4th February, 1922, namely :—

In part VIII of the said rules, for Division XXVI-J and the heading and rules thereunder, the following Division, heading and rules shall be substituted namely :—

"Division XXVI-J-The Indian Agricultural Research Institute (Allotment of Residences) Rules, 1977—

S. R. 317-J-1 : Short title, application and commencement :—

(1) These rules may be called the Indian Agricultural Research Institute (Allotment of Residences) Rules, 1977.

(2) They shall apply to the residential buildings belonging to the Government and located within the premises of the Indian Agricultural Research Institute.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

S. R. 317-J-2 : Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) 'allotment' means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;

(b) 'allotment year' means the year beginning on 1st January or such or other period as may be notified by the Director.

(c) 'Director' means the Director of the Institute and includes any other officer authorised by him to act on his behalf;

(d) 'eligible office' means the office of the Indian Agricultural Research Institute and its sub-stations, the staff of which has been declared by the Director as eligible for accommodation under these rules;

(e) 'emoluments' means the emoluments as defined in rule 45-C of the Fundamental Rules, but excluding the compensatory allowance.

Explanation :—In the case of an officer who is under suspension the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the emoluments drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments;

(f) 'family' means the wife or husband, as the case may be, and children, step-children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with, and are dependent on, the officer;

(g) 'Government' means the Central Government;

(h) 'Institute' means the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi;

(i) 'licence fee' means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these rules;

(j) 'priority date' of an officer for allotment of accommodation under these rules means the earliest date of holding continuous qualifying appointment on a post under the Institute including the periods of authorised absence on deputation, foreign service training, leave etc:

Provided that the eligibility for the type of residence under the provision of S. R. 317-I-5 shall be determined on the emoluments on the first day of the allotment year as may be specified:

Provided further the officers eligible to Type V or Type VI shall also be eligible to allotment of residences in type next below to their eligible type, namely, Type IV and Type V respectively:

Provided also that where the priority date of two or more officers is the same seniority amongst themselves shall be determined by the amount of emoluments, the officer in receipt of higher emoluments taking procedure over the officer in receipt of lower emoluments; and where the emoluments are equal, by the length of service;

(k) 'residence' means any residence for the time being under the administrative control of the Director;

(l) 'subletting' includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person.

'Explanation' Any sharing of accommodation be an allottee with close relations shall not be deemed to be subletting;

(m) 'transfer' means a transfer from an office of the Institute at New Delhi to any other office of the Institute outside New Delhi or vice versa and also deputation to a post in an ineligible office or organisation;

(n) 'temporary transfer' means a transfer which involves an absence for a period of not exceeding four months;

(o) 'Type' in relation to an Officer means the type of residence to which he shall be eligible under S.R. 317-J-5.

S.R. 317-J-3 Ineligibility of officers owning houses for allotment under these rules :—

No officer shall be eligible for allotment of a residence under these rules if he/she owns a house in full or in part in his/her own name or in the name of his/her wife or husband or any dependent within the municipal limits of New Delhi/Delhi.

S. R. 317-J-4 Allotment to husband and wife. Eligibility in cases of officers who are married to each other :—

(1) Where both husband and wife are employed under the Institute, the title of each of the two officers to allotment of a residence under these rules shall be considered independently.

(2) No officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered :

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(3) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules marry each other, they shall, within one month of the marriage surrender one of the residences

(4) If a residence is not surrendered, as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower Type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period and if the residences are of the same Type, the allotment of such one of them as the Director may decide shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(5) Notwithstanding anything contained in sub rules (1) to (4)

(a) if a wife or husband, as the case may be, who is an allottee of a residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender any one of the residences within one month of such allotment

Provided that this clause shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court,

(b) where two officers, in occupation of separate residences in the same station one allotted under these rules and another from a pool to which these rules do not apply marry each other any of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage,

(c) if a residence is not surrendered as required under clause (a) or clause (b) as the case may be, the allotment of the residence made under these rules shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period

S R 317-J-5 Classification of residences —

(1) Save as otherwise provided in these rules an officer shall be eligible for allotment of a residence of the Type shown in the Table below

Type of Residence	Category of Officer on his monthly emoluments as on 1st day of the allotment year in which the allotment is made	Residences
I	Less than Rs 260 per month	Class IV Type I
II	Less than Rs 500 but not less than Rs 260/-per month	Type II-A -IIB, H and I
III	Less than Rs 700/-but not less than Rs 500/-per month	Type D
IV	Less than Rs 1000/-but not less than Rs 700/-per month	D-II flats & C Type
V	Less than Rs 1650/- but not less than Rs 1000/-per month	Type C
VI	Less than Rs 2500/- but not less than Rs 1650/- per month	Type B
VII	Director	Type B

The classification and reservation of residences shall be as given respectively in Schedules I and II appended to these rules The permissible period for retention of residence of a reserved quarter on demitting the office for which a residence is earmarked shall be two months on the expiry of which the officer shall vacate the residence

S R 317 J 6 Application for allotment —

(1) Every Officer in occupation of accommodation under these rules shall submit his application in such form and manner and by such date as may be specified by the Director in this behalf

(2) In case of officers not in occupation of accommodation under these rules the Director shall invite applications in such form and manner and before such date as may be specified by him

(3) An officer joining duty in the Institute on first appointment or on transfer may submit his application to the Director within a month of his joining duty

(4) Applications received under sub-rule (3) on or before the 20th day of a calender month shall alone be considered for allotment in the succeeding month

S R 317 J 7 Allotment of residences and offers —

(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence on falling vacant, shall be allotted by the Director preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that Type, under the provisions of S R 317 J-15 and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earlier priority date for that type of residence subject to the following conditions, namely —

(i) that the Director shall not allot a residence of a type higher than that to what the applicant is eligible under S R 317 J 5

(ii) that the Director shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than that to what he is eligible under S R 317 J-5,

(iii) that the Director on request from an applicant for allotment of a lower category residences might allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible under S R 317-J 5 on the basis of his priority date for the same

(2) The Director may cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same type or, in emergent circumstances, an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated

(3) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1), be offered simultaneously to other eligible officers in order of their priority dates

S R 317-J 8 Out of turn allotments —

Notwithstanding the provisions of S R 317-J 7, allotment of a residence may be made by the Director on out-of-turn basis to an officer on the grounds of serious illness of self or a member of his family, in consultation, if considered necessary with a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon or a District Medical Officer The priority date for allotment in such cases shall be the date on which the application of the officer for out of-turn allotment is received by the Director

S R 317 J-9 Non acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance —

(1) If any officer fails to accept the allotment of residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of issue of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter

(2) If an officer occupying a lower type of residence is allotted or offered a residence of the type for which he shall be eligible under S R 317 J 5 or for which he has applied under clause (iii) of sub-rule (1) of S R 317-J-7 he may on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permited to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely —

(a) that such an officer shall not be eligible for another allotment for the remaining period of allotment year in which he has declined the allotment or offer for the higher class of accommodation,

(b) that while retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have had to pay under FR 45-A in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher If an officer occupying a lower type of residence has given his option in his application made under S R 317 J 6 to retain the said residence, the provision contained in this clause shall not apply to him during the period for which such option has been given

S R 317-J 10 Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention —

(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until—

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-clause (2) after the officer ceases to be on duty in the Institute in Delhi, or

(b) it is cancelled by the Director or is deemed to have been cancelled under any provision in these rules, or

(c) it is surrendered by the Officer or

(d) the officer ceases to occupy the residence

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in Col I of the Table below for the period specified in co responding entry in Column (2) thereof provided that the residence is required for the bona fide use of the officer or members of his family

TABLE

Events	Permissible period for retention of the residence
(i) Resignation, dismissal or removal from service, termination of service or unauthorised absence without permission	1 month
(ii) Retirement or terminal leave	2 months
(iii) Death of the allottee	4 months
(iv) Transfer to a place outside Delhi	2 months
(v) Transfer to an ineligible office in Delhi	2 months
(vi) On proceeding on foreign service in India	2 months
(vii) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India	4 months
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave)	For the period of leave but not exceeding 4 months
(ix) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under F R 86 or earned leave to employees of the Institute who retire under F R 56	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of 4 months inclusive of the period permissible in the case of retirement
(x) Study leave or deputation outside India	For the period of leave but not exceeding 6 months
(xi) Study leave in India	For the period of leave but not exceeding 6 months
(xii) Leave on medical grounds	For full period of leave
(xiii) On proceeding on training	For full period of training, provided it is sponsored by the Institute

Explanation I —Where an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (iv) (v) (vi), (vii) or for the period of leave, whichever is more

Explanation II —Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave the period permissible under explanation (I) shall count from the date of issue of such order

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2), the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in the Institute in Delhi

(4) Where an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the con cession under item (xii) of the Table below sub rule (2), pro vided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled

(5) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or item (ii) of the Table below sub-rule (2) shall, on re-employment in the Institute wi hin the period specified in the said Table be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment of residence under these rules

Provided that if the emoluments of the officer on such re employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower type of residence

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub rule (3) or in sub rule (5), when an officer is removed or his services have been terminated and the Director is satis fied for reasons to be recorded in writing that it is necessary or expedi nt in the public interest to do so, he may cancel the allotment of the residence made to such officer either forth with or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table below sub rule (2) as he may specify

S R 317-J-11 Provisions relating to licence fee —

(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of issue of the allotment letter, whichever is earlier

An officer who after acceptance, fails to take pos session of that accommodation within eight days from the date of issue of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of twelve days, provided nothing contained herein shall apply where Central Works Department certified that the accommodation is not yet ready for occupation and as a result thereof the officer does not occupy the accommodation within the period aforesaid

(2) Where an officer, who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupied the new residence the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence He may however, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting

S R 317 J-12 Personal liability of the officer for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing of surety by temporary officer —

(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotmen has been cancelled under any of the provisions in these rules until the residence along with the out-houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to the Director

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent employee of the Institute he shall execute a Surety bond in the form prescribed in this behalf by the Director with a Surety who shall be a permanent employee of the Institute serving under the Institute for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu

(3) If the surety ceases to be in the service of the Institute or becomes insolvent or ceases to be available for any other reasons the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty from the date of his

knowledge of such event of the fact and that if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by the Director, be deemed to have been cancelled with effect from the date of the event.

S.R. 317-J-13 Surrender of an allotment and period of notice :—

(1) An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Director at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Director, or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice, he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days, provided that the Director may accept a notice for a short period.

(2) An officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of accommodation at the Institute for a period of one year from the date of such surrender .

S.R. 317-J-14 Change of residence :—

(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under S.R. 317-J-5 whichever is lower, provided that not more than one change shall be allowed to any such officer in respect of one type of residence allotted to the officer.

(2) All applications for change made in the form prescribed by the Director and received upto the 19th day of a calendar month shall be included in the waiting list in the subsequent month. For the purpose of this rule, the officers whose names are included in the waiting list, in an earlier month shall be senior on block to those whose names are included in the list in subsequent months. The inter-se seniority of the officers included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Change shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officer's preferences, as far as possible.

(4) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment, he shall not be considereed again for a change of residence of that type.

(5) An officer who, after accepting a change of residence fails to take possession of the same shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provisions of sub-rule (1) of S.R. 317-J-11 in addition to the normal licence fee under F.R. 45-A for the residence already in his possession, the allotment of which shall continue to subsist.

S.R. 317-J-15 Change of residence in the event of death of a member of the family :—

Notwithstanding anything contained in S.R. 317-J-14, an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change may be given in the same type of residence and on the same floor as the residence already allotted to the Officer.

S. R. 317-J-16 Mutual exchange of residence:—

Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission for mutual exchange of their residences. Permission of mutual exchange may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty in Delhi and to reside in their mutually exchanged residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

S.R. 317-J-17 Transfer to non-family stations :—

If an officer is transferred to a station where he is not permitted to or advised by the Director to take his family with him and the residence allotted to him under these rules as required by the family for the bona fide educational needs of his children, he may be allowed, on request, to retain the residence on payment of licence fee under F.R. 45-A till the end of the current academic session of his children studying in Delhi.

S.R. 317-J-18 Maintenance of residences :—

The Officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Director and the Municipal Corporation of Delhi. Such officer shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Director nor cut or lop off any existing tree shrubs in any garden, courtyard or compound attached to the residence, save with the prior permission in writing of the Director. Trees, plantation or negetation, grown and rearing of poultry or cattle in contravention of these rules may be caused to be removed at the risk and the cost of the officer concerned.

S.R. 317-J-19 Subletting and sharing of residences :—

(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses, garages and stables appurtenant thereto except with the employees of the Institute eligible for allotment of residences under these rules. The servants quarters, out-houses, garages and stables may be used only for the bona-fide purposes including residence of the servants of the allottee or for such purposes as may be permitted by the Director.

(2) No officer shall sublet the whole of his residence provided that an officer proceeding on leave may accommodate in the residence any other officer eligible to share accommodation, as a caretaker, for the period specified in S.R. 317-J-10(2), but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence without the prior permission of the Director shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts beyond fair wear and tear.

S.R. 317-J-20 Consequences of breach of rules and conditions.

(1) If an officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent from the sharer at a rate which the Director considers execessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purposes other than that for which it is meant or tempers with the electric or water connections or commit any other breach of these rules or of the terms and conditions of allotment or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any other purpose which the Director considers to be improper or conducts himself in a manner which in his opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relation with his neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application of written statement with a view to securing the allotment, the Director may without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

Explanation.—In this sub-rule, the expression 'Officer' includes unless the context otherwise required a member of his family and person claiming through the Officer.

(2) If any officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses garages or stables appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against him be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under F.R. 45-A or market licence fee whichever is the highest. The quantum of market licence fee is to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case shall be decided by the Director on merits. In addition the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Director.

(3) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allottee, a period of 15 days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him therein to vacate the premises The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of 15 days from the date of orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with

neighbours, the officer at the discreation of the Director may be allotted another residence in the same class at any other place.

(5) The Director shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (4) and also to declare the officer, who commits a breach of these rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

S.R. 317-J-21 Overstayal in residence after cancellation of allotment :—

Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision continued in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any person claiming through his, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges, equal to the market licence fee as may be determined by the Government from to time.

Provided that an officer, in special cases, may be allowed by the Director to retain a residence on payment of twice the standard licence fee under F.R. 45-A, or twice the pooled standard licence fee under F.R. 45-A, whichever is higher, if for a period not exceeding six months beyond the period permitted under S.R. 317-J-10(2).

S.R.317-J-22 Continuance of allotments made prior to the issue of these rules:—

Any valid allotment of a residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules under the rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under S.R. 317-J-5 and all the proceeding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

S.R.317-J-23 Interpretation of rules:—

If any question arises as to the interpretation of the rules, it shall be decided by the Director.

S.R.317-J-24 Relaxation of rules:—

The Government may, for reason to be recorded in writing, relax all or any of the provisions of these rules in the case of any officer or residence or class of officers or type of residences.

S.R.317-J-25 Delegation of powers or functions:—

The Government may delegate any or all the powers conferred upon it by these rules to any officer under its control, subject to such conditions as it may deem fit to impose.

SCHEDULE-I

(See S.R.317-J-5)

Classification of Residences

Type of Residences	Classification of Residences
I.	Type I (old) No.1 to 44 Type I (New) No.1 to 300
II.	E-Type No. 1 to 104 II-B Type No. 1 to 48 II-A Type No. 1 to 36 H-Type No. 1 to 3.
III.	D-Type No. 1 to 43
IV.	D-II/flats No. 1 to 12 C-Type No. 25 to 31
V.	B-Type No.22 to 24 & 32 C-Type No. 33 to 42
VI.	B-Type No. 1 to 7 & 9 to 20
VII.	B-Type No.8

SCHEDULE-II

(See S.R.317-J-5)

RESERVATION OF RESIDENCES AT INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

Particulars of the residences	Designation of the officers for whom reserved
1. B-8	Director
2. B-7	Dean and Joint Director
3. B-11	Chief Administrative Officer-cum-Registrar
4. B-13	Senior Project Director
5. B-32	Estate and Protocol Officer
6. C-27	Medical Officer, Indian Agricultural Research Institute Dispensary
7. E-1	Pharmacist
8. D-44	Assistant Livestock Officer, Indian Agricultural Research Institute Diary.
9. D-1	Assistant Engineer, Department of Farm Operation and Machinery.
10. E-28	One Security Supervisor.

The permissible period for retention of residences of a reserved quarter on demitting the office for which a residence is earmarked shall be two months on expiry of which the officer shall vacate the residence.

Note 1:—Officers who shall be entitled to the particular reserved house in accordance with this Schedule may be given first priority for allotment of residences in the categories to which they are entitled and may be allowed to occupy the houses earmarked for them as and when such houses fall vacant.

Note 2:—The occupants of reserved houses shall be required to vacate residences on transfer, promotion or reversion to posts with which no houses are attached. Alternative accommodation in the category to which the incumbent becomes entitled on transfer, promotion or reversion, may be allotted to him if available, otherwise allotment may be made to him in the next below category giving him overriding priority in both the categories provided he has been in authorised occupation of reserved house for not less than two years."

[F. No. 3-1/69-E.E.IV]

M. C. JAYARAMAN, Under Secy.

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 4 जून, 1977

(पुरातत्व)

का० आ० 2126 —केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व का है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् दो मास के भीतर उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आक्षेप पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	पुरातत्वीय स्थल और अवशेष का नाम और वर्णन	संरक्षण के अधीन सम्मिलित की जाने वाली राजस्व प्लाट संख्याएं	क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	प्रकासम्	गिद्दालूर	पुमलपाडु	सर्वेक्षण सं० 270, 271, 272, 295/1, 296/ख और 393 में समाविष्ट एक टीले में अन्तर्विष्ट पुरातत्वीय स्थल और अवशेष	सर्वेक्षण प्लाट सं० 270, 271, 272, 295/1, 296/ख और 393.	40.64 एकड़	उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट संख्या 273 और 284 पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट संख्या 284, 285, 286, 287 291, 292, 293, 294, 302, 295/2, 295/3 और 392 (टैंक) दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट सं० 394. पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट संख्या 242, 244, 247, 248, 269 और 394.	निजी स्वामित्वाधीन सर्वेक्षण प्लाट संख्या 271 और 272 और शेष क्षेत्र जो सरकार के स्वामित्वाधीन है।	

पुसलपाडु में प्राचीन स्थल का मानचित्र
जिला प्रकासम, आंध्र प्रदेश

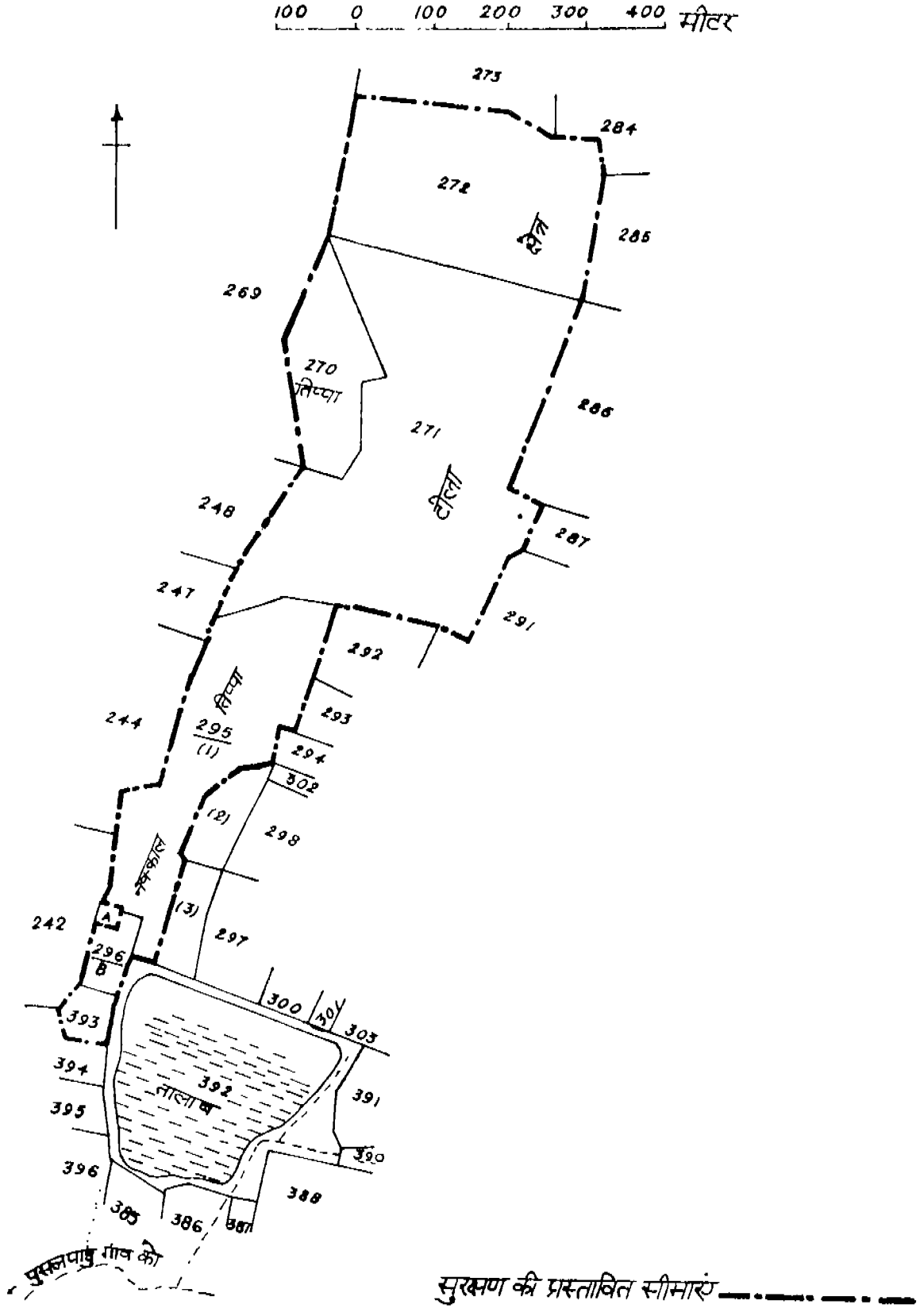

[संख्या 2/35/73-एम]

म० न० देशपांडे, महानिदेशक और पदेन संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 4th June, 1977

(ARCHAEOLOGY)

S. O. 2126—Whereas the Central Government is of opinion that the archaeological site and remains specified in the Schedule attached thereto are of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said archaeological site and remains to be of national importance

Any objection made within two months after the issue of this notification by any person interested in the said archaeological site and remains will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name and Description of Archaeological site and remains	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Andhra Pradesh	Prakasam	Giddalur	Pusalapadu	Archaeological site and remains containing a mound comprising in Survey Nos. 270, 271, 272, 295/1, 296/B and 393.	Survey plot numbers 270, 271, 272, 295/1, 296/-B and 393	40.64 acres.	North: Survey plot numbers 273 and 284. East: Survey plot numbers 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 302, 295/2, 295/3 and 392 (Tank). South: Survey plot number 394. West: Survey plot numbers 242, 244, 247, 248, 269 and 394.	Survey plot numbers 271 and 272 under Private ownership and remaining area owned by Government.	

SITE-PLAN OF THE ANCIENT SITE AT PUSALAPADU DISTRICT PRAKASAM, ANDHRA PRADESH

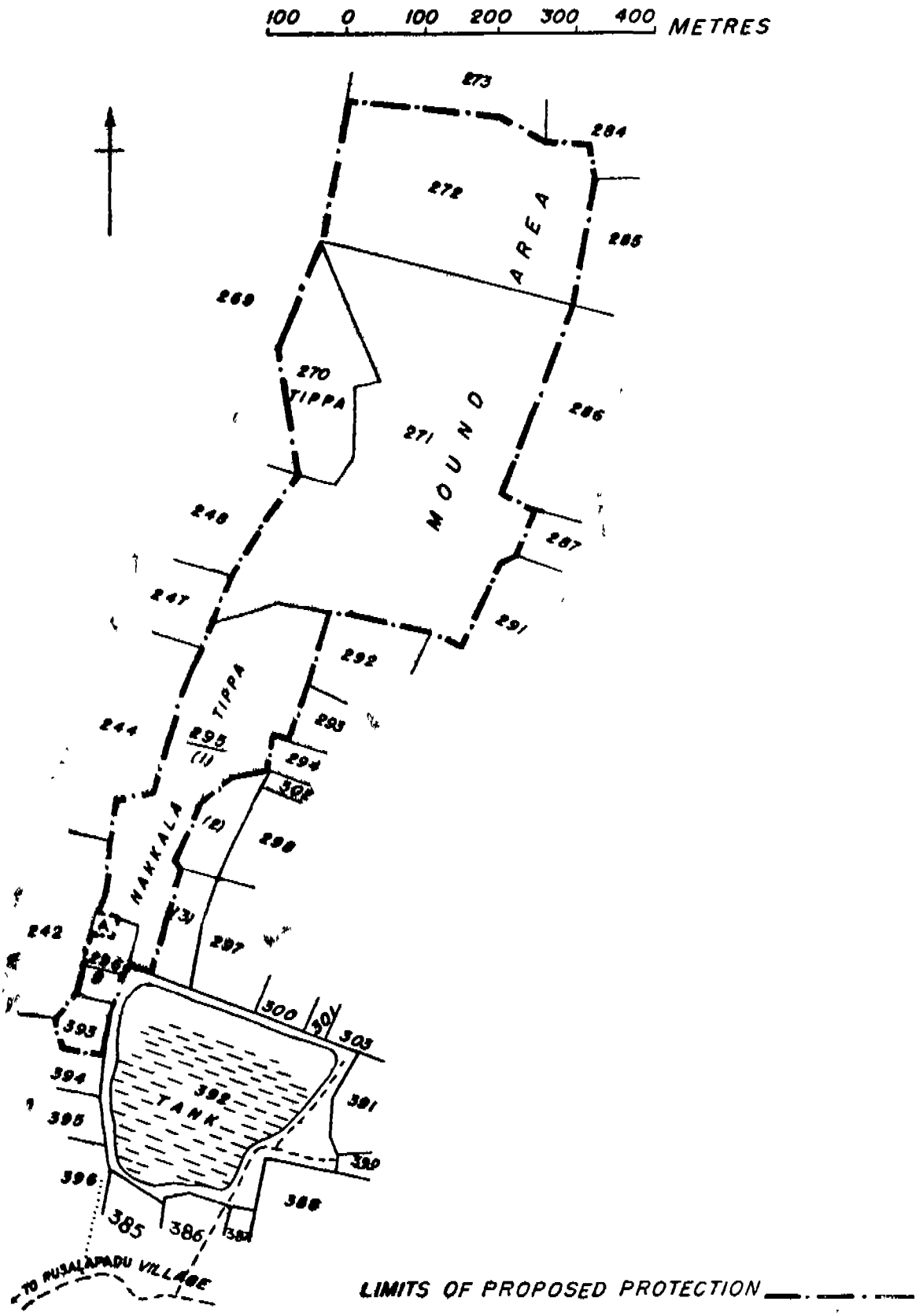

[No.2/35/73-M]

M. N. DESHPANDE, Dir. Genl. & Ex-officio, Secy.

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलौर, 16 मई, 1977

का० आ० 2127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) द्वितीय संशोधन नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अन्तरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 के नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (ग) में "या वह निवारक निरोध के अधीन है या उसे ऋण के कारण गिरफ्तार किया गया है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[सं० 2/10(32)/76-I]

पी० एस० कंवल, उप सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 16th May, 1977

S.O. 2127.—*In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, namely :—*

(1) These rules may be called the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, in Rule 7, in Sub-rule (1), in Clause (c), the words "or he is under preventive detention or has been arrested for debt" shall be omitted.

[No. 2/10(32)/76-I]

P. S. KANWAL, Dy. Secy.

पूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई, 1977

का० आ० 2128.—निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का LXIV) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री वी० एस० अग्रवाल, उप सचिव (मुकदमा), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली के लिए अपने कार्यों के अलावा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों को करने तथा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 32013(1)/75-प्रशा०-राजपत्रित/बं.वि.]

दीना नाथ असीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 23rd May, 1977

S.O. 2128.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (LXIV of 1951) the Central Government hereby appoints Shri V. S. Aggarwal, Deputy Secretary (Litigation), Delhi Administration, Delhi as Competent Officer for the Union Territory of Delhi for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions and exercising the powers assigned to him under the said Act.*

[No. 32013(1)/75-AGZ/SW]

D. N. ASIJA, Jt. Director

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1977

का० आ० 2129.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन बैंक, मद्रास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० सिंगारावेलु होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

1. क्या इंडियन बैंक, मद्रास के प्रबंधतंत्र की अप्रैजरों की सेवा की शर्तों को बदलने की कार्रवाई न्यायोचित है जिसमें प्रतिऋण 50 पैसे और प्रतिमास 150 रु० की न्यूनतम गारंटीकृत मजदूरी समाप्त कर दी गई है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

2. क्या इंडियन बैंक, मद्रास के प्रबंधतंत्र की बैंक के नियमित लिपिक वर्ग को लागू मजदूरी और सेवा की अन्य शर्तें अप्रैजरों को लागू न करने की कार्रवाई न्यायोचित है । यदि नहीं, तो सम्बंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ।

[सं० एल-12011/6/77-डी० II. ए.]

राम प्रसाद नरूला अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 21st April, 1977

S.O. 2129.—*Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Indian Bank, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;*

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7-A read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri T. N. Singaravelu with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Central Government Industrial Tribunal.

SCHEDULE

1. "Whether the action of the management of the Indian Bank, Madras in changing the conditions of service of appraisers so as to eliminate the minimum guaranteed wage of 50 paise per loan and Rs. 150 per month is justified ? If not, to what relief are the workmen entitled ?"

2. "Whether the action of the management of Indian Bank, Madras in denying the appraisers, wages and other conditions of service applicable to regular clerical "Award Staff" of the Bank is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

[No. L-12011/6/77-D. II. A]

New Delhi, the 9th June, 1977

S.O. 2130.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the State Bank of India, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 7-6-77.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1,

RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT-2/76

Ref :—Government of India, Ministry of Labour, Notification No. L. 12012/141/75/D II/A dated the 21st January, 1976.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Shri Gopal Singh

AND

State Bank of India, Jaipur

APPEARANCES :

Shri Ashok Parihar—For the Workman,

Shri S. K. Sharma—For the Bank.

Date of Award : 24th May, 1977

AWARD

By its notification dated 21-1-76, the Central Government has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the State Bank of India, Sanganeri Gate Branch, Jaipur in terminating the services of Shri Gopal Singh, Godown-Darban, with effect from the 1st August, 1974 is justified and legal ? If not to what relief is the said workman entitled ?"

The dispute is between the State Bank of India and its ex-employee Shri Gopal Singh, hereinafter to be referred as the workman.

The case set up by the workman in his statement of claim is that he was appointed by the State Bank of India, Branch Jaipur, as a Godown-Darban on 8-12-70. Since then, he was working in that capacity with no complaint against him. The appointment was of permanent nature. He continued to work as Godown-Darban upto 31-7-74. When he reported himself for duty on 1-8-74, he was not taken on duty by the Bank Manager. He was informed that his services stood terminated with effect from that day. The workman approached the Bank Authorities to redress his grievances of the termination of his services, but his attempt proved abortive. He sent a notice to the Bank raising an industrial dispute about his termination. But, this notice also remained unreplied. The matter was then taken to the Regional Labour Commissioner, Central, for conciliation. But, there also no conciliation could take place due to the non-cooperative attitude of the Bank. The Conciliation Officer submitted his failure report to the Government of India. The Government of India then made the present reference. It was alleged that the termination of the workman's services was bad. No inquiry was held against him. Even if it is taken to be a case of retrenchment, it was not valid, because the mandatory provisions of S. 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter to be referred as the Act, were not complied with. The relief claimed is that he be reinstated with full back wages.

The claim of the workman was resisted by the Bank. In its written statement, the Bank admitted that the workman was appointed as Godown Darban on 8-12-70 and his appointment ended on 31-7-74. The appointment was purely temporary. The workman worked intermitently. The Bank was left with no temporary post of Godown-Darban in August, 1974. The workman was, therefore, offered to work as Messanger. The workman worked as Messenger for one day on 1-8-74. Thereafter, he did not turn up to work. He thus voluntarily abondoned the services of the Bank. The workkman, after some time, approached the Bank for re-employment. He was given the employment of a Messenger on 18-11-75 and since then he was working in that capacity at Sikar Branch. It was alleged that no industrial dispute existed between the parties, and as such the reference was not maintainable.

Both the parties have led oral and documentary evidence. The workman examined himself, while in rebuttal the Bank examined its Manager Shri K. K. Bhargava.

I shall first take up the preliminary objection of the Bank that the reference is not maintainable, as no industrial dispute existed between the parties. I find no merit in this contention. The workman complains that his removal from service, which in essence is retrenchment, was illegal. Such a dispute must be taken to be an industrial dispute between an employer and employee. There being no force in the preliminary objection of the Bank, it is hereby repelled.

There is not much dispute as regards the facts involved in the case. Undisputedly, the workman, Shri Gopal Singh, was appointed Godown-Darban by the Bank on 8-12-70 and he worked in that capacity upto 31-7-74. The Bank has submitted a statement showing the details of the services of the workman from 8-12-70 to 31-7-74. He remained in employment upto 31-7-74. The chart further shows that he worked from 1-1-73 to 31-7-74 with no break during this period. Thus, he had completed one year's continuous service as defined in S. 25-B of the Act. The chart further shows that from 8-12-70 to 31-7-74, the workman worked for 1334 days in all.

The workman, Shri Gopal Singh, stated that he worked as Godown-Darban from 8-12-70 to 31-7-74. He was cross-examined, but with no result. The Bank also examined its manager, Shri K. K. Bhargava, who admitted that the workman worked from 18-12-70 to 31-7-74.

Sec. 25-B defines continuous service. Its sub-sec. (2) lays down that a workman shall be said to be in continuous service for a period of one year, if he, during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which the calculation is to be made, has actually worked for 240 days. As stated earlier the statement filed by the Bank shows that the workman had worked from 1-7-73 to 31-7-74 as Godown-Darban. He had thus worked for more than 240 days during the period of 12-calendar months preceding 31-7-74, which is the date, when his services were terminated.

The stand taken by the Bank is that it was left with no post of Godown-Darban. As such, the workman's services were terminated and he was offered an alternate job of Messanger. The workman worked as Messanger for one day on 1-8-74. Thereafter, he voluntarily abondoned the services.

Now, if the workman voluntarily abondoned the job, there is no question of termination of his services, or his being retrenched. The workman denied that he was offered the job of a Messanger or that he worked as a Messenger for one day on 1-8-74, or that he voluntarily left this job.

In view of these rival contentions, it was for the Bank to prove that the workman was offered the alternate job of a Messenger, he worked for one day as Messenger, and then voluntarily left the service. The Bank has adduced no evidence. Of course, the Bank examined Shri K. K. Bhargava. But, his testimony on this point is far from being Messenger, he worked for one day as Messenger, and then posted at Jaipur Branch since 6-12-74. He further admitted that the job of Messenger was offered to the workman not by him but by his predecessor Shri H. K. Agarwal, the then Manager, Jaipur Branch. He further stated that this offer was verbal and not in writing. He also admitted that Shri H. K. Agarwal is alive and is in the Bank service. He further admitted that the offer for Messenger's job was not made to the workman in his presence. An analysis of his testimony shows that it is entirely hearsay in nature. The offer of Messenger's job was not made in his presence. He can, therefore, have no knowledge about these things. A fact cannot be proved by hearsay evidence.

There are then some circumstances which negatived the stand taken by the Bank. The workman served a notice on the Bank and raised an industrial dispute therein against his illegal retrenchment. Shri K. K. Bhargava in cross-examination admitted the receipt of notice on 30-10-74. He further admitted that no reply of this notice was sent to the workman by the Bank. If the alternate job of Messanger had been offered to the workman by the Bank, the Bank could have never remained silent. It would have never left the workman's notice unanswered The very fact that the Bank sent no reply to the workman's notice raised strong inference that its plea of offering alternate job of Messenger to the workman has not an iota of truth. This plea is an after thought.

Admittedly, the workman has been reemployed by the Bank as Messenger on 18-11-75 at Sikar Branch. Had the offer of this job been made to the workman on 1-8-74, he would have accepted it as he has accepted on 18-11-75. This fact also speaks volumes against the Bank. There is thus no substance in the Bank's plea that it offered the job of Messenger to the workman on 1-8-74 and he refused it.

I have held above that the workman worked continuously for one year as defined in S- 25-B of the Act. Sec. 25-F of the Act lays down the conditions precedent to retrenchment of workman. The provisions of S. 25-F make it amply clear that no workman shall be retrenched until ; (1) he has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment or wages in lieu of such notice, (2) payment of compensation equivalent to 15 days average pay for every completed year and continuous service or any part thereof in excess of six months ; and (3) notice to the appropriate Government in the prescribed manner.

In the instant case, the workman was not given one month's notice in writing or the wages in lieu of such notice. He was also not paid the compensation equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months. Any retrenchment, which contravenes the provisions of S 25-F is illegal and cannot be given effect to The provisions of S. 25-F were recently considered by the Hon'ble Supreme Court in AIR 1976 S. C. 1111 and AIR 1977 S.C. 31. It was laid down in these authorities that when the retrenchment is in contravention of Sec. 25-F, it is illegal. It was further held in these authorities that when the retrenchment is illegal, the relief available to the workman, who was victim of the illegal retrenchment, is his reinstatement with full back wages. The retrenchment of the workman, Shri Gopal Singh, is illegal, because his retrenchment was in direct violation and contravention of the mandatory provisions of S. 25-F of the Act.

Learned representative for the Bank contended vehemently that back wages should not be allowed to the workman. It was argued that the workman did not adduce evidence to show that he remained unemployed since 1-8-74 to 17-11-75 when he was given fresh appointment by the Bank. I find no force in the contention. In the written statement, the Bank did not raise the allegation that the workman sought any employment from 1-8-74 to 17-11-75. The workman was also not cross-examined on this point. As such, he is entitled to get full back wages from 1-8-74 to 17-11-75 and the difference in wages from 18-11-75 till his reinstatement on the post of Godown-Darban, or any other equivalent post.

I, therefore, pass the following award :—

1. The retrenchment of the workman, Shri Gopal Singh was illegal, and

2. He will be forthwith re-instated with full back wages. He will get full back wages from 1-8-74 to 17-11-75 ;

3. He will further get the difference in between the pay scales of Godown Darban and Messenger from 18-11-75 till he is re-instated by the Bank.

The award is submitted to the Central Government for publication.

S. S. BYAS, Judge, Presiding Officer

[F. No. L-12012/141/75-D. II. A]

R. P. NARULA, Under Secy.

New Delhi, the 7th June, 1977

S.O. 2131.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Moonidih Project of National Coal Development Corporation, Limited, P.O. Moonidih (Dhanbad) and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th June, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(i)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 14 of 1977

(Ministry's Order No. L-2012/15/74-LRII, dated 3-2-1975)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Moonidih Project of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Moonidih (Dhanbad)

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen—Shri Lalit Burman, Secretary, United Coal Workers' Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Project.

Dhanbad, dated, the 1st June, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, referred the following dispute for adjudication to Tribunal No. 2, Dhanbad, by Government of India, Ministry of Labour, Order No. L-2012/15/74-LRII, dated, the 3rd February, 1975, namely :—

"(i) Whether the management of Moonidih Project of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Moonidih (Dhanbad) are justified in paying Category I wages to Sarva Shri (1) Bindeswari Gope, (2) Sukhdeo Gope, (3) Aklu Mahato (4) Chhabinath Mahato, (5) Kalachand Gope (6) Jadu Gope, (7) Fantush Mahato, (8) Yudhisthir Karmakar and (9) Bhim Gorai, Tyndal Mistries (Category IV) ? If not, to what relief are they entitled and from which date ?

(ii) Whether the management of Moonidih Project of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Moonidih (Dhanbad) are justified in not paying Project Allowance @ Rs. 7½% of their basic wages to weekly paid employees of the establishment in comparison with the monthly paid employees ? If not, to what relief are the weekly paid employees entitled and from which date ?"

2. The same was received by transfer from that Tribunal in this Tribunal on March 17, 1977, vide Government of India, Ministry of Labour, Order No. S-11025/1/77(i)/D-IV(B), dated the 22nd February, 1977.

3. There are two points in dispute between the management of the Moonidih Project and the United Coal Workers' Union, Moonidih Branch. The first dispute relates to the proper classification of 9 workmen and the second dispute is in respect of payment of Project Allowance to all the workmen employed in the Moonidih Project. I propose to deal with these disputes in seriatim.

4. Bindeshwari Gope, Sukhdeo Gope, Aklu Mahato, Chhabinath Mahato, Kala Chand Gope, Jadu Gope, Fantush Mahato, Yudhisthir Karmakar, Bhim Gorai, Sudun Mahato, Lattu Mahato, Deo Muni Mahato and Jagdish Mahato claimed that they were being designated and shown as General Mazdoors, Category-I, in the Moonidih Project and were being paid Category I wages even though they were actually performing the duties of Tyndals "Heavy" category IV and were entitled to category IV wages. Their cause was taken up by the Secretary, United Coal Workers, Union, Moonidih Branch with the Project Officer, Moonidih Project on February 27, 1973 by the letter Ext. W-1. The demand received no satisfaction and, therefore, the Union served a strike notice Ext. M-1 on the Project Officer on December 24, 1973 of their intention to go on a strike from January 14, 1974. The strike notice was accompanied by a Charter of 25 demands. Demand No. 4 reads thus : "Tyndal Mazdoors at present are being paid at the rate of Category I only being designated as General Mazdoors. All such workmen should be given the due designation of Tyndal Mazdoor and be placed in Category V". The A.L.C.(C) called for the comments of the Project Officer on the charter of demands. Ext. M-2 dated February 2, 1974 contain the comments of the Moonidih Project on these 25 demands. With regard to demand No. 4, the comments are as follows : "The statement is not correct. Person performing the job of Tyndal has been placed in Category IV. The demand is vague. The Union is requested to submit specific names for the consideration of the management." The Union was thereupon required to offer its comments on the comments of the management. The Union's comments are contained in Ext. W-2 dated February 14, 1974. The comments are "The specific cases of the concerned Tyndals (now kept in Category I as General Mazdoors) was earlier forwarded to the management vide union's letter No. CWD/MND/10/73, dated 27-2-1973. For ready reference the names are given below again." Nine names were given and the names of Sudan Mahato, Lattu Mahato, Deo Muni Mahato and Jagdish Mahato were omitted because admittedly after the service of Ext. W-1 and before the date of the comments, these four had been promoted by the Project Officer as Tyndals, Cat. IV. The dispute thus is confined to the remaining nine whose names are specified in item No. 1, of the Schedule to the reference.

5. In addition to the above historical back-ground, we have the pleadings of the parties. The case of the nine workmen is that the thirteen, including them, had been performing for quite a long time the job of handling heavy machineries, Cable drums and other heavy materials from stores to pits and to places of underground workings and of assisting Electrical and Mechanical Fitters in their job of shifting, installing and dismantaling of machineries and materials in the mine, all of which are jobs of Heavy Tyndals who are time-rated Cetagory IV workmen, but the management was treating them as General Mazdoors who are time-rated Category I workmen. They further alleged that their Union made a demand on February 27, 1973 for the proper classification of these thirteen as Category IV workmen but the management classified four of them as Category IV workmen but did not accept the demand in respect of the remaining nine. Their Union then gave a strike notice on February 4, 1974 and the charter of demands included the demand for their proper classification. Their prayer is that since the demand was rejected by the management, the Tribunal should accept it and direct their classification as Heavy Tynadals, Category IV. The management, in its written statement, has admitted the receipt of the demand letter Ext. W-1 and the strike notice Ext. M-1 and pleaded that since the demand was vague, it was opposed in the conciliation proceedings and is opposed now. It has been further pleaded that the demand made was for classification in Category V and the industrial dispute raised and referred is for classification in Category IV and this makes it amply clear that the industrial dispute referred is wholly different from the industrial dispute raised and as such the Tribunal has no jurisdiction to decide the dispute that has been referred. It is then pleaded that these nine workmen have never worked as Heavy Tyndals/Tyndal Mistries and the management is justified in refusing to classify them as Category IV workmen The management filed a rejoinder also to the written statement of the workmen. In that, it is stated that four out of the thirteen were found to be working as Heavy Tyndals and their demand was accepted and they were classified as Category IV workmen but these nine were only working as General Mazdoors and were not assigned the duties of handling heavy machineries, cable drums and other heavy materials from stores to pits and to places of underground workings and they were not assisting Mechanical or Electrical Fitters in shifting, installing and dismantaling machineries and other materials, jobs which are done by Heavy Tyndals and, therefore, their demand for classification as Heavy Tyndals, Category IV, is unjustified. The Union also filed a rejoinder to the written statement of the management, in which the original pleas have been repeated and it has been contended that there was neither any vagueness about nor any difference between the original demand made and the industrial dispute referred and the Tribunal has the jurisdiction to decide the dispute.

6. Before entering into the controversy, I would like to give certain facts which are not disputed, and are indeed, indisputable. Chapter VIII—Section-A, Vol, I of the Report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry deals with time-rated categories. In paragraph 15 of Chapter VIII—Section-A, the Board classified time-rated workmen into six categories. In paragraph 16, the Board mentioned that their recommenations for fitting existing workmen into the new six categories together with the nomenclatures and their job discriptions are contained in Appendix V to their report. Item No. 3 of Category I in Appendix V, relates to "Fitters". It mentions that a fitter is a workman who accompanies a Fitter/Electrician/Carpenter etc. and carries tools or materials. Admittedly, these nine workmen have been classified as Category I workmen under this item. Item No. 22 of Category II, Appendix V refers to "Fitter Helper" as a man who has gained some experience as a Fitter Mazdoor and has improved status by practice until he can do elementary fitting work. He may be a mechanical or electrical helper as the case may be. Item No. 5 of Category IV, Appendix V concerns Tyndals. A Tyndal is a man generally employed in moving engineering stores, drums of Oil and greases. He is also responsible for erection, dismantaling of structures and installation and withdrawal of machinery. Item No. 1 of Category V, Appendix V, deals with a Tyndal Supervisor. He is a man experienced in handling materials and in engineering structures who is incharge of a gang of Tyndals (Heavy). The claim of these nine workmen is for classification under item No. V of Category IV. Para 19 of Chapter VIII—Section-A gives the wages of the workmen belonging to the six categories. The daily minimum wage of a Category I workman is Rs. 5. There is an annual increment of 10 paise per day and the maximum daily wage rises to Rs. 6 in a span of 10 years. The daily minimum wage of a Category IV workman is Rs. 6.90 There is an annual increment of 20 paise per day and the maximum daily wage rises to Rs. 8.90 in a duration of 10 years. The wages have been revised with effect from January 1, 1975 by the Joint Bi-partite Wage Negotiating Committee. The revised rate of Category I is Rs. 10 which rises to Rs. 12 in 10 years with an annual increment of 20 paise per day. The revised rate of Category IV workman is Rs. 12.75 which rises to Rs. 16.85 in 10 years with an annual increment of 41 paise per day.

7. I have to see whether these nine workmen are General Mazdoors (Fitters) mentioned at item No. 3 of Category I in Appendix V or they are Tyndals mentioned at item No. 5 of Category IV in Appendix V. This is a question of fact. I have also to see whether the dispute referred is different from the industrial disputes raised.

8. I will dispose of the second question first. I do not think there is any vagueness or indefiniteness about the dispute. In Ext. W-1, the demand was made for classification of thirteen workmen in Category IV in place of their existing classification in Category I. The management accepted the demand and classified four out of thirteen as Category IV workmen. The dispute in respect of these four, therefore, came to an end. The strike notice certainly did not specify the names of the remaining nine and that was the reason why the management took the stand before the A.L.C. that demand No. 4 in the charter of demands was vague. This, to my mind, was an untenable stand. The management should have known as to who the workman were because they were in possession of Ext. W-1 from February 27, 1973 which contained the names of all the thirteen workmen. Again, they knew that they had promoted four and thus they could have worked out who the remaining nine were. In any case, the names of these nine were repeated by the Union in their comments Ext. W-2. There is thus no vagueness about the names. Likewise, I do not think that the dispute referred is different from the dispute raised. The dispute was for proper classification of nine workmen from their jobs of General Mazdoors to the jobs of Tyndals "Heavy". In the demand Ext. W-1, the category given was category IV. It is only in the charter of demands that by inadvertence the category mentioned was Category V and not Category IV. Category V, as has been seen above, refers to Tyndal Supervisors who is the leader of a gang of Heavy Tyndals. Obviously, these nine did not claim classification as Tyndal Supervisors but only as Heavy Tyndals which is covered by item No. 5 of Category IV. No party was ever in doubt as to the real nature of the demand; and in any case social justice does not favour such hair-splitting contentions. I, therefore, hold that the Tribunal has the jurisdiction to decide the dispute about proper classification.

9. There is both oral and documentary evidence about the nature of the job being performed by these nine, and the truth has to be found out on the basis of this evidence. MW-1 K. Bagchi is the Senior Executive Engineer, Electrical and Mechanical, in the Moonidih Project. He has deposed that these nine assist fitters as Fitter Mazdoors and they are Category I workmen and are shown as such in their service records from the respective dates of their initial appointments. He has further deposed that they do not handle heavy machineries, cable drums and other heavy materials from stores to pits or to places of underground workings; and they do not dismantle machineries and other materials, used in the mine. He has then deposed that there is a separate gang of mazdoors and drifting coal face miners who do the job of handling heavy machineries, cable drums and other materials and of dismantling machineries. He has finally deposed that these nine are not Heavy Tyndals or Tyndal Mistries. In cross-examination, he clarified the position by stating that fitter mazdoors, like these nine, are associated with the fitters for the purpose of carrying tools, tightening nuts and bolts, handling wrenches and helping them in the maintenance of machineries and electrical apparatus. Fitters-helpers are different from Fitter Mazdoors. Fitter-helpers do the same job which are done by Fitter-Mazdoors, but they are more experienced in doing the job. He has denied that these nine work as light or heavy Tyndals and has stated that the job of handling heavy machineries is being carried on not by them but by Shaft-Sinking Miners. As against his evidence, we have the evidence of S. N. Singh WW-1, an Electrician; Kalachand Gope WW-2, one of the concerned workmen; and Shridhar Chandra Roy WW-3, Electrical Chargeman. S. N. Singh has deposed that these nine do the job of transporting gear boxes of conveyor motors, heavy pumps, cables and other heavy materials. In cross-examination, he has said that there are two separate departments, namely, Electrical Engineering Department and Mechanical Engineering Department. He has then stated that these nine work in the Electrical Engineering Department. I do not think that he has given a correct statement that these nine work in the Electrical Engineering Department. He has admitted that gear boxes and conveyor pans are required by the Mechanical Engineering Department; and if that be so, these nine, assuming that they carry gear boxes and conveyor pans, would be working in the Mechanical Engineering Department and not in the Electrical Engineering Department. The witness is the Secretary of the Union and had sponsored the cause of these nine. He had also taken active part in the conciliation proceedings and in connection with the strike notice. His evidence appears to be highly interested. Kalachand Gope admits that he was appointed as a General Mazdoor but says that he was asked to carry motors, cables, gear boxes and chains etc. from the surface to underground and also to places of work in underground. In cross-examination, he admitted that there are separate employees for shaft-sinking and it is these employees who carry goods from surface to underground. He went on to state that he and the other eight are fitters, and the duties of a fitter mazdoor is to carry tools used by fitters, while fitter-helpers help fitters in the actual job of fitting. Shridher Chandra Roy has deposed that these nine were engaged for transporting pans, gear boxes and other machineries used underground. He has further stated that he personally asked them to work on the said jobs. This does not appear to be correct because pans and gear boxes are not used in the Electrical Engineering Department. I am of the view that these nine workmen have magnified the nature of their duties in order to get the wages of Category IV workmen instead of the wages of Category I or II workmen. They would be interested in getting a high jump in the wages and may not be willing to tell the truth. WW-1 and WW-3 are thick and thin with them and are likely to fall in line with them. MW-1 K. Bagchi is an independent person and responsible officer and is expected to tell the truth. I will, therefore, prefer to place reliance upon him, subject to his corroboration by documentary evidence.

10. Ext. M-26 to M-34 are the service records of these nine workmen. Ext. M-26 shows that Bindeswar Gope was appointed on April 8, 1968; Ext. M-27 shows that Sukhdeo Gope was appointed on June 9, 1969; Ext. M-28 shows that Chhabinath Mahato was also appointed on June 9, 1969; Ext. M-29 shows that Aklu Mahato was appointed on August 17 1970; Ext. M-30 shows that Bhim Gorai was appointed on July 19, 1971; Ext. M-31 shows that Yudhisthir Karmakar was also appointed on July 19, 1971; Ext. M-32 shows that Fantush Mahato was also appointed on July 19, 1971; Ext. M-33 shows that Kalachand Gope was appointed on June 21, 1971; and Ext. M-34 shows that Jadu Gope was also appointed on June 21, 1971. They were appointed in the shaft-sinking department. Their work was on the surface of the mine, with the exception of Yudhisthir Karmakar and Fantush Mahato whose place of work was underground. They were all appointed as miscellaneous mazdoors in Category I. Bindeswar Gope, Sukhdeo Gope and Chhabinath were promoted as Category II workmen with effect from January 1, 1974 but the remaining six continue as Category I workmen. Admittedly, therefore, at least three of them are no longer Category I workmen and are, indeed, Category II workmen, i.e., instead of being fitters under item no. 3 of Category I in Appendix V, they have become fitter-helpers under item no. 22 of Category II in Appendix V. Exts. M-35 to M-42 are weekly wage-sheets for the week ending January 19, 1974, May 11, 1974, May 25, 1974, October 26, 1974, November 23, 1974, January 18, 1975 and March 11, 1975 respectively. These wage-sheets show that in addition to Bindeswar Gope, Sukhdeo Gope and Chhabinath Mahato, there is one more who was working as a fitter-helper, and he is Aklu Mahato. He should also have been treated, therefore, as a fitter-helper, Category II and not as a fitter Category I. It is true that Ext. M-35 shows that Chhabinath received the wages of a Tyndal, Category IV but that, to my mind, will not make any difference in his status as a fitter-helper because he received the wages of a Tyndal only for three days and that may have been so because he might have worked as a Tyndal on these three dates. That, however, will not confer a right on him to be categorised as a Tyndal Category IV and paid the wages of a Category IV workman.

11. With regard to the first dispute, therefore, my finding is that none of these nine workmen is a Tyndal and consequently none of them is entitled to be categorised as a Tyndal, Category IV and that Bindeswar Gope, Sukhdeo Gope, Chhabinath Mahato and Aklu Mahato are not fitters, Category I but fitter-helpers, Category II from January 1, 1974 and like the other three Aklu Mahato is also entitled to be paid wages of Category II from January 1, 1974.

12. I will now take up the second dispute.

13. Before the nationalisation of non-coking and coking coal mines; there were hundreds of such mines in the private sector commonly known as market collieries, and in addition to them, there were 11 State Collieries.

Eight such State Collieries were in Bihar, two in Orissa and one in Madhya Pradesh They were owned by the Government of India, Ministry of Production and upto May 31, 1944 were managed by the Railway Board Hence, all those persons who were in service in the State Collieries on May 31, 1944 were governed by the Railway Service Rules and were allowed the benefits of the Railway Provident Fund, Gratuity or special Provident Fund special cheap foodgrains, rent free houses, free electricity, free Railway passes and P T O s From June 1, 1944 the management of the State Collieries was transferred to the Department of Supply and subsequently to the Ministry of Production All employees who entered service on or after June 1, 1944 were governed by the Civil Rules applicable to all other civil employees of the Central Government The Civil employees did not get the benefits which the pre-first June, 1944 employee were entitled to under the Railway Service Rules but were entitled to all the conditions of service which were applicable to similarly situated staff in the Central Government Department What were known as the Sate Collieries, were taken over by the National Coal Development Corporation, a wholly owned Government of India undertaking on its formation on October 1, 1956 The N C D C inherited (1) officers (2) monthly rated staff, (3) daily rated workmen and (4) piece-rated workmen on the date of its corporation The pay structure and other service conditions of the officers and the monthly-rated staff continued to be governed by the Railway Service Rules or the Civil Rules, depending upon the fact whether they were pre-first June, 1944 employees or post-first-June 1944 employees They had ceased to be Government servants on their absorption by he N C D C but their conditions of service including pensionary benefits, remained untouched Their pay scales were revised by the N C D C from time to time in accordance with the recommendations of the Central Pay Commission 1949 or the Second Central Pay Commission, 1959, to the extent that these recommendations were accepted by the Government of India As and when the necessity for fresh appointments arose in respect of any of the aforesaid categories, the N C D C appointed officers monthly-rated staff, daily-rated workmen and piece rated workmen These can be termed as Corporation employees The N C D C framed new rules governing their conditions of service but allowed them all the Civil Service benefits at par with their counterparts in other Central Government Departments except in the matter of pensionary benefits The N C D C introduced a Contributory Provident Fund Scheme for their monthly rated staff who were required to contribute at 8/1/3 per cent of their Basic Pay into the fund and the N C D C had also to contribute to the same extent It also introduced a Gratuity Scheme for the newly appointed monthly-rated staff The recommendations of the Central Coal Wage Board for the Coal Mining Industry came into force on August 15 1967 The Board recommended that the monhtly paid staff should be given their choice of either being on their existing pay-scales which were generally in conformity with the Government of India employees or opt for the wage scales and other benefits recommended by the Board for the industry as a whole In this connection reference may be invited to Chapter VIII—Section B of Vol I of the Board's report The Board recommended that the monthly paid staff of N C D C who were then governed by the Central Pay Commission s scale of pay Railway Service Rules Corporation Rules or any other rules should be allowed to opt for the scales of pay and other service conditions recommended by it for similar monthly rated staff in the private sector collieries Such an option was accordingly given and practically all of the opted for the pay scales recommended by the Wage Board The option was made applicable by the N C D C to the employees governed by the Railway Service Rules the Civil Rules Corporation Rules and also to fresh recruits who were recruited after August 15 1967 The above facts will appear from the deposition of Sri R S Murthy, Chief Personnel Officer Central Coalfields Limited (formerly the N C D C) A change occurred in the year 1973 when the Moonidih Project (with which we are concerned in this dispute) was transferred to the management of the B C C L In 1975 the ownership was also transferred to the B C C L The B C C L drafted officers monthly-rated staff daily-rated workmen and piece rated workmen from other collieries under its ownership to the Moonidhi Project in addition to the strength already employed there They were in receipt of pay and were governed by conditions of service prevailing in the B C C L, or by scales of pay and conditions of service laid down by the Coal Wage Board or by the Joint Bi Partite wage Negotiating Committee by an agreement dated December 11 1974 which came into effect on January 1 1975 The above facts will show that though the pattern of categorisation remained the same throughout, the employees were either governed by Railway Service Rules or by Civil Rules, or by Corporation Rules by B C C L Rules or by various recommendations of Wage Boards

14 Central Government employees working at undeveloped and out of the way places in connection with the construction of major projects are granted a Project or Construction allowance The allowance is given in respect of Central Government projects and also at places where there may be State Government projects It is intended primarily to compensate the staff for the lack of amenities such as housing, schools markets, dispensaries at the project sites The allowance is withdrawn in a phased manner as and when the various amenities become available at or near the project site The phased withdrawal usually takes places over a period of three years Generally, the allowance is sanctioned only for large projects which involve the establishment of a large organisation and where the construction is spread over a number of year Only such of the staff as are employed on the project and reside within the project area or in a nearby locality, are eligible for grant of this allowance It may also be granted to such Central Government staff of other departments as have their offices located in the project area, for the work of the project, provided they also reside within the project area or in a nearby locality No specific rates for the grant of the allowance have been prescribed, but it is subject to certain ceilings The process of withdrawal of the project allowance in a phased manner should begin only after certain amenities by way of provision of schools, markets, medical facilities and reasonable housing facilities have become available within the project area or in its proximity The phased reduction in the quantum of the project allowance or its final withdrawal should be linked with the progress made with the provision of the above mentioned facilities and amenities I have quoted the above passage from paragraphs 62 and 65 of Chapter 56 of Vol IV of the Third Central Pay Commission Report, in order to give a picture of the reason why a project or construction allowance is given

15 The N C D C discovered new coal mines or took in hand the development of known reserves with a view to convert them into working coal mines These fresh ventures are known as projects Work is usually started from a scratch and progresses by removal of over-burden, sinking of shafts, making of inclines, installation of machineries and electric fitting and preparation of working faces for the actual extraction of coal Generally speaking, land is acquired from owners in villages and staff is posted to undertake the job of setting up a coal mine It takes a few years to make the place ready for extraction When the venture is taken in hand, there is lack of basic amenities like water supply, or filtered water supply, electricity, housing, schools, markets, hospitals/dispensaries and the like Those who are uprooted from their jobs at developed places and transferred to project sites naturally have to face the aforesaid difficulties not only in respect of themselves but also in respect of their family members and dependents In order to compensate them for this, they are given the project allowance at certain rates with certain ceilings As and when, one or more of the facilities become available, the rate of the allowance is reduced and when all the facilities become available the allowance is wholly withdrawn It is the general policy to recruit daily rated and piece-rated workmen locally In doing so, the first preference is given to those whose lands have been acquired for the project area and then to those whose lands have not been acquired but who are locals, and lastly, if there is still room for more, to outsiders whether by way of fresh recruitment or by transfer of existing hands

16 I will now refer to the office Memorandum issued by the Central Government regarding the general principles which govern the grant of project allowance to the staff employed on construction projects The first O M No F 7(4) FII(B)/60 dated the 23rd March, 1960 issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) It

deals with (a) cases in which the project allowance will be admissible, (b) the reason for the grant, (c) persons who will be eligible for the grant, (d) persons who will not be eligible for the grant, (e) rate of the allowance and ceiling thereon, (f) reduction and withdrawal of the grant and (g) its applicability to Corporations/Companies. The Office Memorandum says that the project allowance is to be given only for large-scale projects and not for the construction of individual buildings. It will not be admissible except in such projects which have been declared by special orders of Government as qualifying for grant of the same. Generally, the allowance will be sanctioned only if the execution of the project involves the establishment of a large construction organisation and the construction is spread over a number of years. The allowance is intended primarily to compensate the staff for lack of amenities such as, housing, schools, markets, dispensaries etc. Where reasonable amenities already exist, there would be no justification for the grant of the allowance. The allowance will not be admissible to staff recruited locally on ad-hoc scales of pay such as daily-rated or casual labour and staff paid from contingency. The allowance will be admissible only to such staff as are employed on the project and reside within the project area or in a nearby locality. The allwance may also be granted to such Central Government staff of other departments as have their Officers located in the project area for the work of the project, provided that they reside within the project area or in a nearly locality. The term "project area" will be the area defined as such by Government in respect of each project for which the project allowance is sanctioned. The project allowance shall be subject to the following ceilings :

Pay		Rate
Below Rs. 275		25% of pay.
From Rs. 275 upto 500	—	20% of pay with a minimum of Rs. 70 per month.
From Rs. 600 upto 1200	—	Rs. 125/- per month.
From Rs. 1300 upto 1500	—	Rs. 150/- per month.
From Rs. 1600 upto 1740	—	Equal to the amount by which pay falls short of Rs. 1740.
Rs. 1750 and above	—	Nil.

The Government will fix the quantum of the allowance at the time of sanctioning it and also each time it is revised. The continuance of the allowance would not be justified for the regular staff of the project when the necessary amenities have been provided in the project area. Hence, the allowance sanctioned originally for such staff shall be reduced in stages as the necessary amenities are provided, until it is withdrawn finally. As an exception, in the case of temporary construction staff who have not been absorbed finally in the project on a regular basis, the allowance may be continued on a reduced scale until such staff are finally discharged, so long as construction of any magniture goes on. The principles mentioned above which apply to projects run by Government departmentally may also be communicated to Companies/Corporation etc. under the Ministry of Commerce and Industry etc. for information and guidance.

17. The above O.M. was acted upon by the N.C.D.C. also. Certain aspects of the scheme of project allowance came up for clarification or interpretation. Item No. 5 of Para 4 of Office Order No. 10(15)/10/NCDC/P. ALLOW/60 dated March 2, 1962 mentioned that no project allowance will be admissible to persons recruited locally. Clarifications were sought as to the meaning of the expression "locally recruited". The clarification was issued by the Dy. Director (Administration) on June 7, 1962 by letter No. 10(15)/10 NCDC/P. ALLOW/60 dated June 7, 1962 which stated that "local recruits" will mean persons who are original inhabitants within the radius of 5 miles of the project area and who have been recruited locally. See Ext. M-9. There are some documents which show that the N.C.D.C. paid the project allowance only to officers and monthly rated staff and not to daily-rated or piece-rated workmen. Ex. M-18 is a note prepared for the 55th Meeting of the Board of Directors scheduled for February 15, 1962. It mentions that no project allowance was admissible to persons recruited locally. Ext. M-17 contains the minutes of the meeting of the Board of Directors held on February 15, 1962 and shows that it was decided that no project allowance will be admissible to persons recruited locally. Ex. M-19 dated March 2, 1966 is a letter from the Administrative Officer to the Personnel Officer enquiring whether the personnel who were previously recruited in a project but were subsequently transferred to a far away place and then re-transferred to the locality where they had been recruited, were eligible for the project allowance or not. Ex. M-10 is the reply given by the Chief Personnel Officer to the Administrative Officer on April 26, 1966 which says that such of the employees who had been transferred to their local places and were residing within 5 miles radius of the project area, were not entitled to the project allowance even though they might have been in receipt of the allowance in their former place of posting. Likewise, there are certain documents which will go to show that the project allowance was given only to officers and monthly-rated staff. Ex. M-17 are the Minutes of the 55th Meeting of the Board of Directors, referred to above, which indicate that the allowance was given only to officers and monthly rated staff. Ex. M-7 is the Office Order No. 10 (15)/10/NCID/P. A./60/Pt. 1 dated the 4th March, 1964 which directs that the project allowance was being granted to officers and monthly paid staff posted to the Churcha Project. Ext. M-14 is another office order of even number dated July 10, 1964 maintaining the status que with regard to the grant of the allowance to the officers and monthly paid staff employed in 31 projects, including the Moonidih Project, specified at serial no. 18. That the Office Memorandum issued by the Ministry of Finance was acted upon by the N.C.D.C. in respect of phased reduction and withdrawal of the allowance is also supported by various documents. Ext. M-18 (the note prepared for the 55th Meeting) proposed the continuance of the reduced rate in the Korba Project and Ext. M-17 is the Minutes of the Meeting confirming the proposal. Ext. M-8 contains the scheme for the progressive withdrawal of the project allowance. The scheme provides for a 50 per cent reduction in the project allowance once an employee was given a house with water, light and internal sanitation. This, in effect, meant that once a pukka house was allotted with water, light and internal sanitation, there was a minimum reduction of 50 per cent of the project allowance in respect of the individual to whom the house was allotted while other employees who may not have been allotted houses would continue to be entitled to the full project allowance till such time as they were allotted houses with the necessary facilities of water, light and internal sanitation. The scheme further provided that a further 25 per cent reduction would be effected on completion of hospitals, schools and markets. This meant that once these amenities were provided, those already given houses will have a further reduction of 25 per cent in the project allowance, while those who may not have been allotted houses would, in any case, have to accept a reduction of 25 per cent. The scheme further provides that once filtered water supply, and Workers Institutes and hospitals in terms of the rules of the Coal Mines Welfare Commissioner are provided, the project allowance will be fully withdrawn and would be applicable to all employees even if some of the employees have not occupied Corporation quarters. Ext. M-6 Office Order No. 13, 1964 defines "house", "hospital", "school" and "filtered water". It further mentions that the reduction of 25 per cent with regard to filtered water, Workers Institute and hospital, will comprise 15 per cent for the provision of the amenity of filtered water supply and 10 per cent for Workers Institute and hospital, but no cut of 10 per cent will be made where only one of these two amenities, namely, Workers Institute or hospital is provided. Ext. M-11 dated December 18, 1964 shows that where house and filtered water were supplied the project allowance was reduced by 65 per cent. Ext. M-16 dated June 10, 1966 also shows the same facts. Ext. M-12 is not relevant as it deals with amenities or lack of them not in project areas but in regular collieries.

18. The above discussion will show that the Office Memorandum issued by the Ministry of Finance was followed by the N.C.D.C. in respect of grant of project allowance, at full rates or at reduced rates or in the matter of its complete withdrawal, as circumstances and occasion demanded. It further shows that the grant was confined to the officers and monthly-rated staff.

19. The above Office Memorandum was superseded by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. 20011/5/73-EIV(B) dated January

17, 1975. The directions newly issued with regard to cases in which the allowance will be admissible, and the reasons for grant are substantially the same. In respect of the persons who will not be eligible for the allowance, it would be remembered that under the first Office Memorandum, it was not admissible to staff recruited locally and under the second Memorandum, the word "locally" has been deleted but in other respects, the new directions are the same. In respect of persons to whom the allowance would be admissible, the directions under the second Office Memorandum are substantially the same but it is mentioned that as an exception, the allowance may also be granted to an employee residing outside the project area, but subject to the following conditions : (a) he should be residing outside the project area due to the non-availability of residential accommodation in the area and not because such an arrangement is more convenient to him, and (b) no facilities of free or subsidised transport is available to such employee for journeys to and from the project. In respect of rate and ceiling, however, there is a marked difference. The project allowance under the new O.M. shall be subject to the following ceilings :

Upto Rs. 600/-	— 15 per cent per month.
601 to Rs. 700	— Rs. 100/- per month.
Rs. 701 to Rs. 1450	— Rs. 125/- per month.
Rs. 1451 to Rs. 1750	— Rs. 150/- per month.
Above Rs. 1750	— Marginal adjustment upto Rs. 1900/-.

In respect of reduction and withdrawal, the provisions are substantially the same. Likewise, in respect of aplicability to Companies/Corporations, there is no material difference in the two Office Memoranda.

20. I shall now discuss the evidence regarding the grant of Project Allowance in the Moonidih Project itself. MW-2 Sri R. S. Murthy deposed that the Moonidih Project was established in the year 1962. He then said that when a new project is started, daily-rated and piece-rated workmen are recruited from local villages and from amongst persons whose lands have been acquired for the project. Officers and monthly-rated staff are generally transferred to the Project site from other collieries. The Project Allowance was sanctioned by the N.C.D.C. on the pattern of such allowance admissible to Central Government employees posted in new project areas in order to give relief to them for the absence of housing, medical, marketing, schooling and other facilities. Those members of the staff who were governed by the Railway Service Rules or the Civil Rules were automatically given the allowance because of the protection given to their previous service conditions. The monthly-rated staff was given the allowance at 20 per cent of their pay as none of the facilities existed than in the project area. Later on, the quantum was reduced when some facilities became available. They were getting the allowance at 7 per cent of their basic pay at the time of his deposition. He further stated that when the management of the project was taken over by the B.C.C.L. in the year 1973 and when its ownership also passed to it in the year 1975, the B.C.C.L. transferred some monthly-rated staff to the Moonidih Project but the allowance was not given to such staff. He further stated that the allowance is not given to those workmen who reside in neighbouring villages within a radius of 5 miles. The evidence given by Shridhar Chandra Roy, Kala Chand Gope and S. N. Singh WW-3, WW-2 and WW-1 is not different.

21. According to R. S. Murthy, therefore, the project allowance is given only to officers and the monthly-rated staff who were originally governed by Railway Service Rules or by Civil Service Rules or by the Corporation Rules and not to the Monthly-rated staff transferred to or appointed by the B.C.C.L. for the Moonidih Project. It was never paid to other categories of staff also.

22. The question is whether there is any justification for denying the allowance to the excluded categories. Item No. 1 (iv) of the O.M. Ext.-20 dated January 17, 1975 specifically says that the allowance will be admissible only to such staff as are employed on the project and reside within the project area or in a nearby locality. The term "nearby locality" connotes a radius of 5 miles. That being so, each employee who is employed on the project and resides within the project area, demarcated for the purpose, or within a radius of 5 miles, automatically becomes eligible for grant of the allowance. All the workmen employed on the project will thus become eligible because it is not the case of the management that any of them is not employed on the project or does not reside within the project area or within a radius of 5 miles. It has, therefore, to be seen if inspite of this, they fall within the ambit of item No. 1(iii) which says that the allowance will not be admissible to staff recruited on ad-hoc scale of pay, such as daily rated or causal labour and staff paid from contingencies. The exclusion, therefore, depends upon the fact that an employee must be one who was appointed on an ad-hoc scale of pay. Now, there is nothing to show what is an ad-hoc scale of pay but let me assume that it is a tentative or a provisional scale and not a pre-determined or fixed scale. The workmen are governed by the Coal Wage Board recommendations and their categories and wages are fixed and, therefore, it cannot be said that they were recruited on ad-hoc scales of pay. There thus seems to be no justification for excluding them on the basis of Ext. M-20. However, Ext. M-20 fixed the project allowance for Government projects and not for Corporation/Company projects, though a choice was given to Corporation/Company to adopt the project allowance. The N.C.D.C. adopted, and in doing so, denied it to local recruits who were appointed on ad-hoc scales of pay. A local recruit is an original inhabitant of a village within a radius of 5 miles of the project area. It follows that if there are workmen who are original inhabitants of villages within a radius of 5 miles of the project area, they would be local recruits; and if, on the other hand, they are original inhabitants of villages outside the limit of 5 miles radius, they will not be local recruits and they will become eligible for the project allowance. The evidence shows that the strength of the monthly-rated staff in the Moonidih Project on April 1, 1974 was 286 which swelled to 326 on April 1, 1975 and to 380 on April 1, 1976. The strength of daily-rated and piece-rated workmen was 1300 on April 1, 1974 and it rose to 1800 on April 1, 1975 and to 2300 on April 1, 1976. See the evidence of MW-3 Hari Das. No evidence has been led on behalf of the management to show as to how many of the monthly-rated staff and as to how many of the daily and piece-rated workmen are local recruits and how many outsiders. The allowance can be denied only to local recruits and not to outsiders. It was the duty of the management to have given the break up. Ext. M-23 which gives the total man-power strength and not the break up is thus irrelevant. Sreedhar Chandra Roy W.W. 3 stated that 25 per cent of the man-power is locally recruited and 75 per cent are outsiders. W.W 2 Kalachand Gope has stated that the majority came from Varansi, Arrah, Giridih, and even from the States of West Bengal and Madras. These outsiders cannot be excluded from the grant of the project allowance. Besides, the grant of the allowance to one category of monthly-rated staff and to deny it to another category of the same kind of staff, will introduce an insidious distinction and cause heart-burning and industrial unrest. It is true that the management can lay down the policy to give it to one category and deny it to another but the classification must be rational and intelligible and not arbitrary. It denied the project allowance to local recruits and not to outsiders even though the latter be daily-raters and piece-raters. Likewise, if it grants the allowance to monthly-raters, it cannot be allowed to pick and choose and say that it would give it to one group and not to a second group, although both the groups are monthly-raters.

23. The learned counsel for the management gave several reasons why the project allowance is not being given to some categories indicated above. The first ground given is that the monthly-raters transferred or appointed by the B.C.C.L. for the Moonidih Project were not governed by the scheme of project allowance governing the old staff and, therefore, they cannot claim this allowance. I do not think there is any substance in this ground. If there is a project allowance given not in accordance with service conditions but in order to compensate for hardship, all those who have to face the hardships must suffer equally and must also gain equally. His second ground is that the management has not the financial capacity to pay the allowance to all its staff and workmen. W.W. 3 Hari Das deposed that if the allowance is given at 7 per cent of the basic pay to all the employees, the additional expenditure involved would be Rs. 6.62 lakhs in 1973-74; Rs. 8.64 lakhs in 1974-75 and Rs. 11.13 lakhs

in 1975-76. He further deposed that the project incurred a loss of Rs. 2.73 crores in 1973-74; Rs. 2.85 crores in 1974-75 and Rs. 3.17 crores in 1975-76. All capital projects require a heavy investment, which starts yielding profits after some years when production starts in full measure. Besides, if the project is prepared to incur loss and yet pay the allowance to some categories, it could as well pay to other categories also, or abrogate the allowance for all and not retain it for some and deny it to others. Again, the figures worked out include the figures for officers and monthly-rated staff to whom the allowance is already being given and these figures should have been excluded to find out the additional expenditure involved if the allowance is paid to those who are at present excluded. Another ground taken is that the daily and piece-rated workmen are entitled to the benefits of C.M.P.F. Scheme but the officers and monthly-rated staff are debarred from joining that scheme and thus if they lose in one matter, they gain in another. This ground is correct in part only. Clause (g) of para 2 of the C.M.P.F. Scheme excludes the old employees of the N.C.D.C. from the benefits of the Scheme. The daily and piece raters are, however, not excluded because they are governed by Coal Wage Board pay scales. They contribute at the rate of 8 per cent of their total wage-packet : Basic, D.A., V.D.A., U.G.A., O.T. etc—and the N.C.D.C. also makes a matching contribution. The N.C.D.C. has, however, its own separate P.F. Scheme for its officers and monthly-raters who contribute 8⅓ per cent of their basic wages only and the N.C.D.C. makes a matching contribution of its own. This is a very minor difference which can be ignored. Another ground taken is that whereas daily-raters and piece-raters have to pay a rent of Rs. 2 per month only for their quarters, an officer and a monthly-rater has to pay 10 per cent of his salary or the standard rent whichever is less and here also the daily and piece raters stand to gain. This ground has no substance whatsoever. The project allowance is given, inter alia, for the absence of housing facilities. Officers and monthly-raters, like daily-raters and piece-raters have not to pay any house rent, because there are no houses in the project area and if and when a house is provided, both have to pay, and the former gets a reduced allowance.

24. My award on the first dispute is that Bindeswari Gope, Sukhdeo Gope, Aklu Mahato, Chhabinath Mahato, Kalachand Gope, Jadu Gope, Funtush Mahato, Yudhistir Karmakar and Bhim Gorain are not Tyndal Mistries and are thus not entitled to wages of a Category IV workman. However, Bindeswari Gope, Sukhdeo Gope, Chhabinath Mahato and Aklu Mahato are Fitter-helpers, Category II and not Fitters, Category I. Bindeswari Gope, Sukhdeo Gope and Chhabinath Mahato have been accepted by the management as Category II workmen. Aklu Mahato is not being treated as Category II workman. He will be so treated and paid the wages of Category II from January 1, 1974 since which date he is working as a Fitter-helper. My award on the second dispute is that the project allowance will not be paid to such of the daily raters and piece-raters as are original inhabitants of villages within a radius of 5 miles of the project area. It will, however, be paid to such daily-raters and piece-raters as are not original inhabitants of villages within the radius of 5 miles of the project area. The management will work out the two categories to fix the persons to whom it will be paid and to whom it will not be paid. In order to ensure that the management is not saddled with a heavy financial commitment in respect of the previous years, I direct that the award in respect of the project allowance shall be enforceable from February 3, 1975 when the reference was made.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

[No. L-20012/15/74-I.R. II/D III A]

S.O. 2132.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chasnala Colliery of Messrs. Indian Iron and Steel Company Limited, P.O. Patherdih, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th May, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 35 of 1977

(Ministry's Order No. L-2012/179/74-LRII/DIIIA, Dt. 19-4-1975)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chasnala Colliery of Messrs. Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Patherdih, District Dhanbad.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri P. K. Bhandari, Personnel Officer.

For the Workmen.—Shri B. N. Sharma, President, Congres Mazdoor Sangh, Dhanbad.

State : Bihar. Industry : Coal.

Dhanbad, the 25th May, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act referred the following dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad by Order No. L-2012/179/74-LRII/DIIIA, dated, the 19th April, 1975, namely,

"1. Whether the management of Chasnala Colliery of Messrs. Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Patherdih, District Dhanbad, are justified in not making payment of overtime wages at 2-1/2 times normal rate of wages or 1-1/2 times normal rate of wages plus a compensatory day of rest for work done on Sunday, the common weekly rest day ? If not, to what relief are the workmen entitled to ?

2. Whether the management of Chasnala Colliery of Messrs. Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Patherdih, District Dhanbad, are justified in transferring Sarva Shri (i) D. D. Singh, Despatch Clerk, (ii) K. K. Chatterjee, Register Keeper, (iii) Mahabir Mahato, Weigh Bridge Clerk and (iv) R. K. Routh, Watchman, from 14-10-1974 ? If not to what relief are the workmen entitled ?"

2. While the reference was pending in Tribunal No. 2, the parties filed a settlement in respect of Issue No. 2 on September 16, 1976 and that settlement in Annexure 'A'.

3. The reference was received on transfer from Tribunal No. 2 in this Tribunal on March 22, 1977 vide Government on India, Ministry of Labour, Order No. S-11025(1)/77-(i)-D.iv(B) dated February 22, 1977. Here also the parties filed a second settlement with regard to Issue No. 1 and that settlement is Annexure 'B'.

4. Both the settlements have been duly verified by P. K. Bhandari on behalf of the management and by Shri B. N. Sharma on behalf of the Congress Mazdoor Sangh. The two mutual settlements appear to be for the benefit of both the parties and are, therefore, accepted by the Tribunal also.

5. My award is that the two disputes stand settled on the basis of the two settlements Annexure 'A' and 'B' which shall form part of the award.

K. B. SRIVASTAVA, Presding Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 43 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chasnala Colliery of M/s. Indian Iron and Steel Co. Ltd., P.O. Patherdih, Distt. Dhanbad.

AND

Their workmen.

Parties above named most respectfully beg to submit that in the above reference the issue No. 2, related to the dispute of transfer of S/Shri D. D. Singh, Despatch Clerk (ii) K. K. Chatterjee, Register Keeper (iii) Mahabir Mahato, weigh Bridge Clerk, (iv) R. K. Routh, Watchman.

That parties above named have settled the dispute on the following terms and conditions :—

1. That the Employers have agreed to transfer S/Shri D. D. Singh, Despatch Clerk (ii) Mahabir Mahato, Weigh Bridge Clerk, (iii) R. K. Routh, Watchman, **back to Chasnalla Colliery in their respective posts** with immediate effect.

2. That as issue No. 2 of the term of Reference have been settled amicably, Workman do not press the issue No. 2 for further adjudication as by now no Industrial Dispute exists on this issue.

Under the circumstances stated above, it is humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may be graciously pleased to pass an Award on the above terms and condition by accepting **the terms of settlement.**

Sd/-

(P. K. Bhandari)

Personnel Officer

On behalf of Employers.

Sd/-

(B. N. Sharma)

President

Congress Mazdoor Sangh, Jorapokhar

No. 1, Jealgora,

Distt. Dhanbad.

On behalf of Workmen

Dated, Dhanbad the 16th September, 1976.

ANNEXURE 'B'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, AT DHANBAD

Ref. No. 43/75
35/77

Employers in relation to the management of Chasnalla Colliery of M/s. Indian Iron & Steel Co. Ltd.

AND

Their workmen

The parties to the dispute beg to submit that they have already filed a settlement regarding item No. 2 of the Reference.

2. That negotiations were going on between the parties with a view to enter into amicable settlement in relation to item 2 as well.

3. That after prolonged negotiations and on consideration of the facts and circumstances, the parties have agreed to resolve dispute No. 1 in the following terms :—

(a) It is agreed that work done on Sunday, which is generally the recognised day of rest in the coal **mines in the Jharia Coal field, all workmen employed** on Sundays, apart from getting a weekly day of rest, shall be paid extra wages @ ½ times the normal rate of their wages. In other words for working on a Sunday the workmen shall get 1½ times the normal wages.

(b) That the above settlement shall be effective retrospectively from 20th April, 1977.

4. That thus, the disputes between the parties have been resolved to the fullest satisfaction of the parties.

It is, therefore, prayed that an Award may kindly be made in terms of the two settlements, as above.

Sd/- **Sd/-**

Illegible (P. K. Bhandari)

President P.O. Chasnalla.

For & on behalf of the workmen. For & on behalf of the Employers.

Dated : 21-5-1977

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-20012/179/74-LR. II/D. III(A)]

S.O. 2133.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chief Mining Engineer of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th May, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 19(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

C.G.I.T. No. 2—Reference No. 24 of 1973

C.G.I.T. No. 1—Reference No. 30 of 1977

(Ministry's Order No. L-2012/71/72-LRII, dated, 27-7-1973)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chief Mining Engineer of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba. Post Office Jamadoba, District Dhanbad

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri N. C. Ganguly, Advocate, and Sri L. H. Parvatiyar, Chief Personnel & Welfare Officer.

For the Workmen—Sri B. Joshi, Advocate, and Sri Janki Mahato, Vice-President, INMOSSA.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated, the 25th May, 1977

AWARD

The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act referred the following dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2 at Dhanbad by its Order No. L-2012/71/72-I RII, dated the 27th July, 1973, namely,

"Whether the management of Chief Mining Engineer of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jamadoba, District Dhanbad were justified in terminating the services of the following nine workmen from the date shown against their names and if not, to what relief the workmen are entitled ?

S.No.	Name of workmen	Designation.	Colliery in which worked.	Date of termination of Service.
1.	Shri S.B.Tiwari	Overman	Digwadih Colliery.	30.5.72
2.	Shri M.M.Choudhary	Overman	Malkera Colliery	30.5.72
3.	Shri A.T.Banerjee	Overman	Jamadoba 6/7 Pits	30.5.72
4.	Shri D.N.Pandey	Overman	Jamadoba 3/4 Pits	30.5.72
5.	Shri M.K.Roy.	Overman	Sijua Colliery	30.5.72
6.	Shri A.K.Mukherjee	Overman	Jamadoba Colliery	30.5.72
7.	Shri A.N.Misra	Ove man	Digwadih Colliery	25.12.72
8.	Shri B.C.Thakur	Overman	Jamadoba 6/7 Pits	26.12.72
9.	Shri Gupteshwar Choubey.	Mining Sirdar.	Jamadoba 6/7 Pits	26.12.72

2. The reference was received on transfer from Tribunal No. 2 in this Tribunal on March 22, 1977 vide Government of India, Ministry of Labour, Order No. S-11025(1)/77-(i)/D. iv(B) dated the 22nd February, 1977.

3. M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd. and the Vice Prsident, INMOSSA, have filed a settlement Annexure 'A' praying for a no dispute award. The settlement has been signed by Sri L. H. Parvatiyar, Chief Personnel & Welfare Officer and by Sri N. C. Ganguly, Advocate, on behalf of the management and by Sri Janki Mahato, Vice President, INMOSSA, and by Sri B. Joshi, Advocate, on behalf of INMOSSA. They have verified the settlement and also their signatures on it. The settlement appears to be in the interests of both the parties.

4. My award is that the dispute has been amicably settled and there is no further dispute left. The settlement Annexure 'A' shall form part of the award.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

ANNEXURE A

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT (NO. 1), DHANBAD

C.G.I.T. No. 1, Reference No. 30 of 1977

G.C.I.T. No. 2, Reference No. 24 of 1973

PARTIES

Employers in relation to M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamadoba, P.O. Jamadoba, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

The Parties to the present reference have settled their disputes arising out of the present reference on the following terms :—

TERMS

(1) That there is no dispute between the Parties which need further adjudication by the Honourable Tribunal since the workmen concerned are not interested in the services of the Opposite Party and they have already been gainfully employed elsewhere.

(2) That the Union has no further interest in the reference.

(3) That the Parties will bear their own respective cost of the present proceedings.

It is therefore, humbly prayed that the present settlement may kindly be accepted and a "No Dispute Award" may kindly be passed.

For the Employers.

Sd/-

(L. H. Parvatiyar)

25-5-77

C.P.W.O.

Sd/-

(N. C. Ganguly)

25-5-77

Advocate of Management

For the Workmen,

Sd/-

(Janki Mahato)

25-5-77

Vice -President of INMOSSA

Sd/-

(B. Joshi)

25-5-77

Advocate of Workmen.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-20012/71/72-LR.II/D. III(A)]

J. K. JAIN, Desk Officer

का०आ० 2134.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4861 तारीख 6 दिसम्बर, 1976 द्वारा सिक्युरिटि पेपर मिल, होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 6 दिसम्बर, 1976 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 जून, 1977 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11017/10/77/डी-Iए]

S.O. 2134.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4861 dated the 6th December, 1976 the Security Paper Mill, Hoshangabad, to be public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th December, 1976 ;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 18th June, 1977.

[No. S. 11017/10/77-DIA.]

का० आ० 2135.—केन्द्रीय सरकार के यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4862 तारीख 7 दिसम्बर, 1976 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख्ख) में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे बैंकिंग उद्योग को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर 1976 से छ मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून 1977 से छ मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० 11017/7/76-डी I (ए)]

एल० के० नारायणन, डेस्क अधिकारी

S.O. 2135.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S O 4862 dated the 7th December, 1976 the Banking Industry carried on by a banking company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 29th December, 1976,

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 29th June, 1977

[No S 11017/7/76/DI(A)]

L K NARAYANAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 जून, 1977

का० आ० 2136.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि मैसर्स हैंडलिंग प्लान्ट साइट वर्कशाप, विशाखापटनम, पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापटनम के कर्मचारियों को सारतः उसी प्रकार की प्रसुविधाएं अन्य रूप में प्राप्त हैं जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अगस्त 1969 से 21 सितम्बर, 1976 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है छूट देता है।

2 पूर्वोक्त छूट की शर्त निम्नलिखित है, अर्थात् —

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे उसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के अधीन उस उक्त अवधि की बाबत देनी थीं

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों का, जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है, या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से सम्बन्धित ऐसे लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वपेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट की मंजूरी के लिए नियोजक से अभ्यावेदन देर से प्राप्त हुआ था। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/29/76-एच०आई०]

New Delhi the 3rd June, 1977

S O. 2136.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Ore Handling Plant Site Workshop, Visakhapatnam Port Trust Visakhapatnam, are otherwise in respect of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the abovementioned factory from the operation of the said Act for the period from 1st August, 1969 upto and inclusive of the 24th September, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the request from the employer for the grant of exemption was received late. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/29/76-HI]

नई दिल्ली, 6 जून, 1977

का० आ० 2137.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1025 तारीख 26 मार्च, 1973 के अनुक्रम में केन्द्रीय कर्मशाला, लघु उद्योग सेवा संस्थान (औद्योगिक विकास विभाग, भारत सरकार) गुण्डी के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 7 अप्रैल, 1974 से 3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 6 अप्रैल, 1977 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे।

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी,—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसी किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से सम्बन्धित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे

निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते है; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि यह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट देने के लिए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने के नियमित कर्मचारियों को आरम्भ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान है और वे छूट के पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/8/77-एच०-I]

New Delhi, the 6th June, 1977

S.O. 2137.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1025 dated the 26th March, 1973 the Central Government hereby exempts the regular employees of the Central Workshop, Small Industries Service Institute (Ministry of Industrial Development, Government of India), Guindy, from the operation of the said Act for a further period of 3 years with effect from the 7th April, 1974 upto and inclusive of the 6th April, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees' State Insurance Corporation for the grant of exemption was received late. However, it is certified that the conditions under which the regular employees of the factory were initially granted exemption still persist and they are eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38011/8/77-HI]

का० आ० 2138.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2047 तारीख 15 मई, 1976 के अनुक्रम में केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 15 जून, 1976 से 30 अप्रैल, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए छूट देता है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी,

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि कारखाने को छूट देने के लिए महानिरीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को आरम्भ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान है और कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/9/77-एच-I]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th June, 1977

S.O. 2138.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2047 dated the 15th May, 1976, the Central Government hereby exempts the Central Scientific Instruments Organisaion, Chandigarh, from the operation of the said Act for a further period with effect from the 15th June, 1976 upto and inclusive of the 30th April, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees' State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No S. 38014/9/77-HI]

का० आ० 2139.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार मुद्रणालय कोयम्बटूर के कर्मचारियों को सारतः उसी प्रकार की प्रसुविधाएं अन्य रूप में प्राप्त है जैसी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2640 तारीख 7-9-1973 के अनुक्रम में कर्मचारी राज्य

बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 12 फरवरी 1974 से 30 अप्रैल 1977 तक की अवधि के लिए जिसमें 30 अप्रैल 1977 की तारीख सम्मिलित है छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं अर्थात —

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों का सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाना स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझता है या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति का जो ऐसे कारखाना, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी, है परीक्षा करना या

(घ) ऐसे कारखाना स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखा-बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि मंजूरी के लिए नियोजक का आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/14/76-एन्च I]

S.O. 2139—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Government of India Press, Coimbatore are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No S O 2640 dated the 7th September 1973 the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for the period from the 12th February 1974 upto and inclusive of the 30th April 1977

2 The above exemption is subject to the following conditions, namely —

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub section (1) of section 45 of the said Act or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub section (1) of section 44 for the said period, or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950 for the said period, or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification, or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary, or

(b) enter any factory establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary, or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory establishment office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee, or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the request of the employer for grant of exemption was received late. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/14/76-HI]

नई दिल्ली, 10 जून, 1977

का० आ० 2140.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारत अल्यूमिनियम उद्योग, 10/3, माल रोड, कलकत्ता-28 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017/23/76-पी०एफ०-2(i)]

New Delhi, the 10th June, 1977

S.O. 2140.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharat Aluminium Udyog, 10/3, Mall Road, Calcutta-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1975.

[No. S. 35017/23/76-PF. II(i)]

का० आ० 2141.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 दिसम्बर, 1975 से मैसर्स भारत अल्यूमीनियम उद्योग, 10/3, माल रोड, कलकत्ता-28, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35017/23/76-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 2141.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of December, 1975, the establishment known as Messrs Bharat Aluminium Udyog, 10/3, Mall Road, Calcutta-28, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/23/76-PF. II(ii)]

का० आ० 2142.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुन्दरबन लांच सिंडीकेट, चन्दपाल घाट, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017/24/77-पी०एफ०-2]

S.O. 2142.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sundarban Launch Syndicate, Chandpal Ghat, Strand Road, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35017/24/77-PF. II]

का० आ० 2143.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बांडोमोटर वर्क्स-2, राजा सुबोध मल्लिक एक्वायर, कलकत्ता-13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017/44/77-पी० एफ० 2]

S.O. 2143.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Bando Motors Works, 8 Raja Subodh Mallick Square, Calcutta-700013 have agreed that the Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S-35017(44)/77-P.F. II]

का०आ० 2144.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बारासात होलसेल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पोस्ट आफिस बारासात 25-परगना (पश्चिमी बंगाल) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए—

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1973 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं०एम०-35017/46/77-पी०एफ०-2]

S.O. 2144.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Barasat Wholesale Consumers Co-operative Society Limited, Post Office, Barasat, 24-Parganas (West Bengal), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1973:

[No. S. 35017/46/77-PF. II]

का०आ० 2145.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पटेल वेयर हाउसिंग कम्पनी 29 मुंशीगंज रोड, कलकत्ता-23 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जून 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017/47/77-पी०एफ० 2]

S.O. 2145.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Patel Warehousing Company, 29, Munshiganj Road, Calcutta-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1976.

[No. S. 35017/47/77-PF. II]

का०आ० 2146.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स परफैक्ट वाल्व्स एण्ड मशीन टूल्स कारपोरेशन, धरम चन्द इंडस्ट्रियल एस्टेट देवनार, चैम्पूर, मुम्बई-88. नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकतीस मार्च 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018/11/77-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 2146.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Perfect Valves and Machine Tools Corporation, Dharamchand Industrial Estate, Deonar, Chembur, Bombay-88, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1976.

[No. S. 35018/11/77-PF. II(i)]

का०आ० 2147.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात इकतीस मार्च 1976 से मैसर्स परफैक्ट वाल्व्स एण्ड मशीन टूल्स कारपोरेशन, धरम चन्द इंडस्ट्रियल एस्टेट, देवनार, चैम्पूर, मुम्बई-88 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं०एस-35018/11/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 2147.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of March, 1976, the establishment known as Messrs Perfect Valves and Machine Tools Corporation, Dharamchand Industrial Estate, Deonar, Chambur, Bombay-88, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/11/77-PF. II(ii)]

का०आ० 2148.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैमिलीना कारपोरेशन, 403, ग्रीन हाउस, ग्रीन फोर्ट बम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018/32/77-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 2148.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chemilina Corporation, 403, Green House, Green Street, Fort, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1976.

[No. S. 35018/32/77-PF. II(i)]

का०आ० 2149.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 अगस्त, 1976 से मैसर्स कैमिलीना कारपोरेशन, 403 ग्रीन हाउस, ग्रीन स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018(32)/77-पी०एफ०-2(ii)]

S.O. 2149.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of August, 1976, the establishment known as Messrs Chemilina Corporation, 403, Green House, Green Street, Fort, Bombay-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(32)/77-PF. II(ii)]

का०आ० 2150.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लिबर्टी हाइड्रालिक्स कम्पनी, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट, स्टेशन रोड भयन्दर (पश्चिम) जिला थाना, पश्चिमी रेलवे, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकतीस जुलाई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018/36/77-पी०एफ-2]

S.O. 2150.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Liberty Hydraulic Company, Laxmi Industrial Estate, Station Road, Bhayandar (West), District Thana, Western Railways, agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1976.

[No. S. 35018/36/77-PF. II]

का०आ० 2151.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम के इंजीनियरिंग, गोदावरी इंडस्ट्रियल एस्टेट, शेड सं० 2, ब्लाक सं० 6 भयन्दर (पश्चिम बंगा) जिला थाना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियमम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकत्तीस जलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०एस०-35018/37/77-पी०एफ०-2]

S.O. 2151.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Amkay Engineering, Godavari, Industrial Estate, Shed No. 2, Block No. 6, Bhayandar (West) District Thana, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1976.

[No. S. 35018/37/77-PF. II]

का०आ० 2152.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि गणपति कैरिज कारपोरेशन, 56/57, दूसरी मंजिल, बाम्बे म्युचुअल बिल्डिंग सर पी०एम० रोड मुम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018/39/77-पी०एफ-2]

S.O. 2152.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ganpati Carriage Corporation, 56/57, 2nd Floor, Bombay Mutual Building, Sir, P. M. Road, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No.S.35018/39/77-PF. II(i)]

का०आ० 2153.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स गणपति कैरिज कारपोरेशन, 56/57 दूसरी मंजिल, बाम्बे म्युचुअल बिल्डिंग, सर पी०एम०रोड मुम्बई-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35018/39/77-पी०एफ-2(ii)]

S.O. 2153.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976, the establishment known as Messrs. Ganpati Carriage Corporation, 56/57, 2nd Floor, Bombay Mutual Building, Sir, P. M. Road, Bombay-1, for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35018/39/77-PF.II(ii)]

का०आ० 2154.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ग्रीव्स इन्टरनेशनल लिमिटेड, 1 डाक्टर बी०बी० गान्धी मार्ग, पोस्ट बाक्स सं० 91, मुम्बई-23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मजारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(40)/77-पी०एफ-2(i)]

S.O. 2154.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Greaves International Limited, 1, Dr. V. B. Gandhi Marg, Post Box No. 91, Bombay-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S. 35018(40)/77-PF.II.(i)]

का०आ० 2155.—केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 नवम्बर, 1976 से मैसर्स ग्रीव्स इन्टर नेशनल लिमिटेड, 1 डाक्टर बी०बी० गान्धी मार्ग, पोस्ट बाक्स सं० 91, मुम्बई-23 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018/40/77-पी०एफ-2(ii)]

S.O. 2155.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of November, 1976 the establishment known as Messrs Greaves International Limited, 1, Dr. V. B. Gandhi Marg, Post Box No. 91, Bombay-23 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018/40/77-PF.II(ii)]

का०आ० 2156.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टील इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-2 औद्योगिक एस्टेट, राजाजीनगर, बंगलोर-10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण, उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019/142/77-पी०एफ-2]

S.O. 2156.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Steel India Private) Limited, C-2, Industrial Estate, Rajajinagar, Bangalore-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/142/77-PF.II]

का० आ० 2157.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महालक्ष्मी वीविंग फैक्ट्री, रामपुरा, रामबाग, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(194)/77-पी०एफ०-2]

S.O. 2157.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Mahalaxmi Weaving Factory, Rampura, Ram Baug, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtyfirst day of August, 1976.

[No. S. 35019(194)/77-PF.II]

का० आ० 2158.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री सरस्वती विद्या मन्दिर मल्हार गंज, स्ट्रीट सं० 4, इन्दौर-2 (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/212/77-पी०एफ०-2]

S.O. 2158.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs. Shri Sraswati Vidya Mandir, Malharganj, Street No. 4, Indore-2 (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1977.

[No. S. 35019/212/77-PF.II]

का० आ० 2159.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईश्वर भाई पटेल ठेकेदार, क्वार्टर एल०आई०जी०-18, रामनगर, म० प्र० हाउसिंग कालोनी, भिलाई (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35019/216/77-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 2159.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ishwar Bhai Patel Contractor, Quarter L.I.G.-18 Ramnagar, M.P. Housing Colony, Bhilai (Madhya Pradesh), have agreed that the provisios of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1975.

[No. S. 35019/216/77-PF.II(i)]

का० आ० 2160.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 सितम्बर 1975 से मैसर्स ईश्वर भाई पटेल, ठेकेदार, क्वार्टर एल० आई० जी० रामनगर म० प्र० हाउसिंग कालोनी भिलाई--(मध्य प्रदेश) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एम० 35019/216/77-पी०एफ०2(ii)]

S.O. 2160.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1975, the establishment known as Messrs. Ishwar Bhai Patel Contractor Quarter L.I.G. 18, Ramnagar, M.P. Housing Colony, Bhilai (Madhya Pradesh), for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/216/77-PF.II(ii)]

का० आ० 2161.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी० टी० रोड लान्स, डाकघर फेरोके, कोझीकोड तालुक, जिला कोझीकोड, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मार्च 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/225/77-पी०एफ०2-]

S.O. 2161.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. V. T. Road Lines, Post Office Feroke, Kozhikode Taluk, Kozhikode District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1977.

[No. S. 35019/225/77-PF.II]

का० आ० 2162.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जगदीश प्रैस, एम० जी० रोड, जैपुर जिला कोरापुत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/245/77-पी० एफ०-2]

S.O. 2162.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Jagadish Press, M. G. Road, Jeypore, District Koraput, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S. 35019/245/77-PF.II]

का० आ० 2163.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बेद प्रकाश अग्रवाल (धातु कारखाना) बोलनगिर, उड़ीसा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35019/246/77-पी०एफ०-2]

S.O. 2163.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bedprakash Agarwal (Metal Factory), Bolangir, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S. 35019(246)/77 PF.II]

का० आ० 2164.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडिया सावरैन्स (जै) कम्पनी, पोस्ट बाक्स सं० 21, जेपुर, जिला कोरापुट नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/247/2/77-पी० एफ०-2]

S.O. 2164.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. India Sovereigns (Jey) Company, Post Box No. 21, Jeypore, District Koraput, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1976.

[No. S. 35019/247/77-PF.II]

का० आ० 2165.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डा० नीला बी० पटैल्स 'निराली' नर्सिंग होम, 'निराली' नैशनल हाईवे, हिम्मत नगर-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019(248)/77-पी० एफ०-2]

S.O. 2165.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Dr. Neela B. Patel's "Nirali" Nursing Home, "Nirali", National Highway, Himatnagar-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1977.

[No. S. 35019/248/77-PF.II]

का० आ० 2166.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री स्वामीनारायण आयल इंडस्ट्रीज, सानन्द, जिला अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुई केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना इकत्तीस मार्च, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019/250/77-पी० एफ०-2]

S.O. 2166.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shree Swaminarayan Oil Industries, Sanand, District Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provision of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1977.

[No. S. 35019/250/77-PF.II]

का० आ० 2167.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पुष्पा टेक्सटाइल्स, 34-ब, जगन्नाथ इंडस्ट्रियल एस्टेट, राखियाल, अहमदाबाद-23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35019/251/77-पी०एफ०-2]

S.O. 2167.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Pushpa Textiles, 34-B, Jagnath Industrial Estate Rakhial, Ahmedabad-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February, 1977.

[No. S. 35019/251/77-PF.II]

का० आ० 2168.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जी० पी० इंजीनियरिंग वर्क्स, 21/1, भारत खण्ड काटन मिल कम्पाउन्ड, नरोड़ रोड, अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/252/77-पी०एफ०-2]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

S.O. 2168.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. G. P. Engineering Works, 21/1, Bharat Khand Cotton Mill Compound, Naroda Road, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1976.

[No. S. 35019/252/77-PF.II]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1977

का० आ० 2169.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष लम्बित है।

और केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक कारणों से उक्त विवादों को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए हस्तान्तरित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली से वापस लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली को हस्तान्तरित करती है और निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली उक्त कार्यवाहियों उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वे उसे हस्तान्तरित की गई हैं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रमांक	विवाद संख्या	विवाद के पक्षकार
1.	1976 का *केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद संख्या 104	क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, चण्डीगढ़ बनाम श्री आई० एस० कपूर।
2.	1976 का के० स० औ० वि० संख्या 105	पंजाब नेशनल बैंक, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली, बनाम श्री बी० एन० बनसल।
3.	1976 का के० स० औ० वि० संख्या 106	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, चण्डीगढ़ बनाम श्री एस० के० धीर।
4.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 107.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ बनाम श्री आर० एन० आहूजा।
5.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 108.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लि०, चण्डीगढ़ बनाम श्री बाल कृष्ण ।
6.	1976 का के० स० औ० वि० स० 109.	स्टेट बैंक आफ पटियाला बनाम श्री सन्तोष गुप्ता।
7.	1976 का के० स० औ० वि० स० 110.	पंजाब नेशनल बैंक, शिमला बनाम श्री सुरेश कुमार।
8	1976 का के० स० औ० वि० सं० 111.	श्याम प्रोजेक्ट तलवारा बनाम श्री पवित्र सिंह।
9.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 112.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ बनाम श्री के० के० लिम्बा।
10.	1976 का के० स० औ० वि० स० 113.	यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस चण्डीगढ़ बनाम श्री हरदयाल सिंह।
11.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 114.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, चण्डीगढ़ बनाम श्री विशाल मणि।
12.	1976 का के० स० औ० वि० स० 115.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, चण्डीगढ़ बनाम स्टाफ यूनियन, अम्बाला केण्ट।
13.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 116.	पंजाब कोआपरेटिव बैंक लि०, अमृतसर बनाम ठाकुर दुर्गादास।
14.	1976 का के० स० औ० वि० स० 117.	पंजाब नेशनल बैंक, चण्डीगढ़ बनाम सुभाष चन्द।
15.	1976 का के० स० औ० वि० स० 42.	मैसर्स चार्टर्ड बैंक, कानपुर बनाम श्री जोगेश्वर झा।
16.	1976 का के० स० औ० वि० स० 31.	भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर बनाम श्री जे० एन० शर्मा ।
17.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 32.	भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर बनाम श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।
18.	1976 का के० स० औ० वि० स० 20	लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०, नई दिल्ली बनाम श्री महेश चन्द जैन।
19.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 54.	बैंक आफ इंडिया बनाम श्री प्रवेश कुमार और अन्य, लखनऊ।
20.	1975 का के० स० औ० वि० स० 59.	बैंक आफ इंडिया, लखनऊ बनाम श्री ए० के० जैन।
21.	1976 का के० स० औ० वि० स० 16.	बैंक आफ इंडिया, लखनऊ बनाम श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा।
22.	1976 का के० स० औ० वि० स० 92.	स्टेट बैंक आफ पटियाला बनाम श्री मेघेर सिंह।
23.	1976 का के० स० औ० वि० स० 103.	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम सर्वश्री धर्म सिंह, तारसेन लाल, रेशम सिंह।
24.	1976 का के० स० औ० वि० स० 99	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री श्रीराम।
25.	1976 का के० स० औ० वि० स० 95	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, बनाम श्री सुखा राम।
26	1976 का के० स० औ० वि० स० 100.	भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली बनाम श्री सुरेन्द्रपाल सिंह।
27.	1976 का के० स० औ० वि० स० 97.	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, बनाम श्री नरेन्द्र मारवाह।

क्रमांक	विवाद सं०	विवाद के पक्षकार
28	1976 का कें० स० औ० वि० स० 96.	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, बनाम श्री मलकित सिंह।
29	1976 का कें० स० औ० वि० स० 99	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री देव प्रकाश।
30	1976 का कें० स० औ० वि० स० 94	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री शक्ति सिंह।
31.	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 91	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री दीप चन्द।
32	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 93	स्टेट बैंक आफ चण्डीगढ़, बनाम श्री अमरिक सिंह।
33	1976 का कें० स० औ० वि० स० 93	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री देवी दयाल शर्मा।
34	1975 का कें० स० औ० वि० सं० 56	बैंक आफ इंडिया लखनऊ बनाम श्री हरीश कुमार रावत।
35	1975 का कें० स० औ० वि० स० 36	नारंग बैंक आफ इंडिया बनाम श्री भगवान दास चोपड़ा।
36	1976 का कें० स० औ० वि० स० 43	बैंक आफ बड़ौदा, लखनऊ बनाम श्री गंगा बक्श सिंह।
37	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 2	नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक, नई दिल्ली बनाम कर्मकार चौकीदार
38	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 38	बनारस स्टेट बैंक, वाराणसी बनाम श्री राम बाबू मिश्र।
39	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 40	कमारा बैंक लखनऊ, बगलौर बनाम श्री किशन लाल।
40	1976 का कें० स० औ० वि० स० 37	इलाहाबाद बैंक आफ लखनऊ बनाम श्री राज नारायण शुक्ल।
41	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 12	पजाब नेशनल बैंक, जम्मू बनाम श्री किशोरी लाल।
42	1974 का कें० स० औ० वि० सं० 7	मैसर्स फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक, बनाम श्री एस० एल० बालाई।
43	1974 का कें० स० औ० वि० सं० 5	स्टेट बैंक आफ पटियाला बनाम श्री एल० आर० सिगल।
44.	1975 का कें० स० औ० वि० सं० 1.	मैसर्स देना बैंक, नई दिल्ली बनाम सर्वश्री अशोक कुमार एण्ड एम० एम० शर्मा।
45	1976 का कें० स० औ० वि० स० 45	भारतीय खाद्य निगम, बरेली बनाम 51 कर्मकार।
46	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 10	मैसर्स व्यास सहलुज लिक प्रॉडक्ट्स, सुन्दरनगर, बनाम कर्मकार।
47	1976 का कें० स० औ० वि० स० 51	मैसर्स ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, नई दिल्ली बनाम श्री जे० आर० भवान।
48	1975 का कें०स० औ० वि० स० 46	बैंक आफ बड़ौदा, नई दिल्ली बनाम श्रीमती नागपाल।
49	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 8	मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री आर० एन० दास।
50	1975 का कें० स० औ० वि० स० 49	मैसर्स ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, नई दिल्ली बनाम श्री महिन्द्र लाल खन्ना।
51	1976 का कें० स० औ० वि० स० 101	भारतीय स्टेट बैंक, अम्बाला केण्ट बनाम श्री आर० एन० दास।
52	1974 का कें० स० औ० वि० स० 9	नेशनल सिटी बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री बिपिन कुमार शर्मा।
53	1976 का कें० स० औ० वि० स० 21	मैसर्स लक्ष्मी कमर्शियल बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री शिवनाथ शर्मा।
54	1975 का कें० स० औ० वि० सं० 21	मैसर्स बैंक आफ राजस्थान बनाम श्री हीरा लाल।
55	1974 का कें० स० औ० वि० सं० 13	मैसर्स बैंक आफ बड़ौदा, नई दिल्ली बनाम श्री एम० सी० शर्मा।
56	1975 का कें० स० औ० वि० सं० 61	मैसर्स ग्रीण्डलेज बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री प्रेम चन्द गुप्त।
57	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 41	मैसर्स यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम श्री प्रलाद प्रकाश।
58	1976 का कें० स० औ० वि० स० 44	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कानपुर बनाम श्री आर० एस० कपूर।
59	1975 का कें० स० औ० वि० स० 10	भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली बनाम 51 कर्मचारी।
60	1976 का कें० स० औ० वि० स० 84	स्टेट बैंक आफ पटियाला बनाम श्री गुरुमित सिंह।
61	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 87	मैसर्स बैंक आफ बड़ौदा, सोनीपत बनाम श्री राज कुमार मुखी।
62	1975 का कें० स० औ० वि० स० 9	यूनियन बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली बनाम श्री मिठ्ठन लाल गुप्त।
63	1975 का कें० स० औ० वि० सं० 60	मैसर्स ग्रीण्डलेज बैंक, नई दिल्ली बनाम कर्मकार।
64	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 22	मैसर्स ग्रीण्डलेज बैंक, कानपुर बनाम यूनियन।
65	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 18	मैसर्स ग्रीण्डलेज बैंक, अमृतसर, बनाम सर्वश्री एस० पी० खन्ना, और अन्य।
66	1975 का कें० स० औ० वि० स० 72	मैसर्स भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली, बनाम शाम चन्द गुलाटी।
67	1976 का कें० स० औ० वि० स० 27	मैसर्स इलाहाबाद बैंक, लखनऊ, बनाम श्री गिपी नाथ कपूर।
68	1976 का कें० स० औ० वि० स० 35	मैसर्स ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल, इशोरेंस कानपुर, बनाम श्री कुतुब उल्लाह खान।
69	1976 का कें० स० औ० वि० सं० 34	मैसर्स ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इशोरेंस कानपुर, बनाम श्री कुतुब उल्लाह खान।
70	1976 का कें० स० औ० वि० स० 90	मैसर्स न्यू बैंक आफ इण्डिया, जालन्धर बनाम श्री यमुना प्रसाद।
71	1976 का कें० स० औ० वि० स० 89	मैसर्स जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स, जम्मू लि० बनाम कर्मकार।
72	1976 का कें० स० औ० वि० स० 30	मैसर्स पजाब नेशनल बैंक, कानपुर, बनाम श्री आर० एन० धर्मा।
73	1976 का कें० स० औ० वि० स० 29	मैसर्स इलाहाबाद बैंक, लखनऊ बनाम श्री रमा कान्त टण्डन।

क्रमांक	विवाद सं०	विवाद के पक्षकार
74.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 28.	मैसर्स इलाहाबाद बैंक, लखनऊ बनाम श्री राम कुमार खन्ना।
75.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 55.	मैसर्स इंडियन एयर लाईन्स बनाम श्री पी० एस० जासल।
76.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 39.	मैसर्स बैंक आफ बड़ौदा, कानपुर बनाम श्री जे० एल० मल्होत्रा।
77.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 7.	मैसर्स ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स नई दिल्ली बनाम मनोहर लाल खन्ना।
78.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 45	मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम कर्मकार।
79.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 69.	पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री दौलत राम।
80.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 42.	मैसर्स इंडियन एयर लाइन्स बनाम श्री मुख्तियार सिंह।
81.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 82.	मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक बनाम श्री जैय गोपाल वर्मा।
82.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 34	मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक, बनाम श्याम बाबू नई दिल्ली।
83.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 13.	मैसर्स इंडियन एयर लाइन्स बनाम श्री एम० एम० अग्रवाल।
84.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 88.	मैसर्स ब्यास डैम प्रोजैक्ट, तलवाड़ा बनाम श्री मनोहर लाल।
85.	1976 का के० स० औ० वि० स० 26.	मैसर्स एल० आई० सी० इंडिया, कानपुर बनाम श्री डी० के० मिश्रा।
86.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 47.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली बनाम श्री प्रेम चन्द जैन।
87.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 12.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली बनाम विजेन्द्र कुमार जैन और अन्य।
88.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 31.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली बनाम श्री राम दुलार उपाध्याय।
89.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 23.	मैसर्स यूनियन बैंक आफ इंडिया, लखनऊ बनाम श्री बी० आर० त्रिवेदी।
90.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 19.	मैसर्स ग्रीण्डलेज बैंक लि०, नई दिल्ली बनाम कर्मकार।
91.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 69.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ बनाम श्री राम सिंह।
92.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 77.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ बनाम बचन सिंह।
93.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 59	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ बनाम अमरजीत सिंह।
94.	1976 का के० स० औ० वि० स० 61.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ बनाम श्री जी० एस० गुलाठी।
95.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 68.	मैसर्स सी० बी० आई०, चण्डीगढ़ बनाम श्री अजीत कुमार।
96.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 102.	मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक, न्यू दिल्ली बनाम श्री नन्द किशोर शर्मा।
97.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 80.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ बनाम श्री के० एल० विज।
98.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 67.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया बनाम श्री एच० पी० जैन।
99.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 26.	मसर्स इंजीनियर चीफ पी० डब्ल्यू० डी०, नई दिल्ली बनाम श्री सरदार सिंह।
100.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 2.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली बनाम श्री के० एल० गुप्ता और अन्य।
101.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 13.	मैसर्स बैंक आफ इंडिया, लखनऊ बनाम श्री ए० के० कीर्ति।
102.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 46.	मैसर्स पंजाब नेशनल बैंक, शिमला बनाम श्री हुकम सिंह।
103.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 58.	मैसर्स यूनियन बैंक आफ इंडिया, बम्बई बनाम श्री डी० सी० शर्मा।
104.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 44.	मैसर्स यूनाईटेड कमर्शियल बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री आर० एम० तलवार।
105.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 48.	मैसर्स पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू बनाम श्री मोहिन्द्र सिंह परमार।
106.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 49.	मैसर्स पंजाब नेशनल बैंक, शिमला बनाम श्री तिलक राज बेद।
107.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 47.	मैसर्स पंजाब नेशनल बैंक, शिमला बनाम श्री आर० सी० वशिष्ठ।
108.	1975 का के० स० औ० वि० सं० 74.	मैसर्स भारत सरकार मुद्रणालय, बनाम श्री सी० पी० गर्ग।
109.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 52.	मैसर्स सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चण्डीगढ़ बनाम ए० एल० चोपड़ा।
110.	1976 का के० स० औ० वि० सं० 15.	मसर्स भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली बनाम श्री हरभजन सिंह।
111	1976 का के० स० औ० वि० सं० 25.	मैसर्स इंडियन एयर लाइन्स बनाम तारा चन्द।

*केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद।

[संख्या एल०-12025(21)/76-डी० 2(ए०)/डी० IV-बी०]

जगदीश प्रसाद, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 13th May, 1977

S.O. 2169.—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal, Delhi;

And whereas for administrative reasons, the Central Government considers it desirable to transfer the said disputes for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal, Delhi and transfers the same to the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi constituted under section 7A of the said Act and directs that the said Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, shall proceed with the said proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Case No.	Parties to the dispute
1.	*C.G.I.D. No. 104 of 1976	Regional Manager, Punjab National Bank, Chandigarh V/s. Sh. I.S. Kapoor.
2.	C.G I.D. No. 105 of 1976	Punjab National Bank, Jhandewalan Extn., New Delhi V/s. Sh. V.N. Bansal.
3.	C.G.I.D. No. 106 of 1976	Central Bank of India, Chandigarh V/s. Sh. S.K. Dhir.
4.	C.G.I.D. No. 107 of 1976	Central Bank of India, Chandigarh V/s. Sh. R.N. Ahuja.
5.	C.G.I.D. No. 108 of 1976	Oriental Bank of Commerce Ltd., Chandigarh V/s. Sh. Bal Krishan.
6.	C.G.I.D. No. 109 of 1976	State Bank of Patiala V/s. Sh. Santosh Gupta.
7.	C.G.I.D. No. 110 of 1976	Punjab National Bank, Simla V/s. Sh. Suresh Kumar.
8.	C.G.I.D. No. 111 of 1976	Beas Project Talwara V/s. Sh. Pawitra Singh.
9.	C.G.I.D. No. 112 of 1976	Central Bank of India, Chandigarh V/s. Sh. K.K. Trikha.
10.	C.G.I.D. No. 113 of 1976	United India Fire & Genl. Insurance, Chandigarh V/s. Sh. Hardial Singh.
11.	C.G.I.D. No. 114 of 1976	Central Bank of India, Chandigarh V/s. Sh. Vishal Mani.
12.	C.G.I.D. No. 115 of 1976	Central Bank of India, Chandigarh V/s. Staff Union, Ambala Cantt.
13.	C.G.I.D. No. 116 of 1976	Punjab Co-operative Bank Ltd. Amritsar V/s. Thakur Durga Das.
14.	C.G.I.D. No. 117 of 1976	Punjab National Bank, Chandigarh V/s. Sh. Subhash Chand.
15.	C.G.I.D. No. 42 of 1976	M/s. Chartered Bank, Kanpur V/s. Shri Jogeshwer Jha.
16.	C.G.I.D. No. 31 of 1976	State Bank of India, Kanpur V/s. Sh. J.N. Sharma.
17.	C.G.I.D. No. 32 of 1976	State Bank of India, Kanpur V/s. Sh. Virender Partap Singh.
18.	C.G.I.D. No. 20 of 1976	Laxmi Commercial Bank Ltd. New Delhi. V/s. Sh. Mahesh Chand Jain.
19.	C.G.I.D. No. 54 of 1975	Bank of India V/s. Sh. Parwesh Kumar & Others, Lucknow.
20.	C.G.I.D. No. 59 of 1975	Bank of India, Lucknow V/s. Shri A.K. Jain.
21.	C.G.I.D. No. 16 of 1976	Bank of India Lucknow V/s. Sh. Surender Kumar Verma.
22.	C.G.I.D. No. 92 of 1976	State Bank of Patiala V/s. Sh. Megher Singh.
23.	C.G.I.D. No. 103 of 1976	State Bank of India, New Delhi V/s. S/Sh. Dharam Singh, Tarsenlal Pesham Singh.
24.	C.G.I.D. No. 99 of 1976	State Bank of India, New Delhi V/s. Shri Bri Ram.
25.	C.G.I.D. No. 95 of 1976	State Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Sucha Ram.
26.	C.G.I.D. No. 100 of 1976	State Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Surenderpal Singh.
27.	C.G.I.D. No. 97 of 1976	State Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Narinder Marwaha.
28.	C.G.I.D. No. 96 of 1976	State Bank of India, New Delhi. V/s. Sh. Malkit Singh.
29.	C.G.I.D. No. 98 of 1976	State Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Dev Parkash.
30.	C.G.I.D. No. 94 of 1976	State Bank of India, New Delhi. V/s. Sh. Shakti Singh.
31.	C.G.I.D. No. 91 of 1976	State Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Dep Chand.
32.	C.G.I.D. No. 93 of 1976	State Bank of Chandigarh V/s. Sh. Amrik Singh.
33.	C.G.I.D. No. 83 of 1976	State Bank of India, New Delhi, V/s. Sh. Devi Dayal Sharma.
34.	C.G.I.D. No. 56 of 1975	Bank of India, Lucknow V/s. Sh. Harish Kumar Rawal.
35.	C.G.I.D. No. 36 of 1975	Narang Bank of India V/s. Sh. Bhagwan Dass Chopra.
36.	C.G.I.D. No. 43 of 1976	Bank of Baroda, Lucknow. V/s. Sh. Ganga Bax Singh.
37.	C.G.I.D. No. 2 of 1976	National & Grindlays Bank, New Delhi V/s. Workmen Chowkidar.
38.	C.G.I.D. No. 38 of 1976	Banaras State Bank, Varanasi V/s. Sh. Ram Babu Mishra.
39.	C.G.I.D. No. 40 of 1976	Canara Bank, Lucknow, Bangalore V/s. Sh. Kishan Lal.
40.	C.G.I.D. No. 37 of 1976	Allahabad Bank of Lucknow V/s. Sh. Raj Narain Shukla.
41.	C.G.I.D. No. 12 of 1976	Punjab National Bank, Jammu V/s. Sh. Kishori Lal.
42.	C.G.I.D. No. 7 of 1974	M/s. First National City Bank V/s. Sh. S.L. Balai.
43.	C.G.I.D. No. 5 of 1974	State Bank of Patiala V/s. Sh. L.R. Singal.
44.	C.G.I.D. No. 1 of 1975	M/s. Dena Bank, New Delhi V/s. S/sh. Ashok Kumar & M.M. Sharma.

Sl. No.	Case No.	Parties to the dispute
45.	C.G.I.D. No. 45 of 1976	Food Corporation of India, Bareilly V/s. 51 workmen.
46.	C.G.I.D. No. 10 of 1976	M/s. Beas Satluj Link Products, Sunder Nagar V/s. Workmen.
47.	C.G.I.D. No. 51 of 1976	M/s. Oriental Bank of Commerce, New Delhi V/s. Sh. J.R. Madan.
48.	C.G.I.D. No. 46 of 1975	Bank of Baroda, New Delhi V/s. Mrs. Nagpal.
49.	C.G.I.D. No. 8 of 1976	M/s. State Bank of India, New Delhi V/s. Sh. R.N. Dass.
50.	C.G.I.D. No. 49 of 1975	M/s. Oriental Bank of Commerce, New Delhi. V/s. Sh. Mohinder Lal Khanna.
51.	C.G.I.D. No. 101 of 1976	State Bank of India, Ambala Cantt. V/s. Sh. R. N. Dass.
52.	C.G.I.D. No. 9 of 1974	National City Bank, New Delhi V/s. Sh. Vipin Kumar Sharma.
53.	C.G.I.D. No. 21 of 1976	M/s. Luxmi Commercial Bank, New Delhi V/s. Sh. Shiv Nath Sharma.
54.	C.G.I.D. No. 21 of 1975	M/s. Bank of Rajasthan V/s. Sh. Hira Lal.
55.	C.G.I.D. No. 13 of 1974	M/s. Bank of Baroda, New Delhi V/s. Sh. M.C. Sharma.
56.	C.G.I.D. No. 61 of 1975	M/s. Grindlays Bank, New Delhi V/s. Sh. Prem Chand Gupta.
57.	C.G.I.D. No. 41 of 1976	M/s. United Commercial Bank. V/s. Sh. Prahlad Prakash.
58.	C.G.I.D. No. 44 of 1976	M/s. Central Bank of India, Kanpur V/s. Sh. R.S. Kapoor.
59.	C.G.I.D. No. 10 of 1975	Reserve Bank of India, New Delhi V/s. 51 Employees.
60.	C.G.I.D. No. 84 of 1976	State Bank of Patiala. V/s. Sh. Gurmit Singh.
61.	C.G.I.D NO. 87 of 1976	M/s. Bank of Baroda, Sonepat V/s. Sh. Raj kumar Mukhi.
62.	C.G.I.D. No. 9 of 1975	Union Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Mithan Lal Gupta.
63.	C.G.I.D. No. 60 of 1975	M/s. Grindlays Bank, New Delhi V/s. Workmen.
64.	C.G.I.D. No. 22 of 1976	M/s. Grindlays Bank, Kanpur V/s. Union.
65.	C.G.I.D. No. 18 of 1976	M/s. Grindlays Bank, Amritsar V/s. S/Sh. S.P. Khanna & Others.
66.	C.G.I.D. No. 72 of 1975	M/s. Food Corporation of India, New Delhi. V/s. Sh. Gian Chand Gulathi.
67.	C.G.I.D. No. 27 of 1976	M/s. Allahabad Bank, Lucknow V/s. Sh. Gipi Nath Kapoor.
68.	C.G.I.D. No. 35 of 1976	M/s. Oriental fire & genl. Insurance, Kanpur V/s. Sh. Qutub Ullah Khan.
69.	C.G.I.D. No. 34 of 1976	M/s. Oriental fire & genl. Insurance, Kanpur V/s. Sh. Qutub Ullah Khan.
70.	C.G.I.D. No. 90 of 1976	M/s. New Bank of India, Jullundur V/s. Sh. Yamuna Parshad.
71.	C.G.I.D. No. 89 of 1976	M/s. Jammu & Kashmir Minerals Jammu Ltd. V/s. Workmen.
72.	C.G.I.D. No. 30 of 1976	M/s. Punjab National Bank, Kanpur V/s. Sh. R.N. Verma.
73.	C.G.I.D. No. 29 of 1976	M/s. Allahabad Bank Lucknow. V/s. Shri Rama Kant Tondan.
74.	C.G.I.D. No. 28 of 1976	M/s. Allahabad Bank, Lucknow V/s. Shri Ram Kumar Khanna.
75.	C.G.I.D. No. 55 of 1976	M/s. Indian Air Lines V/s. Sh. P.S. Jasal.
76.	C.G.I.D. No. 39 of 1976	M/s. Bank of Baroda, Kanpur V/s. Sh. J.L. Malhotra.
77.	C.G.I.D. No. 7 of 1975	M/s. Oriental Bank of Commerce, New Delhi V/s. Manohar Lal Khanna.
78.	C.G.I.D. No. 45 of 1975	M/s. State Bank of India, New Delhi V/s. 14 Workmen.
79.	C.G.I.D. No. 69 of 1975	Punjab National Bank, New Delhi V/s. Sh. Daulat Ram.
80.	C.G.I.D. No. 42 of 1975	M/s. Indian Air Lines V/s. Sh. Mukhtiar Singh.
81.	C.G.I.D. No. 82 of 1976	M/s. State Bank of India V/s. Sh. Jai Gopal Verma.
82.	C.G.I.D. No. 34 of 1975	M/s. State Bank of India V/s. Shyam Babu, New Delhi.
83.	C.G.I.D. No. 13 of 1975	M/s. Indian Air Lines V/s. Sh. S.M. Aggarwal.
84.	C.G.I.D. No. 88 of 1976	M/s. Beas Dam Project, Talwara V/s. Sh. Manoher Lal.
85.	C.G.I.D. No. 26 of 1976	M/s. L.I.C. India, Kanpur V/s. Sh. D.K. Mishra.
86.	C.G.I.D. No. 47 of 1975	M/s. Centrzl Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Prem Chand Jain.
87.	C.G.I.D. No. 12 of 1975	M/s. Central Bank of India, New Delhi V/s. Vijendra Kumar Jain & others.
88.	C.G.I.D. No. 31 of 1975	M/s. Central Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Ram Dular Upadhyay.

Sl. No.	Case No.	Parties to the dispute
89.	C.G.I.D. No. 23 of 1976	M/s. Union Bank of India, Lucknow V/s. Sh. B.R. Trivedi.
90.	C.G.I.D. No. 19 of 1976	M/s. Grindlays Bank Ltd. New Delhi V/s. Workmen.
91.	C.G.I.D. No. 69 of 1976	M/s. Central Bank of India, Chandigarh V/s. Sh. Ram Singh.
92.	C.G.I.D. No. 77 of 1976	M/s. Central Bank of India, Chandigarh V/s. Sh. P han Singh.
93.	C.G.I.D. No. 59 of 1976	M/s. Central Bank of India, Chandigarh V/s. Baljit Singh.
94.	C.G.I.D. No. 61 of 1976	M/s. Central Bank of India, Chandigarh V/s. Sh. G.S. Gulathi.
95.	C.G.I.D. No. 68 of 1976	M/s. C.B.I. Chandigarh V/s. Ajit Kumar.
96.	C.G.I.D. No. 102 of 1976	M/s. State Bank of India New Delhi V/s. Shri Nand Kishore Sharma.
97.	C.G.I.D. No. 80 of 1976	M/s. Central Bank of India, Chandigarh V/s. Sh. K.L. Vij.
98.	C.G.I.D. No. 67 of 1976	M/s. Central Bank of India V/s. Sh. H.P. Jain.
99.	C.G.I.D. No. 26 of 1976	M/s. Engineer Chief P.W.D., New Delhi V/s. Sh. Sardar Singh.
100.	C.G.I.D. No. 2 of 1976	M/s. Central Bank of India, New Delhi V/s. Sh. K.L. Gupta & others.
101.	C.G.I.D. No. 13 of 1976	M/s. Bank of India, Lucknow V/s. Sh. A.K. Kirti.
102.	C.G.I.D. No. 46 of 1976	M/s. Punjab National Bank Simla V/s. Sh. Hukam Singh.
103.	C.G.I.D. No. 58 of 1975	M/s. Union Bank of India, Bombay V/s. Sh. D.C. Sharma.
104.	C.G.I.D. No. 44 of 1975	M/s. United Commercial Bank, New Delhi, V/s. Sh. R.M. Talwar.
105.	C.G.I.D. No. 48 of 1976	M/s. Punjab National Bank, Jammu V/s. Sh. Mohinder Singh Parmar.
106.	C.G.I.D. No. 49 of 1976	M/s. Punjab National Bank, Simla V/s. Sh. Tilak Raj Vaid.
107.	C.G.I.D. No. 47 of 1976	M/s. Punjab National Bank, Simla V/s. Sh. R.C. Vashisth.
108.	C.G.I.D. No. 74 of 1975	M/s. Govt. of India Press V/s. Sh. C.P. Garg.
109.	C.G.I.D. No. 52 of 1976	M/s. Central Bank of India, Chandigarh V/s. A.L. Chopra.
110.	C.G.I.D. No. 15 of 1976	M/s. State Bank of India, New Delhi V/s. Sh. Harbhajan Singh.
111.	C.G.I.D. No. 25 of 1976	M/s. Indian Air Lines V/s. Tara Chand.

*Central Government Industrial Dispute.

[No. L-12025(21)/76-D-II(A)/D-IV-B]

JAGDISH PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 जून, 1977

का० आ० 2170.—केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में लौह अयस्क खान श्रम कल्याण संगठन के कल्याण-आयुक्त को लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त विनिर्दिष्ट करती है जो लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 की 58) की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन उद्ग्रहीत और एक अक्तूबर, 1974 के पूर्व शोध्य हुए उत्पाद-शुल्क के निर्धारण और संग्रहण के लिए अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर अनन्यता उत्तरदायी होगा।

[फा० सं० एम० 23013/2/74-एम० 4]

पी० के० सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd June, 1977

S.O. 2170.—In exercise of the powers conferred by rule 31 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, the Central Government hereby specifies the Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Organisation in the State of Madhya Pradesh to be Iron Ore Mines Cess Commissioner who shall be exclusively responsible in the territories within his jurisdiction for the assessment and collection of the duty of excise levied under clause (b) of section 2 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961) and accrued due before the 1st day of October, 1974.

[F. No. S. 23013/2/74-M.IV]

P. K. SEN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 1977

का० आ० 2171.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि औद्योगिक जंजीरें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण के अधीन हों ,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित के अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए जिनकी उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है, प्रकाशित करती है ।

2. यह सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (8वीं मंजिल) कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि औद्योगिक जंजीरें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी;

(2) इस आदेश के उपाबन्ध-1 में दिए गए औद्योगिक जंजीरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसी औद्योगिक जंजीरों पर निर्यात से पूर्व लागू होगा;

(3) (क) विदेशी क्रेता एवं निर्यातकर्ता के मध्य निर्यात संविदा में वर्णित विनिर्देशों का मान्यता देना;

(ख) स्तम्भ (क) में निर्दिष्ट किसी भी विनिर्देश की अनुपस्थिति में औद्योगिक जंजीरों के लिए भारतीय मानक संस्थान या विदेश के राष्ट्रीय मानकों द्वारा जारी किए गए विनिर्देशों को मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसी औद्योगिक जंजीरों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि औद्योगिक जंजीरें क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करती है तथा निर्यात-योग्य है ।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी खेपों को भूमि, वायु या समुद्र मार्ग द्वारा औद्योगिक जंजीरों के नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी ।

4. इस आदेश में 'औद्योगिक जंजीरों' से विद्युत के संचारण के लिए या किसी औद्योगिक तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्र में यांत्रिक संचालन के लिए प्रयुक्त सामान्य या मिश्रित बनावट वाली इस्पात की रोलर जंजीर; बुश जंजीर या लीफ जंजीर अभिप्रेत हैं ।

उपाबन्ध-1

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप ।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :—इन नियमों का नाम औद्योगिक जंजीरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977 है ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) इस आदेश में 'औद्योगिक जंजीरों' से विद्युत के संचारण के लिए या किसी औद्योगिक तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्र में यांत्रिक संचालन के लिए प्रयुक्त सामान्य या मिश्रित बनावट वाली इस्पात की रोलर जंजीर, बुश जंजीर या लीफ जंजीर अभिप्रेत है ।

3. क्वालिटी नियंत्रण : (1) निर्यात के लिए आशयित 'औद्योगिक जंजीरों' की क्वालिटी इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए नियंत्रण की परखों के साथ विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) खरीदी गई सामग्री तथा संघटक नियंत्रण :

(क) प्रयुक्त किए जाने वाले घटकों तथा सामग्री के गुण धर्मों को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा क्रय विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे और उसके पास आने वाले लाटों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण या परख के पर्याप्त साधन होंगे ।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए प्रदाय-कर्ता का परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा, उस दशा में यदा-कदा होने वाली जांच (अर्थात् साल में हर तीन महीनों में एक बार उसी माल के उसी प्रदाय-कर्ता के लिए) विनिष्ट प्रदाय-कर्ता के लिए क्रेता द्वारा उक्त परख या निरीक्षण प्रमाण-पत्रों की शुद्धता सत्यापित करने के लिए की जाएगी या क्रय किए गए माल या घटकों का या तो कारखाने की प्रयोगशाला में या किसी अन्य प्रयोगशाला या परीक्षण गृह में नियमित रूप से निरीक्षण या परख की जाएगी ।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परख के लिए नमूना लेना लेखबद्ध किए गए अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(घ) निरीक्षण या परख किए जाने के पश्चात्, स्वीकृत तथा अस्वीकृत माल या घटकों के पृथक्करण में तथा अस्वीकृत माल या घटकों के निपटान में व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी ।

(ङ) ऊपर निर्दिष्ट नियंत्रणों के सम्बन्ध में विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित तथा नियमित रूप से रखे जाएंगे ।

(ii) प्रक्रम नियंत्रण

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रमों के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत प्रक्रम विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपस्कर, उपकरण सुविधाएं पर्याप्त होंगी ।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन की सम्भावनाओं को सुनिश्चित करने के लिये विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे।

(iii) उत्पाद नियंत्रण :

(क) विनिर्माता के पास अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य विनिर्देशों के अनुसार उत्पादन की परख करने की या तो स्वयं की अपनी परख सुविधाये होंगी या अन्य स्थान पर विद्यमान ऐसी परख सुविधाओं तक उसकी पहुंच होगी।

(ख) परख के लिये नमूना (जहां अपेक्षित हो) लेना लेखबद्ध किये गये अन्वेषण पर आधारित होगा।

(ग) की गई परखों के सम्बन्ध में पर्याप्त अभिलेख विनिर्माता द्वारा व्यवस्थित एवं नियमित रूप से रखे जायेंगे।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण :

(क) उत्पाद को मौसमी दशाओं के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिये विनिर्माता विस्तृत विनिर्देश बनाएगा।

(ख) उत्पादन भंडारकरण एवं अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जायेगा।

(v) मौसम सम्बन्धी नियंत्रण :

उत्पादन तथा निरीक्षण में प्रयुक्त मापकों एवं उपकरणों की कालिक जांच या अंशशोधन किया जायगा और विनिर्माता द्वारा अभिलेख वृत्तकार्ड के रूप में रखे जाएंगे।

(vi) पैकिंग नियंत्रण :

निर्यात पैकजों के लिये विनिर्माता ब्यौरेवार पैकिंग विनिर्देश बनायेगा तथा उसका सख्ती से पालन करेगा।

(2) निरीक्षण—निर्यात के लिये आशयित औद्योगिक जंजीरों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जायेगा कि क्या ऊपर वर्णित नियंत्रणों का सुसंगत स्तरों पर समाधान रूप से प्रयोग किया गया है और औद्योगिक जंजीरे इस पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) निर्यातकर्ता किसी भी अधिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ एक घोषणा पत्र देगा कि औद्योगिक जंजीरों का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट नियंत्रणों के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण परिमापों का प्रयोग करके निर्मित किया गया है या किया जा रहा है और परेषण उक्त प्रयोजन के लिये मान्यता-प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। निर्यातकर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रतिलिपि परिषद् के निकटतम कार्यालय को भेजेगा। परिषद् के पते इस प्रकार हैं :—

मुख्य कार्यालय:

निर्यात निरीक्षण परिषद्,
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (8वीं मंजिल)
कलकत्ता—1

क्षेत्रीय कार्यालय :

(i) निर्यात निरीक्षण परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय,
अमन चैम्बर्स (पांचवीं मंजिल)
113 महर्षि कर्वे रोड,
बम्बई—4

(ii) निर्यात निरीक्षण परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, 'मनोहर बिल्डिंग्स'
महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम,
कोचीन-11

(iii) निर्यात निरीक्षण परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, 'फरीदाबाद,
670, सैक्टर 16 ए०, मथुरा रोड,
फरीदाबाद

(2) निर्यातकर्ता परेषण पर लगाये गये पहचान चिन्ह भी अधिकरण को देगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा विनिर्माता या निर्यात-कर्ता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम 7 दिन से पहले अधिकरण के कार्यालय को पहुंचेगी।

(4) उपनियम (1) और (3) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अधिकरण,—

(क) निर्यातकर्ता की दशा में, यदि वह स्वयं ही विनिर्माता है, तो, उसके यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसने इस पर लागू होने वाले मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिये इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी किये गये अनुदेशों, यदि कोई हों, तथा नियम 3 में दिये गये पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग गया है।

(ख) निर्यात-कर्ता की दशा में, यदि वह स्वय विनिर्माता नही है तो, उसके यह समाधान कर लेने पर कि उसने विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान, इस पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिये इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी किये गये विनिर्देशों, यदि कोई हों तथा नियम 3 में दिये गये पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणो का प्रयोग किया है तो वह निरीक्षण करने के तीन दिनों के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा कि औद्योगिक जंजीर का परेषण निर्यात योग्य है।

परन्तु जहां अधिकरण को इस प्रकार का समाधान नहीं हुआ है वहां वह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके लिये कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

5. मान्य चिन्ह का चिपकाना और उसकी प्रक्रिया :—भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36), भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) विनियम, 1955 के उपबन्ध, जहां तक हो, औद्योगिक जंजीरों पर निर्यात से पूर्व मान्य चिन्ह या सील के चिपकाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में लागू होंगे तथा इस प्रकार चिन्हित औद्योगिक जंजीरें नियम 4 के अन्तर्गत किसी भी निरीक्षण के अधीन नही होंगी।

6. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण विनिर्माता या निर्यातकर्ता के परिसर पर पोत लदान की बन्दरगाह पर किया जायेगा।

7. निरीक्षण फीस :—नियम 4 के अन्तर्गत औद्योगिक जंजीरों के ऐसे प्रत्येक परेषण के लिये पर्यंत निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपये पर पचास पैसे की दर से पोत निरीक्षण फीस के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा अधिकरण को दी जायेगी। यह फीस कम से कम एक सौ रुपये होगी।

8. अपील :—(1) नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन अधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के इन्कार से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर उक्त प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन लेकिन अधिकतम सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के दो तिहाई सदय गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निपटा दी जायेगी।

अनुसूची

नियम 3 का उप-नियम (1) देखिए

क्रम सं०	परख/निरीक्षण विशेषताएं	अपेक्षाएं	परख किए जाने लाट वाले नमूनों की सं०	टिप्पणी
1.	सामग्री			
	(क) रसायन	मान्य विनिर्देशो के अनुसार	एक साथ 5 कुंडलियों से 5 नमूने	प्रत्येक प्रदायकर्ता से प्रत्येक लोट
	(ख) विमाएं			
	(ग) वाक्षुष परीक्षा			
	(घ) कठोरता/तनन सामर्थ्य			
2.	संघटक			
	विमाएं			
	कारीगरी तथा फिनिश	वही	5 नमूने	प्रत्येक आधे घंटे का उत्पादन
3.	उष्म उपचार			
	कठोरता की गहराई	वही	10 नमूने	प्रत्येक चार्ज
4.	तमंजन			
	समग्र विमाएं			प्रत्येक आधे घंटे का उत्पादन
	(क) आन्तरिक पर चौड़ाई	वही	5 नमूने	
	(ख) बाहरी प्लेटों के बीच की चौड़ाई			
	(ग) जंजीर की लम्बाई की (भारसिद्धता के पश्चात्)	वही	5 नमूने	प्रत्येक घंटे का उत्पादन
5.	टूटन भार परख	वही	5 नमूने	सभी जंजीरे, प्रत्येक घटक के लिए उसी चार्ज से संघटकों के साथ संमजिल हो गई
6.	पैकिंग :			
	(क) रूप	वही	प्रत्येक	प्रत्येक परेषण
	(ख) पात परख	वही	एक नम्बर	वही
	(ग) रौलिंग परख		वही	वही
	(घ) जल फुहारा परख		एक नम्बर	प्रत्येक डिजाइन

* पैकेज की अच्छी तरह फिनिश की जाएगी और देखने में सुन्दर होगा ।

** पैकेज वह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का होगा कि उसमें रखा माल नीचे दी गई पोत परख, रौलिंग परख तथा जल फुहार परख को सहन करेंगे :

पोत परख—(केवल 37 कि० ग्रा० तक के भार तक निर्बंधित करने के लिए) 150 से० मी० की ऊंचाई से गिराए जाने वाले पैकेज एक बार बड़ी समतल सतह पर, एक बार सबसे लम्बे किनारे पर और एक बार इसके किसी भी किनारे पर गिराया जाएगा ।

रोलिंग परख—(केवल 500 कि० ग्रा० के भार तक निर्बंधित करने के लिए) रोलिंग करने वाली पैकेज इसके किसी भी ओर 6 मीटर आगे की तरफ और 6 मीटर पीछे की ओर या 12 मीटर केवल एक ही दशा में रोल किए जाएंगे ।

जल फुहार परख—जल फुहार के लिए खोलने वाला पैकेज एक मिनट के लिए सामान्य आकस्मिकता के समतुल्य होगा ।

[सं० 6(26)/76-नि०नि० तथा नि० उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 25th June, 1977

S.O. 2171.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) INDUSTRIAL CHAINS should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby published the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this order in the Gazette of India to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that INDUSTRIAL CHAINS shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of INDUSTRIAL CHAINS (Quality Control and Inspection) Rules, 1976 set out in Annexure—I to this Order as the type of Quality control and inspection which would be applied to such INDUSTRIAL CHAINS prior to export ;

(3) To recognise—

(a) the specifications as stipulated in the Export contract between the foreign buyer and the exporter;

(b) In the absence of any stipulation referred to in clause (a) the specifications issued by the Indian Standards Institution or National Standards of a foreign country for INDUSTRIAL CHAINS as the standard specifications.

4. To prohibit the export in the course of international trade of any such INDUSTRIAL CHAINS unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the effect that the INDUSTRIAL CHAINS satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are export-worthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of INDUSTRIAL CHAINS to prospective buyers.

4. In this Order—"Industrial Chain" shall mean any steel roller-chain, bush chain or leaf chain of simple or multiple construction used for transmission of power or for mechanical handling in any industrial and other allied field.

ANNEXURE-I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of INDUSTRIAL CHAINS (Quality Control and Inspection), Rules, 1977.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) "agency" means any one of the agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Act;

(c) "Industrial Chain" means any steel roller chain, bush chain or leaf chain of simple or multiple construction used for transmission of power or for mechanical handling in any industrial and other allied field.

3. Quality Control.—(1) The quality of the INDUSTRIAL CHAINS intended for export shall be ensured by effecting the following controls, at different stages of manufacture together with the test of control as given in the Schedule annexed hereto namely :—

(i) Bought-out materials and components control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and shall have adequate means of inspection or testing to ensure conformity of the incoming lots.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test or inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specification, in which case occasional checks (that is to say once in each quarter of the year for the same supplier of the same material) shall be conducted by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test on inspection certificates, or the purchased materials or components shall be regularly inspected tested either in a laboratory in the factory or in some other laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on a recorded investigation

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and in disposal of rejected materials or components.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process control :

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipments, instrumentation and facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture

(iii) Product control :

(a) The manufacturer shall either have his own adequate testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(iv) Preservation control :

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse affects of weather condition.

(b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

(v) Metrological control :

Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards by the manufacturer.

(vi) Packing control :

The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and would strictly adhere to the same.

(2) Inspection—The inspection of INDUSTRIAL CHAINS intended for export shall be carried out with a view to seeing that the above mentioned controls have been exercised at the relevant levels satisfactorily and that specifications applicable to them.

4. Procedure of inspection.—(1) The exporter shall give intimation in writing to any agency Act and submit along with such intimation a declaration that the consignment of INDUSTRIAL CHAINS have been or are being manufactured by exercising quality control measures as per controls referred to in rule 3 and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for the purpose. The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Council The addresses of the Council are as under :

Head Office :

Export Inspection Council, 14/1-B, Ezra Street (7th Floor), Calcutta-1.

Regional Offices :

(i) Export Inspection Council, Regional Office, Aman Chambers (4th Floor), 113 Maharishi Karve Road, Bombay-4.

(ii) Export Inspection Council, Regional Office, 'Manohar Buildings', M. G. Road, Ernakulam, Cochin-11

(iii) Export Inspection Council, Regional office : Faridabad, 670 Sector 16A, Mathura Road, Faridabad.

(2) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises or exporter's premises.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rules (1) and (3), the agency,—

(a) in the case of an exporter who is himself the manufacturer on satisfying itself that during the process of manufacture he had exercised adequate quality control as provided under rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard to manufacture the product according to the standard specifications applicable to it,—

(b) in the case of an exporter who is not himself the manufacturer on satisfying itself that during the process of manufacture the manufacturer had exercised adequate quality control as provided under rule 3 and the instructions if any, issued by the Council in this regard to manufacture the product according to the standard specifications applicable to it,

within three days of carrying out the inspection, issue a certificate declaring the consignment of INDUSTRIAL CHAINS as export-worthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Affixation of recognised mark and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standard Institution (Certification Marks), Regulations, 1955 shall, so for as may be, apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on INDUSTRIAL CHAINS perior to export INDUSTRIAL CHAINS, so marked shall not be subjected to any inspection under rule 4.

6. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out at the premises of the manufacturer or exporter at the port of shipment.

7. Inspection Fee.—A fee at the rate of FIFTY paise for every hundred rupees of F.O.B. value subject to a minimum of rupees ONE HUNDRED for each such consignment of Industrial chains shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee under rule 4.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of exporter consisting of not less than three but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE

Tests of Control

[See sub-rule (i) of rule (3)]

Sl. No.	Test or Inspection Characteristic	Requirements	No. of samples to be tested	Lot Size	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Materials : (a) Chemical analysis (b) Dimensions (c) Visual examination (d) Hardness/Tensile strength	As per standard specification recognized	5 samples from coils at random	5 Each lot from each supplier.	
2.	Components : Dimensions Workmanship & finish	–do–	5 samples	Each half an hour's production.	
3.	Heat Treatment : Hardness case depth	–do–	10 samples	Each charge	
4.	Assembly :	–do–	5 samples	Each half an hour's production.	
	Overall dimensions (a) Width over inner links (b) Width between outer plates (c) Length of chain (After proof leading)	–do–	5 samples	Each hour's production.	
5.	Breaking Load Test :	–do–	5 samples	All chains assembled with components from same charge for each component.	

1	2	3	4	5*	6
6.	Packing :				
	(a) Appearance	As per standard specification recognized	Each	Each consignment.	
	(b) Drop test	-do-	One No	-do-	
	(c) Rolling test	-do-	-do-	-do-	
	(d) Water spraying test	-do-	One No.	Each design.	

*The package shall be well finished and have a good appearance.

**The package shall be such as to ensure that the inner contents shall withstand Drop test, Rolling test and Water spraying test as given below :

Drop test — (to be restricted to head loads upto 37 kgs. only) the package to be dropped from a height of 150 cm once on the largest flat surface, once on the longest edge and once on an, corner of its own.

Rolling test — (to be restricted to a weight of 500 kgs. only) The package to be subjected to rolling on its sides either six metres forwar and six metres backward or twelve metres in one direction only.

Water spraying test — The package to be exported against a water spray equivalent to a normal accidental shower for one minute.

[No. 6(26)/76 EI & EP]

आदेश

का०ग्रा० 2172.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि बीचडीमर निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन हों;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल), कलकत्ता-700001 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि बीचडीमर निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन हो;

(2) इस आदेश के उपबंध I में दिए गए, बीचडीमर के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारूप के अनुसार, निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो बीचडीमर पर उनके निर्यात से पूर्व लागू होगा;

(3) इस आदेश के उपाबंध II में दिए विनिर्देशों को बीचडीमर के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना; और

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान बीचडीमर के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि ऐसे बीचडीमर का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा करता है और निर्यात-योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, जल या वायु मार्ग द्वारा बीचडीमर के उन नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी जिसका भार चार किलो ग्राम से अधिक नहीं है।

3. इस आदेश में बीचडीमर से होलोथूरिया स्केबरा जाति से तैयार की गई, खाद्य पूर्व पकायी हुई, सुखाई हुई मछली अभिप्रेत है।

उपाबंध–1

(पैरा 1 का उप-पैरा (2) देखें)

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम इन नियमों का नाम बीचडीमर का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977 है।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है:

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है:

(ग) 'बीचडीमर' से होलोथूरिया स्केबरा जाति से तैयार की गई खाद्य पूर्व पकायी हुई, सुखाई हुई मछली अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार—निर्यात की जाने वाली बीचडीमर का निरीक्षण इस दृष्टि से यह सुनिश्चित करने के विचार से किया जाएगा कि क्या बीचडीमर अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया—बीचडीमर के निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता निर्यात किए जाने वाले परेषण का पूर्ण विवरण देते हुए अभिकरण के निकटम कार्यालय को प्रार्थना-पत्र देगा ताकि वह ऐसे परेषणों का परीक्षण कर सके या। यह देखने के लिए कि वह नियम 3 में संदर्भित

विनिर्देशों के अनुरूप है परीक्षण करने के साधन देगा और निर्यात-कर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति निरीक्षण के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक प्रार्थना-पत्र विनिर्माता के परिसर से भेजे जाने के निर्धारित समय से कम से कम सात दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुंचेगी।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर अभिकरण बीचडीमर के परेषण का निरीक्षण, इसके लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार यह देखने के विचार से करेगा कि क्या वह मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(4) निर्यात-कर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा।

(5) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् यदि अभिकरण का समाधान हो जाए कि निर्यात किए जाने वाले बीचडीमर का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो अभिकरण प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के सात दिन के भीतर वह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र दे देगा कि बीचडीमर का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से सम्बन्धित शर्तों को संतुष्ट करता है और निर्यात-योग्य है।

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहां वह उक्त सात दिनों की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके लिए कारणों सहित निर्यात-कर्ता को देगा।

(6) अभिकरण, यदि अनिवार्य पूर्व-पोत लदान योजना का समाधान करने के लिए यह आवश्यक समझता है तो, निरीक्षित परेषण का उसके वास्तविक पोत-लदान से पूर्व भंडारीकरण के किसी स्थान पर, अभिवहन में या जहाज घाट पर ऐसा पर्यवेक्षण करेगा।

6. अपील—(1) नियम (4) के उप-नियम (5) के अधीन अभिकरण के प्रमाण-पत्र देने से इंकार करने पर व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन और अधिकतम सात व्यक्ति विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) पैनल में, विशेषज्ञों के पैनल कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई गैर सरकारी सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील उसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी

उपाबंध–II

सुखाई हुई बीचडीमर के लिए विनिर्देश

होलोथूरिया स्केबरा

[पैरा 1 का उप-पैरा (3) देखिए]

प्रकार	आकार	श्रेणी	रंग	गंध	सामान्य विशेषताएं
बड़ा	4″	6″	पृष्ठीय ओर से काले की ओर गहरा भूरा तथा उदर की ओर से हल्का सफेद।	मसालों की विशिष्ट गंध और किसी भी दुर्गन्ध से मुक्त होगी।	सुखाई हुई बीचडीमर होलोथूरिया स्केबरा मसालों से तैयार की जाएगी। सामग्री भली प्रकार सुखाई जाएगी तथा फफूंदी, कीड़ा तथा अणु बाधा से मुक्त होगी। यह किसी दृष्टिगत दोषों से भी मुक्त होगी। उसमें किनारों पर सफेद बहाव अधिक नहीं होगा। सुखाई हुई बीचडीमर का विशिष्ट आकार होगा।
मध्य	3″	4″			
छोटा	3″ से नीचे				

टिप्पण :—बचे खुचे सहित अगले उच्च तथा निम्न आकार की भार के आधार पर 5 प्रतिशत की सहायता अनुमोदित की जाएगी।

[सं० 6(30)/76–नि० नि० तथा नि० उ०]

के० वी० बालसुब्रह्मणियम, उप निदेशक

ORDER

S.O. 2172.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that Beche-de-mer should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspecion), Rules, 1964 :

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within 45 days of the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council of India, 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta 700001.

PROPOSALS

(1) to notify that Beche-de-mer shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) to specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Beche-de-mer (Inspection) Rules 1976

set out in the Annexure I to this order as the type of inspection which would be applied to such Beche-de-mer prior to export ;

(3) to recognise the specifications as set out in Annexure II to this Order as the standard specifications for Beche-de-mer, and

(4) to prohibit the export in the course of international trade of Beche-de-mer unless the same is accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of such Beche-de-mer satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land sea or air of samples of Beche-de-mer to prospective buyers, provided such samples do not exceed 4 kgs. in nett weight.

3. In this order Beche-de-mer means edible, pre-cooked, dried fish prepared from the species Holothuria scabra.

ANNEXURE I

(See sub-paragraph (2) of paragraph 1)

Draft rules proposed to be made under Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

1. Short title.—These rules may be called the Export of Beche-de-mer (Inspection) Rules, 1977.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) "Agency" means any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under Section 7 of the Act.

(c) 'Beche-de-mer' means edible, pre-cooked, dried fish prepared from the species Holothuria scabra

3. Basis of Inspection.—Inspection of Beche-de-mer for export shall be carried out with a view to seing that Beche-de-mer conforms to the specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Act.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export Beche-de-mer shall submit an application to the nearest office of the Agency giving particulars of the consignment intended to be exported to enable it to examine such consignments or cause the same to be examined to see whether the same conforms to the specifications referred to in rule 3 and the exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation for inspection to the nearest office of the Export Inspection Council.

(2) Every application under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than 7 days before the anticipated time of despatch of the consignment from the exporter's premises.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the agency shall inspect the consignment of Beche-de-mer as per the instructions issued by the Export Inspection Council, in this behalf, from time to time, with a view to seeing that the same conforms with the requirements of the recognised specifications.

(4) The exporter shall provide all necessary facilities to the agency to enable it to carry out such inspection.

(5) If, after inspection, the agency is satisfied that the consignments of Beche-de-mer to be exported complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3, the agency shall, within 7 days of the receipt of the application issue a certificate declaring that the consignment of Beche-de-mer satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is exportworthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of 7 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

(6) The agency may exercise such supervision of the inspected consignment at any place of storage, in transit, or at wharves before its actual shipment as it may consider necessary for satisfying the purposes of the compulsory pre-shipment scheme.

5. Inspection fee.—Subject to a minimum of Rs. 50.00 for each consignment, a fee at the rate of 0.5 per cent of f.o.b. value shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

6. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may within three days of their receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts, consisting of not less than three but not more than seven persons as may be appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE II

SPECIFICATIONS FOR DRIED BECHE-DE-MER

Holothuria scabra

[See Sub-paragraph (3) of paragraph 1]

Type	Size - Grades	Colour	Odour	General Characteristics
Large Medium Small	4" — 6" 3" - 4" Below 3"	Dark Brown to Black on the dorsal side and pale white in the ventral side.	Characteristic odour of the species and shall be free from any off-odour.	Dried Beche-de-mer shall be prepared from the species Holothuria scabra. The material shall be properly dried and free from fungal, insect and mite infestation. It shall be also free from any visible contamination. There should not be too much white discharge at the cut ends. The dreid Beche-de-mer shall have the characteristic shape.

NOTE :—A tolerance of 5% by weight of the next higher or lower size along with brokens shall be permitted.

[No 6(30)/76-EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली 13 जून, 1977

का० आ० 2173.—दुर्ग-भिलाई टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए, जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434(3) (2 सी) में अपेक्षित है दुर्ग-भिलाई में चालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 28 मार्च 1977 को "एम पी क्रोनिकल" "नवभारत" तथा "हितवादा" समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी।

उक्त सूचना के उत्तर में जनसाधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(3)(2सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-7-77 से दुर्ग-भिलाई का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा—

दुर्ग-भिलाई टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था

दुर्ग-भिलाई के स्थानीय क्षेत्र में वह क्षेत्र शामिल है जोकि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई-दुर्ग के क्षेत्राधिकार में पड़ता है और जिसमें इस समय दुर्ग, भिलाई और खुरसीपुर एक्सचेंज शामिल है जैसा कि अधिसूचना संख्या 264/एफ०-11-6 XXX III/74 दिनांक 23-1-74 में घोषित किया गया था और जोकि मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र में दिनांक 15-3-1974 को पृष्ठ 207 पर प्रकाशित की गई थी।

किन्तु वे टेलीफोन प्रयोगकर्ता जो कि ऊपर उल्लिखित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे।

[संख्या 3-3/73-पी०एच०बी०]

प्रा० ना० कौल, निदेशक फोन (ई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 13th June, 1977

S.O. 2173.—Whereas a public notice for revising the local area of Durg Bhilai Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(2c) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Durg Bhilai, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 28th March, 1977 in newspapers 'M.P. Chronicle' 'Nav Bharat' and 'Hitvada';

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 434 (III) (2c) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-7-77 the revised local area of Durg-Bhilai shall be as under :

Durg-Bhilai Telephone Exchange System

The local area of Durg-Bhilai shall cover an area falling under the jurisdiction of Special Area Development Authority Bhilai-Durg presently covering Durg-Bhilai and Khursipur Exchanges as declared vide notification No. 264/F-11-6 XXXIII/74 dated 23-1-74, published in M.P. Gazette dated 15-3-1974 on page No. 207 ;

Provided that the telephone subscribers located outside the area under special Area Development Authority described above shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-3/73-PHB]

P. N. KAUL, Director Phones(F)

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977